वार्षिक रिपोर्ट 1992-93

नीपा

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रो. जी. राम रेड्डी के साथ भागीदारों की अनौपचारिक बातचीत

प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक सत्र

वार्षिक रिपोर्ट

1992-93

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
17-बी, श्री अरविंद मार्ग नई दिल्ली–110016

150 प्रतियां

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, 1994

LIBRARY & DOCUMENTATION
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-9373
Date 5.12.96

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान के लिए कुलसचिव, नीपा द्वारा प्रकाशित तथा शगुन कंपोजर्स, 92-बी, कृष्णा नगर, सफदर जंग इन्कलेव, नई दिल्ली-29 में लेजर टाइप सेट होकर, प्रभात ऑफसेट प्रेस, कूचा चेलान, दरिया गंज, दिल्ली-2 में मुद्रित

विषय सूची

अध्याय

1.	सिंहावलोकन	1
2.	प्रशिक्षण	7
3.	अनुसंधान और प्रकाशन	21
4.	व्यावसायिक सहयोग और परामर्शकारी सेवा	44
5.	पुस्तकालय, प्रलेखन और अकादमिक समर्थनकारी प्रणाली	48
6.	संगठन, प्रशासन और वित्त	51

अनुबंध

I.	प्रशिक्षण कार्यक्रम/संगोष्ठी/कार्यशिविर/सम्मेलन	55
II.	प्रशिक्षण सामग्रियों की सूची	64
III.	संकाय का अकादमिक योगदान	66

परिशिष्ट

I.	नीपा परिषद के सदस्य	85
II.	कार्यकारी समिति के सदस्य	88
III.	वित्त समिति के सदस्य	91
IV.	योजना और कार्यक्रम समिति के सदस्यों की सूची	92
V.	संकाय और प्रशासनिक स्टाफ़	97
VI.	वार्षिक लेखा और लेखा परीक्षा रिपोर्ट	101

उद्देश्य

- शैक्षिक योजना और प्रशासन में उत्कृष्टता का ऐसा राष्ट्रीय केंद्र बनना जो योजना और प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार लाए और इसके लिए अध्ययन, नए विचारों और तकनीकों के सृजन का रास्ता अपनाए तथा रणनीतिक समूहों के साथ अंतःक्रिया और प्रशिक्षण के माध्यम से इनका प्रचार-प्रसार करे;

- केंद्र, राज्यों और संघीय क्षेत्रों की सरकारों के वरिष्ठ शिक्षाधिकारियों तथा शैक्षिक योजना और प्रशासन से जुड़े विश्वविद्यालयी और महाविद्यालयी प्रशासकों के लिए अभिविन्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, गोष्ठियों, संगोष्ठियों तथा परिचय-सत्रों का आयोजन करना;

- शैक्षिक योजना और प्रशासन के विभिन्न पक्षों पर शोधकार्यों को सहायता और प्रोत्साहन देना और उनका समन्वय करना। इनमें भारत के विभिन्न राज्यों और दुनिया के अन्य देशों में प्रयुक्त योजना तकनीकों और प्रशासनिक कार्यप्रणालियों के तुलनात्मक अध्ययन भी शामिल हैं;

- राज्य सरकारों और शिक्षासंस्थाओं के अनुरोध पर सलाहकारी सेवाएं प्रदान करना;

- शैक्षिक योजना और प्रशासन संबंधी अनुसंधान, प्रशिक्षण और विस्तार से संबंधित विचारों और सूचनाओं के लिए काम करना;

- इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आलेखों, पत्रिकाओं और पुस्तकों की तैयारी, मुद्रण और प्रकाशन; विशेष रूप से शैक्षिक योजना और प्रशासन पर एक पत्रिका का प्रकाशन करना;

- अन्य देशों और खासकर एशियाई देशों के अनुरोध पर उनको शैक्षिक योजना और प्रशासन संबंधी प्रशिक्षण और अनुसंधान की सुविधाएं प्रदान करना तथा ऐसे कार्यक्रमों में उनका सहयोग करना।

1992–93

अध्याय 1

सिहांवलोकन

एक शीर्षस्थ संस्था के रूप में पिछले तीन दशकों से राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान शैक्षिक योजना और प्रबंध के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भारत और यूनेस्को के बीच एक करार के आधार पर दस साल के लिए यूरेस्को क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र के रूप में 1962 में इस संस्थान की स्थापना की गई थी। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के शैक्षिक योजनाकारों, प्रशासकों और पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण के लिए इसकी स्थापना की गई थी। 1 अप्रैल, 1965 को इस केंद्र का नाम बदलकर एशियाई शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान रख दिया गया। यूनेस्को के साथ हुए करार की अवधि की समाप्ति के बाद कोठारी ओयाग की सिफारिश पर भारत सरकार ने 1970 में यूनेस्को केंद्र का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया और स्वायत्त संस्था के रूप में शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों के राष्ट्रीय स्टाफ कालेज की स्थापना की। इसका उद्देश्य शैक्षिक योजना और प्रशासन की राष्ट्रीय जरूरतों की पूर्ति करना था और साथ ही इस क्षेत्र में दूसरे देशों के अनुभवों और विशेषज्ञता का आदान-प्रदान करना था। 1979 में संस्थान का नाम बदलकर राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान रखा गया।

अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए संस्थान ने अकादमिक कार्यक्रमों को निम्नाकिंत चार विषयगत एककों में बांटा है: (i) योजना, (ii) प्रशासन, (iii) वित्त और (iv) नीति। शैक्षिक स्तर पर दो मुख्य एककें – (1) विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा और (ii) उच्च शिक्षा; और क्षेत्र स्तर पर दो एककें –(1) प्रादेशिक प्रणाली एकक और अंतर्राष्ट्रीय एकक हैं। इसके अतिरिक्त पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र, प्रकाशन एकक, हिंदी कक्ष, इलैक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, रिपरोग्राफी और मानचित्रण कक्ष व सामान्य प्रशासन और वित्त अनुभाग. अकादमिक कार्यों में सहायता करते हैं। प्रस्तुत रिपोर्ट वर्ष 1992-93 में संस्थान की प्रमुख गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत करती है।

संस्थान के अकादमिक कार्य की निम्नलिखित तीन मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है : (i) क्षमता निर्माण-प्रशिक्षण; (ii) प्रयोग-अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान तथा (iii) ज्ञान का प्रसाार—परामर्शकारी, व्यावसायिक समर्थन और प्रकाशन।

प्रशिक्षण

कार्यक्रम का बलः– प्रशिक्षण के क्षेत्र में शैक्षिक योजना और प्रशासन में प्रशिक्षण सुविधाओं के नेटवर्क पर बल दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी ध्यान दिया गया जिससे उनके अंदर क्षेत्रीय, राज्य, स्थानीय और सांस्थानिक स्तर की प्रशिक्षण क्षमताओं का विकास हो सके।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सबके लिए शिक्षा, व्यष्टि स्तरीय योजना, जिला स्तरीय योजना, सांस्थानिक योजना और मूल्यांकन, अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की योजना और प्रबंध, आदिवासी शिक्षा, विकेंद्रीकृत प्रशासन, लिंगीय मुद्दे, पर्यावरण शिक्षा, संगणक प्रयोग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की विशेष महत्व दिया गया। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित क्षेत्रों की योजना और विकास पर भी विशेष बल दिया गया : (i) अकादमिक स्टाफ कालेज; (ii) स्वायत्त कालेज और (iii) उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता और संबद्धता के लिए योजना।

विस्तारः–वर्ष में संस्थान ने 48 कार्यक्रमों का संचालन किया जिनमें 721 कार्यक्रम दिवस शामिल थे। इन कार्यक्रमों ने भारत के विभिन्न भागों और विश्व के 22 देशों के 1,155 भागीदारों को अवसर प्रदान किए।

प्रशिक्षण सामग्रीः–क्षेत्रीय, राज्यीय और राष्ट्रीय स्तर पर क्षमता के विकास के लिए संस्थान ने 25 स्वयं अधिगम माड्यूल, आलेख, योजना और प्रशासन पर सांख्यिकी आंकड़ा रिपोर्ट तैयार किए। संस्थान के संकाय के सदस्यों ने विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करके प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए विशेष पाठ्य सामग्री के सेट तैयार किए। पाठ्य सामग्रियां भागीदारों में वितरित की गईं।

प्रशिक्षण प्रणालीः-सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतरशास्त्रीय हैं। कार्यक्रमों में प्रायोगिक और सामूहिक कार्य, केस अध्ययन व संगोष्ठियां शामिल हैं। प्रस्तुतियों को ज्ञानवर्धक बनाने के लिए कंप्यूटर फिल्में, विडियो और प्रोजैक्टर जैसी प्रशिक्षण सहायता सामग्री का भी इस्तेमाल किया जाता है। आवश्यकता अनुसार भागीदारों को क्षेत्रीय दौरे पर भी ले जाया जाता है।

मूल्यांकनः- प्रत्येक प्रशिक्षण में मूल्यांकन का तत्व अंतर्निहित होता है। शैक्षिक योजना और प्रशासन में छह महीने का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा वाले लंबी अवधि के कार्यक्रमों का मूल्यांकन लगातार होता रहता है। पाठ्यचर्या कार्य के अतिरिक्त इन कार्यक्रमों के भागीदारों को डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में शोध कार्य भी करना पड़ता है।

अनुसंधान

अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान संस्थान की महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है। किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले उस कार्यक्रम का आरंभिक या गहन अध्ययन किया जाता है। उन मुद्दों पर प्रायः क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है जिनकी चर्चा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में की जाती है। शिक्षा में योजना, प्रशासन और नीति जैसे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान गतिविधियां चलाई जाती हैं। संस्थान शैक्षिक योजना और प्रशासन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान करने की इच्छा रखने वाले विद्वानों को अनुसंधान परियोजनाओं में सहायता प्रदान करके अनुसंधान को बढ़ावा देता है।

वर्ष में, 7 अनुसंधान परियोजनाओं के कार्य पूरे किए गए। 16 अनुसंधान परियोजनाएं जारी हैं। समाप्त हुई परियोजनाओं में, पांच परियोजनाएं शिक्षा व्यवस्था के कार्यप्रणाली पर केंद्रित थीं। इनमें से प्रत्येक समता और गुणवत्ता के मुद्दों पर केंद्रित थीं। एक अध्ययन अनुसंधान तकनीक पर किया गया। अन्य दो अध्ययन महिला महाविद्यालयों के प्राचार्यों के लिए प्रशिक्षण की जरूरतों की पता लगाने और व्यावसायिक रूप से शिक्षित लोगों की मांग का निर्धारण करने के लिए किए गए। जारी अध्ययन, समता, विद्यालय और उच्च शिक्षा, योजना और वित्त मामलों से संबंधित हैं।

परामर्श और व्यावसायिक सहयोग

संस्थान के संकाय सदस्यों ने राष्ट्रीय, राज्यीय और सांस्थानिक स्तर के संगठनों व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को परामर्शकारी और व्यावसायिक सेवाएं प्रदान कीं। इस संस्थान ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राज्य शिक्षा विभाग, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद और अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों, जैसे– यूनेस्को, विश्वबैंक और एस.आई.डी.ए. को परामर्शकारी और व्यावसायिक सेवाएं प्रदान की हैं।

सूचनाओं का प्रसार

प्रकाशन : संस्थान अनुसंधान अध्ययनों और शैक्षिक योजना एवं प्रशासन पर जर्नल प्रकाशित करता रहा है। वर्ष में नीपा ने तीन पुस्तकों और जर्नल के नौ अंकों का प्रकाशन किया। इसके अतिरिक्त संस्थान ने कई मिमियोंग्राफ और अनुसंधान आलेख भी प्रकाशित किए।

1992–93

नीपा विचार मंचः– नीपा विचार मंच शिक्षा के क्षेत्र में चर्चा और विचारों के आदान-प्रदान के लिए व्यावसायिक मंच प्रदान करता है। समीक्षाधीन वर्ष में दो विषयों पर व्याख्यान आयोजित किए गए थे। डॉ. जार्ज सकारोपाउलस, विश्वबैंक के विख्यात अर्थशास्त्री ने "आज शैक्षिक योजना के लिए कोई जगह है?" पर व्याख्यान दिया। लॉ आइलैंड यूनीवर्सीटी, साउथैपटन, अमेरीका के डॉ. एम. आर. अचुतन ने "उत्तर प्रदेश में ग्राम विकास–शिक्षक के रूप में अभिभावक : पिछड़े समुदाय का वित्तचित्र" विषय पर व्याख्यान दिया।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोगः- विश्वबैंक, यूनेस्को, एशियाई विकास बैंक, ब्रिटिश कौंसिल और नार्थ लंदन विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों ने संकाय के सदस्यों और संयुक्त निदेशक के साथ सूचनाओं और विचारों का आदान-प्रदान किया।

अकादमिक और समर्थनकारी एककें

संस्थान का अकादमिक कार्यक्रम आठ अकादमिक एककों द्वारा चलाया जाता है। इन अकादमिक और समर्थनकारी एककों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है।

अकादमिक एककें

शैक्षिक योजना एककः– वर्तमान में केंद्रीकृत योजना में विकेंद्रीकृत योजना पर अधिक बल दिया जा रहा है। योजना एकक में अनुसंधान प्रशिक्षण और परामर्शकारी सेवा के क्षेत्रों में परिवर्तन किया गया है। वर्तमान में संस्थान, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर योजना के आगतों, प्रक्रियाओं और उत्पादों के समन्वयन पर प्रमुख बल है। अर्थव्यवस्था में उदारीकरण की नीति की मद्देनज़र रखते हुए सुविधा की दृष्टि से विस्तृत योजना की बजाए रणनीतिक और सांकेतिक कार्यान्वयन की ओर ध्यान दिया गया है। शिक्षा का सार्वजनीकरण के अलावा योजना के सिद्धांत और व्यवहार के क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा कवच के रूप में एक नई प्रणाली विकसित हुई है। इस एकक में शैक्षिक योजना के क्षेत्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और संबंधित क्षेत्र में परामर्शकारी सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

शैक्षिक प्रशासन एककः- शैक्षिक प्रशासन एकक विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अनुसंधान और अन्य गतिविधियों द्वारा शैक्षिक प्रशासकों का सांस्थानिक और अधिसांस्थानिक स्तर पर क्षमताओं का विकास करने का प्रयत्न करता है। इस समय देश में 80,000 से भी अधिक विद्यालय हैं। इसलिए प्रशासन एकक इस बात का प्रयास करता है कि नेटवर्क द्वारा अधिक से अधिक विद्यालय प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त हो सके। यह एकक रेलवे विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों केंद्रीय विद्यालयों, आश्रम विद्यालयों जैसे विशेष वर्गों के संस्थानों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखता हैं। शैक्षिक प्रशासन प्रणाली में नवीनता लाने के लिए यह एकक शैक्षिक प्रशासकों के अंदर अपेक्षित प्रबंधकीय कौशल विकसित करने का प्रयत्न करता है जिससे कि वे शैक्षिक विकास के रास्ते में आने वाली बाधाओं और चुनौतियों का सामना कर सकें।

शैक्षिक वित्त एककः– नई आर्थिक शर्तों के कारण शैक्षिक बजटों पर भारी दबाव पड़ा है। शिक्षा व्यवस्था में संसाधनों की आवश्यकता बढ़ती जा रही है जबकि संसाधनों की उपलब्धता सीमित है। इस प्रकार दोनों में अंतर बढ़ता जा रहा है। संसाधनों के आबंटन, सरकारी और गैर सरकारी संसाधनों की लामबंदी व संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए प्रभावी तरीके तलाशने की आवश्यकता है। इसलिए शैक्षिक वित्त के प्रभावी प्रबंध की आवश्यकता बहुत बढ़ गई है।

यह एकक तदनुसार अनुसंधान, परामर्श और प्रशिक्षण और राज्य शिक्षा विभागों और विश्वविद्यालयों के वित्त अधिकारियों की क्षमताओं को दृढ़ बनाने के लिए उन्हें नवीनतम विकास और तथ्यों से परिचित कराता है और वित्तिय प्रबंधों (संसाधनों की उपयोगिता, गतिशीलता और आबंटन) से अवगत कराता है।

शैक्षिक नीति एकक: शैक्षिक नीति के प्रतिपादन और कार्यान्वयन के साथ-साथ नीति मूल्यांकन से संबंधित कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर यह एकक विशेष बल देता है। यह अनुसंधान कार्य चलाता है और शैक्षिक नीति के महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस को बढ़ावा देता है। एकक राष्ट्रीय नीति के बेहतर क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण/ अभिविन्यास कार्यक्रमों का आयोजन करता है। यह एकक शिक्षा में समता और मांग की उत्पत्ति जैसे मुद्दों पर अधिक बल देता है।

समीक्षाधीन वर्ष में एकक की गतिविधियां दूरवर्ती पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा की योजना और प्रबंध, अल्पसंख्यकों का शैक्षिक विकास, विकेंद्रीकृत योजना और समुदाय की भागीदारी पर केंद्रित रहीं। एकक ने संशोधित नीति और कार्ययोजना, 1992 से जुड़े कुछ मुद्दों की तैयारी में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा एकक: जिला शिक्षा अधिकारियों, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों व विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा की योजना और प्रशासन के क्षेत्र में कार्य कर रहे संबंधित अधिकारियों में दक्षता का विकास करना एकक के कार्यों का केंद्र बिंदु है। यह एकक विद्यालय प्रबंध और अनौपचारिक शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों और समस्याओं को उठाता है और उनका हल निकालने के लिए वैकल्पिक रणनीतियां तैयार करता है। एकक ने महत्वपूर्ण अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा व्यावसायिक क्षमता/दक्षता में सुधार लाने का प्रयत्न करता है। यह एकक अनुसंधान परियोजनाओं द्वारा विद्यालय प्रणाली की प्रभावी योजना और प्रबंध के क्षेत्र में प्रमुख अधिकारियों के ज्ञान में वृद्धि करने का प्रयत्न करता है। एकक विद्यालय शिक्षा के प्राथमिक क्षेत्रों और योजनाओं पर बल देता है। यह एकक स्वयं अनुसंधान कार्यों का संचालन करता है और गुणवत्ता सुधार के लिए विद्यालय शिक्षा की योजना और प्रबंध के क्षेत्र में परामर्शकारी सेवा प्रदान करता है।

उच्च शिक्षा एकक:– इस एकक में मुख्यतः समता की संकल्पना का विकास, उत्कृष्टता संबद्धता, स्वायत्तता, उत्तरदायित्व, प्रशिक्षण द्वारा स्टाफ का विकास, अनुसंधान, उच्च शिक्षा में योजना और प्रबंध के लिए परामर्श जैसे मुद्दों पर विशेष बल दिया गया है। उच्च शिक्षा एकक ने 'प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण' कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा योजना और प्रबंध में क्षमता के निर्माण के लिए प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त कालेजों के प्राचार्यों, अकादमिक स्टाफ महाविद्यालयों के निदेशकों, स्वायत्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों, महाविद्यालय विकास परिषद के निदेशकों और उच्च शिक्षा निदेशकों की क्षमता में विकास के लिए भी प्रयास किए गए है। समीक्षाधीन वर्ष में एकक ने सामान्य महाविद्यालयों के प्राचार्यों, महिला और ग्रामीण क्षेत्रों के महाविद्यालयों के प्राचार्यों, स्वायत्त महाविद्यालयों, अकादमिक स्टाफ कालेजों के निदेशकों तथा शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों के महाविद्यालयों के प्राचार्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।

अनुसंधान के क्षेत्र में एकक ने मुख्य रूप से स्वायत्त महाविद्यालयों, महिला महाविद्यालयों के प्राचार्यों के प्रशिक्षण की जरूरतों को पता लगाने, पिछड़े क्षेत्रों के महाविद्यालयों के विकास की योजना, भारत में चुने हुए विश्वविद्यालयों के विकास कीं रूपरेखा पर बल दिया है। एकक ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राज्य उच्च शिक्षा परिषदों, भारत में विश्व विद्यालयों और महाविद्यालयों को परामर्शकारी सेवाएं प्रदान कीं।

प्रादेशिक प्रणाली एकक: एकक ने मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यक्रमों पर बल दिया है : सबके लिए शिक्षा के संदर्भ में विकेंद्रीकृत और व्यष्टि स्तरीय योजना, सांस्थानिक योजना और मूल्यांकन, शैक्षिक कार्यक्रमों का अनुवीक्षण और मूल्यांकन और प्रादेशिक स्तर पर शिक्षा के संकेतकों का विकास। एकक द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर किए गए अध्ययन हैं– प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनीकरण के संचारेक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, शैक्षिक प्रशासन में द्वितीय अखिल भारतीय सर्वेक्षण

और विद्यालय मानचित्रण। एकक ने 'भारत में अनौपचारिक शिक्षा–मूल्यांकन' पर एक विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार की। यह रिपोर्ट अनौपचारिक शिक्षा पर केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं के संदर्भ में शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ जिलों के मूल्यांकन अनुसंधान पर आधारित थी। यह एकक राज्य सरकारों के सहयोग से जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में क्षेत्र आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी करता है।

अंतर्राष्ट्रीय एककः– अंतर्राष्ट्रीय एकक मानव संसाधन विकास के क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों और मुद्दों पर संगोष्ठियां और बैठकों के आयोजन द्वारा विकासशील देशों के बीच विचारों के आदान-प्रदान और आपसी सहयोग और समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करता है। शैक्षिक योजना और प्रशासकों के लिए लंबी अवधि का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना एकक के प्रमुख कार्यों में से एक है। इस कार्यक्रम में एक तरफ शिक्षा की संरचनाओं और प्रक्रियाओं–व्यष्टि, मध्य और समष्टि योजना प्रक्रिया तो दूसरी तरफ शैक्षिक पर्यवेक्षण, प्रशासन, प्रबंध और नेतृत्वकारी भूमिका के देशीकरण पर बल दिया जाता है। विभिन्न देशों के अनुरोध पर यह एकक विशेष प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करता है। समीक्षाधीन वर्ष में यूनिसेफ के तत्वाधान में इस एकक ने चीनी शैक्षिक अधिकारियों के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। यह एकक तुलनात्मक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान करता है और परामर्शकारी सेवा प्रदान करता है।

अकादमिक समर्थनकारी एककें

पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्रः– संस्थान के पुस्तकालय में शैक्षिक योजना और प्रबंध से संबद्ध क्षेत्रों की नवीनतम सामग्रियों का संग्रह किया जाता है और उनके उपयोग के लिए सुविधाएं भी दी जाती हैं। प्रलेखन और सूचना सेवा द्वारा सूचनाओं का प्रसार किया जाता हैं। पुस्तकालय में 45,000 से अधिक पुस्तकें उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 350 पत्रिकाएं भी मंगाई जाती हैं। पुस्तकालय में पुस्तकों और आलेखों की संगणक द्वारा अनुक्रमणिका तैयार की गई हैं। पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र ने जि.शि.प्र.सं. के पुस्तकालयों की योजना और प्रबंध पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

प्रकाशन एककः– अनुसंधान उपलब्धियों के प्रचार-प्रसार का उतना ही महत्व है जितना कि अनुसंधान कार्य करने का। प्रमुख आलेखों और सामयिक लेखों के रूप में शैक्षिक शोधों से संबंधित सामग्री का प्रकाशन किया जाता है। सूचनाओं के प्रसार का दूसरा तरीका मोनोग्राफ और मिमियोग्राफ है। यह एकक प्रमुख और सामायिक आलेखों, शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में हिंदी और अंग्रेज़ी में जर्नल, पुस्तकों और अनुसंधान रिपोर्टों का प्रकाशन भी करता है।

हिंदी कक्षः– हिंदी भाषा के विकास की राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत संस्थान ने एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन जर्नल के चार अंकों का हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया। इसके अतिरिक्त हिंदी कक्ष प्रशिक्षण सामग्रियों का हिंदी में अनुवाद करने में भी मदद करता है। यह राजभाषा नीति के क्रियान्वयन में प्रशासन और संकाय की मदद करता है।

मानचित्रण कक्षः– मानचित्रण कक्ष आंकड़ों के सचित्र प्रस्तुतीकरण, मानचित्रों, प्रशिक्षण के चार्टों, प्रकाशन और प्रदर्शन में अपनी सेवाएं प्रदान करता है।

रिप्रोग्राफ़ी कक्षः– यह कक्ष संस्थान की अकादमिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण सामग्रियों, अनुसंधान आलेखों और मिमियोग्राफ़ों की प्रतियां तैयार करने में सहायता प्रदान करता है।

प्रशासन और वित्त

प्रशासनः– प्रशासनिक ढांचे में सामान्य, अकादमिक और कार्मिक प्रशासन शामिल हैं। 31 मार्च 1993 को संस्थान के स्टाफ़ की सदस्य संख्या 180 थी। इसमें अकादमिक और

अन्य कार्मिक सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा संबंधित परियोजनाओं की निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त परियोजना स्टाफ के 47 सदस्य भी थे।

वित्तः– इस वर्ष संस्थान को 166.00 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ। (इसमें गैर योजना अनुदान के 93.00 लाख और योजना अनुदान के 73.00 लाख रुपये शामिल हैं।) वर्ष के आरंभ में संस्थान के पास 25.00 लाख (गैर योजना 8.50 लाख और योजना 16.50 लाख रुपए) रुपये की रकम जमा थी। वर्ष में कार्यालय और छात्रवास से प्राप्त राशि 22.70 लाख रुपये थी।

संस्थान के पास 54.59 लाख रुपये की रकम बकाया थी और वर्ष के दौरान अन्य संगठनों द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों/ अध्ययनों के लिए 23.59 लाख रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्राप्त हुई।

परिसर सुविधाएंः– संस्थान के पास चार मंजिला कार्यालय भवन है, पूरी तरह सुसज्जित और स्नानघरों से युक्त 48 कमरों वाला एक सात मंजिला छात्रावास है। एक आवासीय परिसर है जिसमें टाइप-I के 16 क्वार्टर, टाइप-II से टाइप-V के 8-8 क्वार्टर तथा एक निदेशक निवास है। छात्रावास भवन के विस्तार और उन्नयन का काम इस समय पूरी तेजी से जारी है और शीघ्र ही उसके पूरी होने की आशा है। इसमें वार्डेन का निवास, संकाय के लिए अतिथि आवास की सुविधा और अतिरिक्त ब्लाक, भोजन कक्ष का विस्तार और मनोरंजन कक्ष शामिल हैं।

अध्याय 2

प्रशिक्षण

सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और साथ ही विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के उन प्रशिक्षकों के लिए जो शैक्षिक योजना और प्रशासन के कार्यों में लगे हुए है, अभिविन्यास और प्रशिक्षण के कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और ऐसे अन्य मिलते-जुलते कार्यक्रमों का आयोजन करना संस्थान के प्रमुख कार्यों में एक है। संस्थान दूसरे देशों के प्रमुख शिक्षाकर्मियों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

दृष्टिकोण और बल के क्षेत्र

संबद्ध क्षेत्र में ही रहे नए विकासक्रमों से प्रशिक्षण संबंधी जो आवश्यकताएं पैदा होती हैं उन्हीं की ध्यान में रखकर इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाती है। कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करते समय उन प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं पर भी ध्यान दिया जाता है जिनकी पहचान भागीदार और निर्णयकर्ता करते हैं। कार्यक्रमों के आयोजन के समय पिछले अवसरों पर भागीदारों द्वारा किए गए सुझावों का भी ध्यान रखा जाता है। कार्यक्रमों के ब्यौरे की विवेचना के लिए कार्यबल गठित किए जाते हैं।

इसके अलावा संस्थान के प्रशिक्षण संबधी कार्यक्रमों की योजना बनाते समय प्राथमिकता के क्षेत्रों को भी ध्यान में रखा जाता है, जैसे—जिलास्तरीय योजना, पिछड़े क्षेत्रों की संस्थाओं और अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित संस्थाओं की योजना और उनका प्रबंध, शैक्षिक योजना और प्रबंध में संगणकों की भूमिका आदि।

यूनेस्को और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से विकासशील देशों की शिक्षाकर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन करके संस्थान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी केंद्रीय भूमिका निभाता रहा है। संस्थान ने यूनिसेफ के सहयोग से वर्ष 92-93 में चीन के शिक्षा आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया है।

नीपा अब अपनी प्रशिक्षण संबंधी प्राथमिकताओं में धीरे-धीरे परिवर्तन कर रहा है। अब वह प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण पर तथा राज्य और क्षेत्र स्तर की संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभागों के साथ संबंध स्थापित करने पर ध्यान दे रहा है।

प्रशिक्षण सामग्री

नीपा का संकाय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अनुसंधान-आधारित प्रशिक्षण सामग्री की तैयारी में सक्रिय रूप से संलग्न रहा है। यह प्रशिक्षण सामग्री कार्यक्रम के दौरान भागीदारों को देने के लिए पृष्ठभूमि आलेख का काम कर रही है। इस सामग्री के साथ संबंधित विषय पर प्रकाशित साहित्य भी दिया जाता है।

नीपा के संकाय ने चीन के शैक्षिक योजनाकर्मियों और प्रशासकों के लिए यूनिसेफ द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के वास्ते भी विशेष प्रशिक्षण सामग्री तैयार की थी। कुल मिलकर 28 आलेख तैयार किए गए। इनमें विवेचित विषयों में योजना और विकास की धारणाओं और विषयों से लेकर प्रबंध, निगरानी और मूल्यांकन तक, आंकड़ों के संकलन की तकनीकों और पद्धतियों से लेकर योजना और शैक्षिक प्रबंध

सूचना प्रणाली तक, विकेंद्रीकरण से लेकर अंतर्राष्ट्रीय योजना और विकास के अनुभव तक शामिल रहे हैं। बड़ी संख्या में स्वाधिगम के माड्यूल तैयार किए गए जिनको विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त ढंग से अनुकूलित किया जा सकता है। तैयार की गई प्रशिक्षण सामग्रियों की पूरी सूची अनुबंध II में दी गई है।

मूल्यांकन

प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम का औपचारिक मूल्यांकन किया जाता है। इसका पहला चरण प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में आता है जब प्रत्येक भागीदार से एक संरचनाबद्ध प्रपत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल्यांकन करने को कहा जाता है। लंबी अवधि के कार्यक्रमों में इस मूल्यांकन से पहले एक-दो मध्यावर्ती मूल्यांकन भी किए जाते हैं।

भागीदारी

राष्ट्रीय

समीक्षाधीन वर्ष में संस्थान ने विभिन्न अवधियों के 48 प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं या संगोष्ठियों का आयोजन किया। इनमें कुल 1155 व्यक्तियों में भाग लिया। इनमें 991 व्यक्ति विभिन्न राज्य सरकारों या संघीय क्षेत्रों से और 123 भारत सरकार के संगठनों और विभागों से संबद्ध थे। कार्यक्रमों की सूची, उनकी अवधियां और प्रत्येक कार्यक्रम में भागीदारों की संख्या को अनुबंध-I में दिखाया गया है।

नीपा द्वारा आयोजित कार्यक्रम चार श्रेणियों में आते हैं : (अ) डिप्लोमा कार्यक्रम (राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय); (ब) शैक्षिक योजना और प्रबंध में सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रम; (स) विशेष विषय पर आधारित अल्पकालिक प्रशिक्षण या अभिविन्यास कार्यक्रम; और (द) विशिष्ट विषयों पर आधारित कार्यशालाएं, संगोष्ठियां या सम्मेलन।

समीक्षाधीन वर्ष में संस्थान ने राष्ट्र और राज्य स्तरों के कार्मिकों के लिए दो डिप्लोमा कार्यक्रमों और 26 कार्यक्रमों का आयोजन किया। कार्यक्रम दिवसों की कुल संख्या 653 और भागीदारों की कुल संख्या 667 थी। विशिष्ट क्षेत्रों में आठ कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 41 कार्यक्रम दिवस लगे और 132 भागीदारों ने भाग लिया। वे कार्यक्रम लिंगीय प्रश्न, अनुसंधान की पद्धति, संसाधनों के प्रयोग, जनांकीय दबावों, शैक्षिक प्रबंध सूचना प्रणाली तथा महाविद्यालयों में स्वायत्तता और जवाबदेही की योजना पर केंद्रित थे। अंतिम श्रेणी में कुल 11 कार्यशालाओं या गोष्ठियों का आयोजन किया गया जिनमें 53 भागीदारों ने भाग लिया और 356 कार्यक्रम दिवस लगे। इन कार्यक्रमों के ब्यौरे तालिका 1 में दिए गए हैं।

तालिका 1

श्रेणियों के अनुसार कार्यक्रमों का आयोजन : 1992-93

क्रम संख्या	कार्यक्रमों का वर्गीकरण	कार्यक्रमों की संख्या	अवधि (दिन)	भागीदारों की संख्या
(अ)	**डिप्लोमा कार्यक्रम**			
1.	राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम	2	194	39
2.	अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम	2	183	19

1992–93

क्रम संख्या	कार्यक्रमों का वर्गीकरण	कार्यक्रमों की संख्या	अवधि (दिन)	भागीदारों की संख्या
(ब) सामान्य कार्यक्रम				
1.	विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	4	48	91
2.	जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	3	48	73
3.	महाविद्यालयों के प्राचार्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	5	49	152
4.	शैक्षिक प्रशासकों/क्षेत्र अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	12	75	286
5.	चीनी शैक्षिक प्रशासकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (यूनिसेफ द्वारा प्रायोजित)	1	31	7
	योग	29	628	667
(स) विषय-आधारित कार्यक्रम				
1.	शिक्षा में लिंग संबंधी संवेदनशीलता	1	5	15
2.	शोध की पद्धति	2	9	25
3.	विद्यालयों में संसाधनों का उपयोग	1	5	25
4.	शिक्षा पर जनांकीय दबाव	1	5	3
5.	कोप का क्रियान्वयन	1	2	4
6.	प्रबंध सूचना प्रणाली में संगणकों का व्यवहार	1	12	10

क्रम संख्या	कार्यक्रमों का वर्गीकरण	कार्यक्रमों की संख्या	अवधि (दिन)	भागीदारों की संख्य
7.	स्वायत्तता और जवाबदेही के लिए योजना	1	2	50
	योग	8	40	132
(द)	**कार्यशालाएं/संगोष्ठियां/सम्मेलन**			
1.	प्रधानाचार्य के लिए शिक्षा संबंधी उत्कृष्टता	1	12	37
2.	प्रतिदर्शी सर्वेक्षण की तकनीकें	1	3	24
3.	क्षेत्रीय योजना	1	4	34
4.	ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा	1	4	33
5.	नई आर्थिक नीतियां, भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण और शिक्षा के लिए उसके निहितार्थ	2	8	97
6.	शैक्षिक सांख्यिकी	1	2	50
7.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति–1992 का क्रियान्वयन	1	4	7
8.	अकादमिक स्टाफ महाविद्यालय कार्यक्रम के क्रियान्वयन की योजनाएं	1	1	38
9.	दूरवर्ती शिक्षा की योजना और प्रबंध	1	3	19
10.	साक्षरता और अनुवर्ती शिक्षा के प्रबंधकर्मी	1	12	17
	योग	11	53	356
	महायोग	48	721	1155

तालिका 2 और 4 राज्यवार, क्षेत्रवार और स्तरवार भागीदारी को प्रदर्शित करती हैं। इनसे निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट होती हैं :

(अ) देश के (त्रिपुरा और लक्षद्वीप को छोड़कर) सभी राज्यों और संघीय क्षेत्रों ने संस्थान के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया है।

(ब) लगभग 51 प्रतिशत भागीदार शैक्षिक रूप से पिछड़े दस राज्यों के थे। ये राज्य इस प्रकार हैं—आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू-कश्मीर, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

(स) क्षेत्रवार देखें तो सबसे अधिक भागीदार (486) उत्तरी क्षेत्र के राज्यों के रहे। उसके बाद दक्षिणी क्षेत्र (188), पूर्वी क्षेत्र (170) और पश्चिमी क्षेत्र (147) की बारी आती है।

(द) राज्यों और संघीय क्षेत्रों के अलावा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भारत सरकार के तथा योजना आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय आदि अन्य राष्ट्रीय संस्थाओं के 123 अधिकारियों ने भी भाग लिया।

तालिका 2

राज्यवार भागीदारी

क्रम संख्या	राज्य/संघीय क्षेत्र	भागीदार
(अ) राज्य		
1.	आंध्र प्रदेश	78
2.	अरुणाचल प्रदेश	8
3.	असम	10
4.	बिहार	22
5.	गोवा	6
6.	गुजरात	24
7.	हरियाणा	15
8.	हिमाचल प्रदेश	12
9.	जम्मू-कश्मीर	21
10.	कर्नाटक	27
11.	केरल	20
12.	मध्यप्रदेश	45
13.	महाराष्ट्र	65

क्रम संख्या	राज्य/संघीय क्षेत्र	भागीदार
14.	मणिपुर	2
15.	मेघालय	3
16.	मिजोरम	9
17.	नागालैंड	2
18.	उड़ीसा	58
19.	पंजाब	10
20.	राजस्थान	253
21.	सिक्किम	4
22.	तमिलनाडु	58
23.	त्रिपुरा	–
24.	उत्तरप्रदेश	52
25.	पश्चिमी बंगाल	20
(ब) संघीय क्षेत्र		
26.	अंडमान-निकोबार द्वीप समूह	32
27.	चंडीगढ़	6
28.	दादरा-नागर हवेली	5
29.	दमन और दीव	2
30.	दिल्ली	117
31.	लक्षद्वीप	–
32.	पांडिचेरी	5
(स) भारत सरकार और अन्य संगठन		123
योग		1114

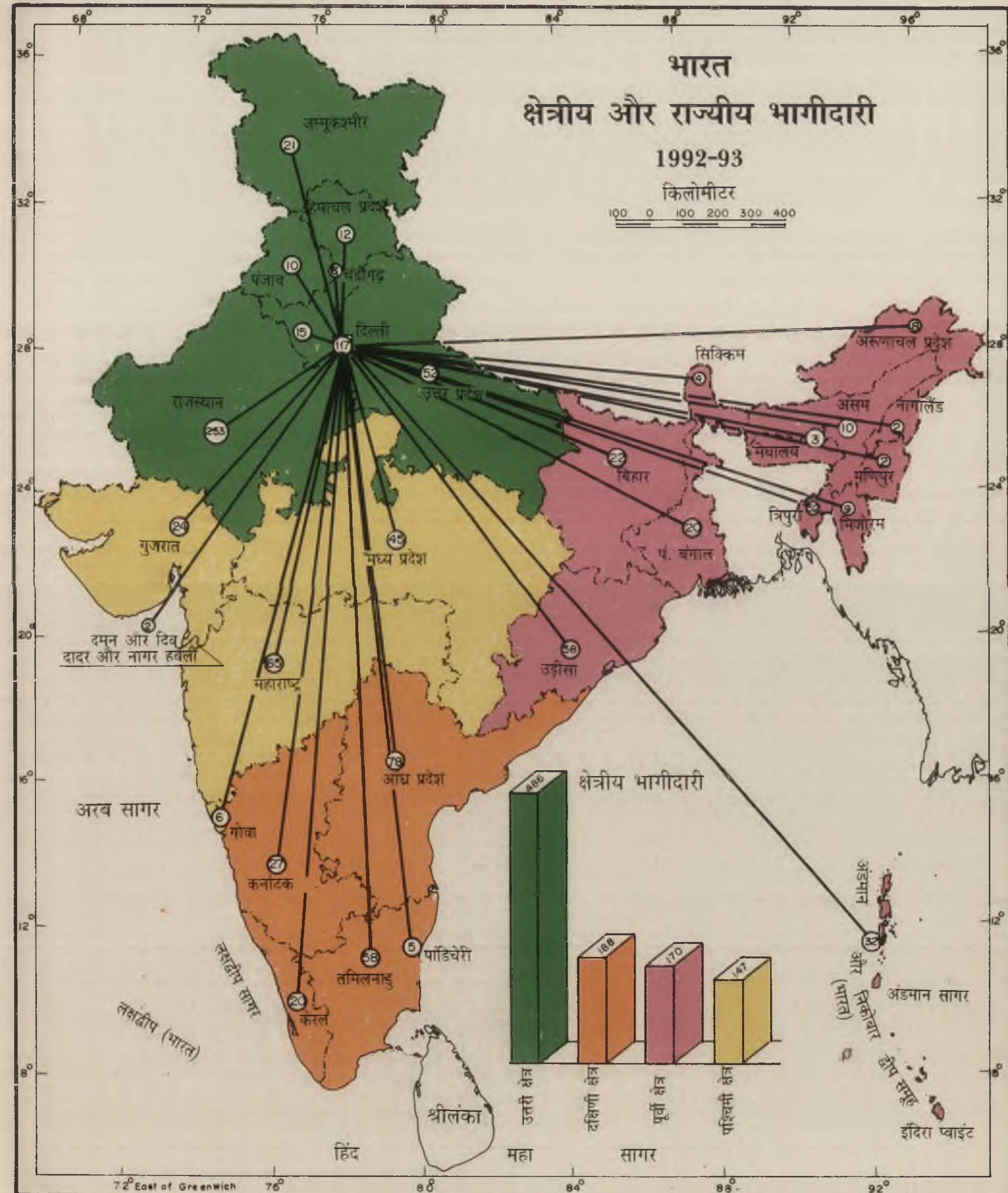

भारत
क्षेत्रीय और राज्यीय भागीदारी
1992-93
किलोमीटर
100 0 100 200 300 400
जम्मूकश्मीर
हिमाचल प्रदेश
पंजाब
चंडीगढ़
दिल्ली
राजस्थान
उत्तर प्रदेश
सिक्किम
अरूणाचल प्रदेश
असम
नागालैंड
मेघालय
मणिपुर
बिहार
त्रिपुरा
मिजोरम
प. बंगाल
गुजरात
मध्य प्रदेश
दमन और दिव
दादर और नागर हवेली
महाराष्ट्र
उड़ीसा
आंध्र प्रदेश
क्षेत्रीय भागीदारी
अरब सागर
गोवा
कर्नाटक
पांडिचेरी
तमिलनाडु
केरल
लक्षद्वीप सागर
लक्षद्वीप (भारत)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (भारत)
अंडमान सागर
इंदिरा प्वाइंट
श्रीलंका
हिंद महा सागर
उत्तरी क्षेत्र
दक्षिणी क्षेत्र
पूर्वी क्षेत्र
पश्चिमी क्षेत्र
486
188
170
147
21
12
10
5
15
17
53
253
4
8
10
2
3
2
22
9
20
24
48
2
63
58
78
6
27
58
5
20
32
72° East of Greenwich

1992–93

अंतर्राष्ट्रीय

भारत के भागीदारों के अलावा 22 देशों के 39 और विश्वबैंक के 2 भागीदारों ने भी संस्थान के कार्यक्रमों में भाग लिया। इनमें आठवें और नवें अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के 19 भागीदार भी शामिल हैं। देशों के अनुसार भागीदारों का विवरण तालिका 3 में दर्शाया गया है।

तालिका 3

प्रशिक्षण कार्यक्रमों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी

क्रम संख्या	देश/संस्था	भागीदार
1.	अफगानिस्तान जनवादी गणराज्य	1
2.	बंगला देश लोक गणराज्य	1
3.	बोत्सवाना	1
4.	चीन लोक गणराज्य	9
5.	घाना गणराज्य	1
6.	इंडोनेशिया गणराज्य	1
7.	ईरान	1
8.	कीनिया गणराज्य	1
9.	मलयेशिया	1
10.	मारीशस	4
11.	नेपाल	1
12.	नाइजीरिया	2
13.	पाकिस्तान	1
14.	फिलीपीन	1
15.	रूवांडा	1
16.	सिंगापुर	1
17.	सेशल्स	1
18.	तंजानिया	1

क्रम संख्या	देश/संस्था	भागीदार
19.	थाइलैंड	1
20.	उगांडा	3
21.	वियतनाम	3
22.	जांबिया	2
	अंतर्राष्ट्रीय संस्था	
23.	विश्व बैंक	2
योग		41

भागीदारी के प्रकार और स्तर

विभिन्न कार्यक्रमों के भागीदार अपने स्तरों की दृष्टि से मिश्रित श्रेणी में आते हैं। इनमें राज्यों के मंत्रिमंडलों, शिक्षा निदेशालयों के वरिष्ठ अधिकारी, क्षेत्रीय और जिला अधिकारी तथा साथ ही विद्यालयों के प्रधानाध्यापक जैसे संस्थाप्रमुख शामिल थे।

इसी प्रकार विश्वविद्यालयों के प्रशासकों ने भी उच्च शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों में भाग लिया। प्रकारों और स्तरों के अनुसार भागीदारों के ब्यौरे तालिका 4 में दिए गए हैं।

तालिका 4

प्रकारों और स्तरों के अनुसार भागीदारी

स्तर	भागीदार
वरिष्ठ शैक्षिक प्रशासक	247
विद्यालयों के प्रधानाध्यापक	154
जिला शिक्षा अधिकारी	44
प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी	35
सांख्यिकी अधिकारी	11
महाविद्यालयों के प्राचार्य	168
विश्वविद्यालयों के प्रशासक (कुलसचिव, वित्त अधिकारी, निदेशक आदि)	273
अन्य	182
योग	1114

अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी 1992-93

1992–93

क्षेत्रों और विषयों के अनुसार कार्यक्रम

संस्थान ने इस वर्ष 37 प्रशिक्षण/अभिविन्यास कार्यक्रमों, 9 कार्यशालाओं और 2 संगोष्ठियों/बैठकों का आयोजन किया। इन्न कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और बैठकों का आयोजन संस्थागत योजना, विद्यालय-मानचित्रण और व्यष्टिस्तरीय योजना, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की योजना और प्रबंध, अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा, स्त्री-शिक्षा की योजना और प्रबंध, आदिवासियों और वंचित समूहों की शिक्षा, जिलास्तरीय शैक्षिक योजना, आर्थिक नीतियां और शिक्षा में संसाधनों का उपयोग, शिक्षा नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा, शैक्षिक योजना और प्रबंध में संगणकों का व्यावहार, उच्च शिक्षा की योजना और प्रबंध, दूरवर्ती शिक्षा की योजना और प्रबंध आदि विषयों पर किया गया। इन कार्यक्रमों का एक संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

1. शैक्षिक योजना और प्रशासन में डिप्लोमा (डेपा)

संस्थान ने जुलाई 1983 में शैक्षिक योजना और प्रशासन में अपने पहले राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यकम का आयोजन किया था। इस वर्ष संस्थान ने बारहवें डिप्लोमा कार्यक्रम के दूसरे और तीसरे चरण की पूरा किया; इस कार्यक्रम का आरंभ नवंबर 1991 में हुआ था। तेरहवें डिप्लोमा कार्यक्रम का तीन माह का पहला चरण फरवरी 1993 में संपन्न हुआ। बारहवें और तेरहवें डिप्लोमा कार्यक्रमों में जिला स्तर के अधिकारियों तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के कार्मिकों ने भाग लिया। डिप्लोमा कार्यक्रम में राज्यवार भागीदारी तालिका 5 में दी गई है।

तालिका 5

राज्यों/संघीय क्षेत्रों के अनुसार डिप्लोमा कार्यक्रमों में भागीदारी

राज्य/संघीय क्षेत्र	भागीदारों की संख्या*
आंध्रप्रदेश	1
असम	2
गुजरात	1
हरियाणा	3
जम्मू-कश्मीर	6
कर्नाटक	3
केरल	4
मध्यप्रदेश	1
महाराष्ट्र	2
मिज़ोरम	1

राज्य/संघीय क्षेत्र	भागीदारों की संख्या*
राजस्थान	2
तमिलनाडु	1
उत्तरप्रदेश	5
पश्चिम बंगाल	2
अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह	1
दादरा-नागर हवेली	2
पांडिचेरी	2
योग	39

*राष्ट्रीय स्तर के बारहवें और तेरहवें डिप्लोमा कार्यक्रम

पिछले कार्यक्रमों के भागीदारों से प्राप्त प्रतिज्ञान के आधार पर और उनकी बदलती भूमिकाओं और प्रकार्यों के आकलन के आधार पर भी डिप्लोमा कार्यक्रमों की अंतःवस्तु और पद्धति की रूपरेखा नए सिरे से तैयार की गई है। इनमें प्रबंधकीय कुशलताओं के उन्नयन पर, विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए परियोजनाएं और कार्रवाई की योजनाएं तैयार करने पर जोर दिया गया है। संस्थागत योजना, विद्यालय-मानचित्रण, विद्यालय संकुलों, परिमाणात्मक तकनीकों, गुणवत्ता-सुधार, संस्थागत मूल्यांकन, नेतृत्व के गुणों, संकट के समाधान, सामुदायिक भागीदारी आदि की विस्तृत विवेचना की गई।

कार्यक्रम की पद्धति व्याख्यान और विचार विमर्श, पैनल विचार विमर्श, केस अध्ययनों, सिंडिकेट विधि, अनुकरण के अभ्यासों, भूमिका-निर्वाह, इन-बास्केट विधि तथा पहचानशुदा विषयों पर सामूहिक विचार विमर्श पर आधारित थी। व्यावहारिक कार्यों, पुस्तकालय-आधारित प्रदत्तकार्यों और कुछ प्रमुख शिक्षा संस्थानों के भ्रमण पर भी पर्याप्त समय लगाया गया।

भागीदारों को विद्यालय-शिक्षा संबंधी प्रवर्तनकारी प्रयोगों और समुदाय-आधारित कार्यक्रमों से परिचित कराने के लिए राजस्थान के जिलों में एक सप्ताह का क्षेत्र-भ्रमण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।

2. शैक्षिक योजना और प्रशासन में अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा (आइडेपा)

पहले अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम का आयोजन जनवरी 1985 में किया गया था। जनवरी 1992 में शुरु होकर इस वर्ष पूरा होने वाले आठवें डिप्लोमा कार्यक्रम में 9 देशों के 13 अधिकारियों ने भाग लिया। नवां अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम फरवरी 1993 में आरंभ हुआ; इसमें 4 देशों के 6 अधिकारियों ने भाग लिया। संस्थान को विभिन्न धनदाता संगठनों से औपचारिक और अनौपचारिक रुपों में कार्यक्रम के बारे में सकारात्मक प्रतिज्ञान प्राप्त होता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम में देशवार भागीदारी तालिका 6 में दर्शाई गई है।

अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम का पहला चरण नीपा में तीन माह के गहन पाठ्यचर्यात्मक कार्य पर आधारित होता है। यह मूलभूत पाठ्यक्रमों और साथ में व्यावहारिक कार्य पर आधारित होता है। कार्यक्रम की पद्धति में सिद्धांत और व्यवहार के बीच

संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। मौटे तौर पर इसमें व्याख्यान और विचारविमर्श, अनुकरण और व्यावहारिक कार्य, भूमिका-निर्वाह, केसों पर विचार विमर्श, व्यावसायिक कार्य, खोज, सम्मेलन, प्रदर्शन और सामूहिक विचार विमर्श शामिल होते हैं। इसके अलावा भागीदारों को प्रोत्साहित करने के लिए पैनल विचारविमर्श और भागीदारों के लिए संगोष्ठियों का आयोजन पाठ्यक्रम की पद्धति की खास विशेषताएं हैं। यह कार्यक्रम व्यष्टिस्तरीय अकादमिक कार्यों, शैक्षिक या सांस्कृतिक क्षेत्र-भ्रमण, क्षेत्र शैक्षिक संबद्धताओं और ज्ञानवर्द्धक व्याख्यानों पर भी जोर देता है।

तालिका 6

आठवें और नवें अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रमों में देशवार भागीदारी

देश का नाम	भागीदारों की संख्या
बोत्सवाना	1
घाना गणराज्य	1
कीनिया गणराज्य	1
मारीशस	4
नाइज़ीरिया	2
रुवांडा	1
सेशल्स	1
तंजानिया	1
वियतनाम	2
उगांडा	3
जांबिया गणराज्य	2
योग	19

3. संस्थागत योजना

माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के लिए चार कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में 103 प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों और रेक्टरों ने भाग लिया। कुछ विवेचित पक्ष इस प्रकार रहे—अकादमिक निगरानी और नेतृत्व, शैक्षिक उत्पादकता, माध्यमिक शिक्षा से बढ़ती प्रत्याक्षाएं और प्रधानाध्यापकों की भूमिका और संस्थागत मूल्यांकन।

4. व्यष्टिस्तरीय योजना

प्रारंभिक शिक्षा की व्यष्टिस्तरीय योजना के लिए विद्यालयस्तरीय कार्मिकों के लिए तीन कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें 61 भागीदारों ने भाग लिया। इन कार्यक्रमों में निम्नलिखित

प्रश्नों की विवेचना की गई—विकेंद्रीकरण के संदर्भ में योजनकर्मियों की उदीयमान भूमिका, आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए मुद्दे, मांग का आकलन और लामबंदी, नामांकन के परिदृश्य में व्यावहारिकता, प्राथमिकता का निर्धारण और लक्ष्यों का निर्धारण, संसाधनों का आकलन और उनकी लामबंदी, पूर्ण साक्षरता अभियान से अंतःसंबंध, सभी के लिए शिक्षा के संदर्भ में आदिवासियों और दूरदराज के क्षेत्रों के हवाले से शिक्षा की विशेष समस्याएं, व्याष्टि स्तर पर शैक्षिक योजना की विकेंद्रीकृत प्रणाली, सभी के लिए शिक्षा की योजना, शैक्षिक विकास के सूचक, प्राथमिक चरण में अधिगम के न्यूनतम स्तर।

5. विकेंद्रीकरण और शिक्षा की जिलास्तरीय योजना

जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के संकाय के लिए शैक्षिक योजना और प्रबंध की विकेंद्रीकृत प्रणाली पर दो कार्यक्रम आयोजित किए गए। कुल मिलाकर जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के योजना और प्रबंध संकाय का प्रतिनिधित्व करने वाले 58 भागीदार इन दो कार्यक्रमों में उपस्थित रहे। इन कार्यक्रमों में विवेचित विशिष्ट विषय इस प्रकार रहे—राष्ट्रीय शिक्षा नीति और संशोधित कार्रवाई योजना, योजना और प्रबंध में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की भूमिका, सामुदायिक भागीदारी का गतिशास्त्र और प्रयोग-क्षेत्र का दृष्टिकोण, सभी के लिए शिक्षा के वास्ते व्यष्टिस्तरीय योजना की विधियां और तकनीकें।

जिलास्तरीय शैक्षिक योजना पर भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 8 भागीदार उपस्थित रहे। इन कार्यक्रम में विवेचित प्रमुख विषय इस प्रकार थे—जिला स्तर पर विकेंद्रीकृत योजना की आवश्यकता, विद्यमान स्थिति, शैक्षिक विकास के सूचक, जिलास्तरीय शिक्षा योजना के लिए आंकड़ों की आवश्यकताएं, आंकड़ा-भंडार के विकास में संगणकों का उपयोग।

6. अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा की योजना और प्रबंध

अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा पर दो कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 48 व्यक्तियों ने भाग लिया। इन कार्यक्रमों में विवेचित विषय इस प्रकार थे—लक्ष्य और उद्देश्य, राष्ट्रीय स्तर पर योजना, परियोजना की योजनाबंदी, कार्मिकों का प्रशिक्षण, पाठ्यचर्या और सामग्रियों का विकास, निगरानी और मूल्यांकन, राज्यों में अनौपचारिक शिक्षा की स्थिति की समीक्षा और भावी दिशाएं, अनौपचारिक शिक्षा की योजना और प्रबंध के क्षेत्र में जिलावार अनुभव और प्रश्न, अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों की अकादमिक दक्षता बढ़ाने से संबंधित प्रश्न।

7. उच्च शिक्षा की योजना और प्रबंध

उच्च शिक्षा की योजना और प्रबंध पर दस कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में कुल मिलकर 356 भागीदार उपस्थित रहे। प्रमुख विवेचित विषय इस प्रकार रहे—स्वायत्त महाविद्यालय : धारणा और व्यवहार; स्वायत्तता की योजना और क्रियान्वयन, स्वायत्त महाविद्यालयों की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहायता; पाठ्यक्रमों और पाठ्यचर्या की पुनर्रचना, परीक्षा-सुधार और परीक्षाओं का प्रबंध, अध्यापकों की अभिप्रेरणा, उच्च शिक्षा और विकास : नीति और कार्रवाई का कार्यक्रम, उच्च शिक्षा के केंद्रीय प्रश्न; शैक्षिक प्रशासकों के लिए टकराव का प्रबंध, सामुदायिक विकास में महाविद्यालय के संसाधन केंद्र की भूमिका, प्रबंध के सांगठनिक और व्यवहारगत पहलू, परिप्रेक्ष्य, संस्थागत योजना की तैयारी, अकादमिक स्टाफ महाविद्यालयों के कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समस्याएं और प्रश्न, अकादमिक स्टाफ महाविद्यालयों के विकास की भावी प्राथमिकताएं, अकादमिक स्टाफ महाविद्यालयों की कारगुज़ारी के मूल्यांकन की विधि और उसके पूरक।

8. अल्पसंख्यक शिक्षा और महिला शिक्षा की योजना और प्रबंध

अल्पसंख्यकों और महिलाओं की शिक्षा की योजना और प्रबंध पर तीन कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें 67 भागीदारों ने

भाग लिया। इन कार्यक्रमों में विवेचित प्रमुख विषय इस प्रकार थे—अल्पसंख्यकों की शिक्षा, महिला-शिक्षा की योजनाबंदी की प्रवृत्तियां, स्त्री-समानता, स्त्रियों के विकास की एकीकृत योजना पर मनन, अनुसूचित जाति की स्त्रियों की शिक्षा, महिला-शिक्षा के समाजशास्त्रीय पहलू और योजना की रणनीतियों में उनका समावेश, शिक्षा और महिलाओं का विकास, महिला साक्षरता और मुक्त शिक्षा, विकलांग स्त्रियों की शिक्षा, महिला-शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल आदि।

9. आदिवासियों और वंचित वर्गों की शिक्षा

आदिवासियों और वंचित वर्गों की शिक्षा के विषय पर चार कार्यक्रम चलाए गए जिनमें 88 भागीदार शामिल हुए। इन कार्यक्रमों में विवेचिल प्रमुख विषय इस प्रकार थे—दूरदराज के क्षेत्रों का शैक्षिक विकास : स्थितिपरक विश्लेषण, दूरस्थ क्षेत्रों के संदर्भ में आपूर्ति और मांग के सृजन से जुड़े प्रश्न; संश्लिष्ट क्षेत्रीय योजना की धारणा का परिचय और उसके अनुभव, आदिवासी शिक्षा : समस्याएं और प्रश्न, शिक्षा में समता और गुणवत्ता की प्राप्ति में आश्रम विद्यालयों की भूमिका, छात्रों के लिए परामर्श और मार्गदर्शन, लड़कियों की शिक्षा की समस्याएं आदि।

10. दूरवर्ती शिक्षा की योजना और प्रबंध

दूरवर्ती शिक्षा की योजना और प्रबंध के विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें 19 व्यक्तियों ने भाग लिया। प्रत्येक प्रश्न पर विचार विमर्श को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम को एक कार्यशाला की तर्ज पर तैयार किया गया था और भागीदारों से कहा गया कि वे प्रत्येक चुनिंदा प्रश्न पर टिप्पणियां/आलेख तैयार करें, जैसे—दूरवर्ती शिक्षा और मानव संसाधन विकास, दूरवर्ती शिक्षा की गुणवत्ता, दूरवर्ती शिक्षा में संबंधस्थापन आदि।

11. शिक्षा नीति और कार्यक्रमों की समीक्षा

शिक्षा नीति और कार्यकेंद्रों की समीक्षा के विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 7 भागीदार शामिल हुए। प्रमुख विवेचित विषय इस प्रकार थे—शिक्षा के प्रबंध में राज्यों के अनुभव, पंचायती राज व्यवस्था और कार्रवाई योजना (1992) का क्रियान्वयन।

12. भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण

भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और शिक्षा के लिए उसके निहितार्थों पर आगत-निर्गत अनुसंधान संगठन के सहयोग से तीन दिनों का एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित कि गई। इसमें प्रौद्योगिक, रोजगार और अनुसंधान-विकास समेत शिक्षा पर नई रोजकोषीय नीति, व्यापार और औद्योगिक नीतियों के प्रभावों और उनके निहितार्थों की विवेचना की गई। संगोष्ठी में नीतिनिर्माताओं, कार्यकारी अधिकारियों और अकादमिकों समेत 54 व्यक्तियों ने भाग लिया।

13. आर्थिक नीतियां और शिक्षा में संसाधनों का उपयोग

आर्थिक नीतियां और शिक्षा में संसाधनों के उपयोग पर पांच कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन पांच कार्यक्रमों में 175 भागीदार शामिल हुए। प्रमुख विवेचित विषय इस प्रकार थे—नई आर्थिक नीतियां और शिक्षा के लिए वित्त की व्यवस्था, शिक्षा के लिए अनुदान, विद्यालयशिक्षा के लिए वित्त की व्यवस्था, उच्च शिक्षा के लिए संसाधनों की लामबंदी, शिक्षा का निजीकरण, शिक्षा के लिए बाहरी सहायता, विद्यालय के संसाधनों का प्रबंध, वित्तीय प्रबंध, लागत विश्लेषण और लेखाकार्य में प्रधानाध्यापक की भूमिका, मानव संसाधन का प्रबंध।

14. शैक्षिक सांख्यिकी

शैक्षिक सांख्यिकी में प्रतिदर्शी सर्वेक्षण की तकनीकों के उपयोग पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला विशेषज्ञों के साथ परियोजना के परिणामों की विवेचना करने के लिए आयोजित की गई। इसका एक और उद्देश्य शैक्षिक आंकड़ों का उपयोग करने वाले राज्यस्तरीय अधिकारियों की परियोजना में विकसित

प्रतिदर्शी सर्वेक्षण की तकनीकों से परिचित कराना था ताकि वे अपने-अपने राज्यों में इनके उपयोग में समर्थ हो सकें। कार्यशाला में अकादमिकों और विशेषज्ञों समेत 24 भागीदार शामिल हुए।

15. शिक्षा पर जनांकीय दबाव

शिक्षा पर जनांकीय दबावों के विषय पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य हाल की जनांकीय प्रवृत्तियों और शिक्षा प्रणाली के लिए उनके निहितार्थों, जनांकीय और शैक्षिक प्रक्षेपण के प्रतिरूपों तथा उनके अंतःसंबंध की समस्याओं की विवेचना करना था। इसमें बिहार और आंध्रप्रदेश के तीन अधिकारियों ने भाग लिया।

16. शैक्षिक योजना और प्रबंध में संगणकों का व्यवहार

शैक्षिक योजना और प्रबंध के लिए संगणकों के व्यवहार पर पांच कार्यक्रम चलाए गए। इनमें 63 भागीदार शामिल हुए। इन कार्यक्रमों में विवेचित प्रमुख विषय इस प्रकार थे—शिक्षा में संगणकों का व्यवहार : आंकड़ों के संग्रह की विद्यमान प्रणालियों के साथ संगणक-आधारित शैक्षिक योजना का अभिसार, साफ्टवेयर और संगणक आधारित शैक्षिक योजना की सहायता से निर्णयकार्य, संगणक आधारित शैक्षिक योजना के क्रियान्वयन की कार्रवाई योजना, शैक्षिक आंकड़े : आवश्यकताएं और कमियां, आंकड़े और सूचनाएं और सूचकों का निर्माण, शैक्षिक प्रबंध सूचना प्रणाली और कार्मिक प्रबंध सूचना प्रणाली का परिचय।

17. संस्थागत पुस्तकालयों की योजना और प्रबंध

जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थाओं के पुस्तकालयों की योजना और प्रबंध पर एक कार्यक्रम चलाया गया। इसमें 15 भागीदार शामिल हुए। इस कार्यकाल में विवेचित प्रमुख विषय इस प्रकार थे—जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के पुस्तकालयों की योजना और प्रबंध, सूचना संबंध-स्थापन, योजना की तकनीकें, पुस्तकालय प्रबंध, ड्यूवी दशमलव वर्गीकरण और सूचना सेवा का परिचय।

18. अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा के अलावा चीन लोकगणराज्य की सरकार के सात अधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना और प्रबंध पर एक माह का एक कार्यक्रम चलाया गया। इसे यूनिसेफ ने प्रायोजित किया था। इसका उद्देश्य शैक्षिक और राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों को पाने के लिए मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में भारत और चीन के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करना था। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रीय परिवेशों में प्राप्त अनुभवों के आदान प्रदान के द्वारा भारत और चीन जैसे विकासशील देशों में शैक्षिक योजना और प्रबंध की संरचना और प्रक्रियाओं का अध्ययन करना था।

मानद अध्येताः उत्सुनोमिया विश्वविद्यालय, जापान के शिक्षा संकाय के ऐसोसिएट प्रोफेसर डा. हिदेयाकी शिबुया अतिथि फैलो के रूप में नीपा में आए। वे जापान फाउंडेशन के फेलोशिप कार्यक्रम के तहत मार्च 1993 में डेढ़ माह के लिए 'राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारत में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की परियोजनाओं का आयोजन और संचालन' विषय पर शोध-अध्ययन के लिए आए थे। डा.शिबुया ने राजस्थान में आधारभूत स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं की योजना और प्रबंध का अध्ययन करने के लिए गहन क्षेत्र-भ्रमण की योजनाएं बनाई थीं।

19. संसाधन सहायता

संस्थान द्वारा अपने बल पर और अन्य संगठनों के सहयोग से आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा विभिन्न राज्यों, संघीय क्षेत्रों, विद्यालयों और अन्य संगठनों को अकादमिक संसाधन सहायता प्रदान की। अनुबंध I में इन संगठनों का विवरण दिया गया है।

1992–93

अध्याय 3

अनुसंधान और प्रकाशन

अनुसंधान

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (नीपा) शैक्षिक योजना और प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान की सहायता, प्रोत्साहन और समन्वय के कार्यों में सक्रिय रूप से संलग्न है। इन अनुसंधानों का स्वरूप बहुशास्त्रीय होता है जिसमें शैक्षिक योजना और प्रशासन के सिद्धांत, उसकी विधियों, तकनीकों और प्रक्रियाओं पर खास जोर दिया जाता है।

संस्थान संकाय की शोध-परियोजनाओं को धन की सहायता देकर, अन्य संगठनों से शोध-परियोजनाएं स्वीकार करके तथा प्राथमिकता के क्षेत्रों में शोध के लिए विशेषज्ञों और संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके अनुसंधानकार्य को बढ़ावा देता है।

नीपा द्वारा संचालित और समर्थित अनुसंधान में सैद्धांतिक और अनुभवाश्रित प्रश्नों का समन्वय किया जाता है। संस्थान की शोध-गतिविधियां नीतियों और योजनाओं के निरूपण के लिए ठोस अनुभवाश्रित और वैश्लेषिक आधार प्रदान करने के निरंतर प्रयास करती हैं। वे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण सामग्री भी प्रदान करती हैं।

समीक्षाधीन वर्ष में सात शोध-अध्ययन पूरे हुए जबकि सोलह अध्ययन प्रगति पर थे। पांच नए अध्ययनों की स्वीकृति दी गई। नए अध्ययनों में एक के लिए संस्थान वित्त दे रहा है, तीन अन्य संगठनों द्वारा प्रायोजित हैं और एक को नीपा की सहायता-योजना के अंतर्गत स्वीकृति दी गई है।

इस वर्ष संस्थान के संकाय द्वारा शुरू किए गए शोध-अध्ययनों पर कुल 7.45 लाख रुपए का व्यय आया। इस वर्ष नीपा की सहायता-योजना के अंतर्गत अध्ययनों के लिए जारी किए गए अनुदानों की कुल राशि 0.31 लाख रुपए रही जबकि बाहरी संगठनों द्वारा प्रायोजित अध्ययनों के लिए 36.41 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई।

पूरे होने वाले अध्ययनों की प्रमुख बातें

विकेंद्रीकृत योजना

निकट अतीत में योजनाओं में केंद्रीकृत की बजाय विकेंद्रीकृत योजनाओं पर जोर दिया जाने लगा है। जोर के इस परिवर्तन के साथ जिला स्तर पर शैक्षिक विकास की योजना और प्रशासन की समस्याएं तात्कालिक महत्व के विषय बनकर उभरी हैं। इसलिए संस्थान ने इन क्षेत्रों में शोध-हस्तक्षेप करके इन उदीयमान केंद्रीय प्रश्नों पर अपना प्रत्युत्तर दिया है।

जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की आधारभूत स्तर पर विकेंद्रीकृत योजना और प्रशासन की बुनियादी कड़ियां माना गया है। ये संस्थान जिलास्तरीय शैक्षिक योजनाओं में उत्प्रेरक की भूमिका निभाएंगे। इसलिए गहन अध्ययन के लिए *हरियाणा के चुनिंदा जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों* को चुना गया ताकि रणनीतिक महत्व के नीतिगत हस्तक्षेपों की पहचान की जा सके। इन जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों को उपलबध संसाधनों और उनके सामने मौजूद बाधाओं के बीच भारी अंतर पाए जाते हैं। अध्ययन में प्रशासनिक संरचना की कमियों और

अकुशल नेतृत्वकारी भूमिका की पहचान की जाती है। इनके लिए उपचारात्मक उपाय भी सुझाए गए हैं।

केंद्रीकृत की जगह विकेंद्रीकृत येाजना पर बल दिए जाने के बाद शैक्षिक विकास में स्वयंसेवी प्रयासों और सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता स्वीकार की गई है। राजस्थान की *'लोक जुंबिश'* और *'शिक्षाकर्मी परियोजनाएं'* इस दिशा में कुछ प्रवर्तनकारी प्रयास हैं। एक विशेषीकृत अध्ययन ऐसे व्याख्यात्मक और वैश्लेषिक ढांचे के विकास के लिए आरंभ किया गया है जिसके संदर्भ से शिक्षाकर्मी परियोजना की प्रबंध-संरचना के कार्यक्रम का आकलन किया जा सके और लोक जुंबिश कार्यक्रम से उसके अंतःसंबंध की पहचान की जा सके। इस अध्ययन ने शिक्षाकर्मी कार्यक्रम की ऐसी संभावित और व्यावहारिक रणनीतियों के निरूपण का प्रयास किया है जिनके सहारे लोकजुंबिश से इष्टतम परिणाम प्राप्त हो सकें। यह अध्ययन शिक्षाकर्मी कार्यक्रम और लोक जुंबिश परियोजना के आपसी सहयोग पर जोर देता है क्योंकि प्राथमिक शिक्षा दोनों के केंद्र में है। इसका उद्देश्य यह है कि शिक्षाकर्मी कार्यक्रम से प्राप्त शोध परिणामों, संसाधनों और अनुभवों का लोक जुंबिश परियोजना के लिए लाभकारी उपयोग किया जा सके। शिक्षाकर्मी कार्यक्रम भूमिका के प्रतिरूप का काम भी कर सकता है।

उच्च शिक्षा में संस्थागत स्तर पर योजनाओं के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए स्वायत्त महाविद्यालयों की धारणा का समावेश किया गया है। *उच्च शिक्षा में संस्थाओं की स्वायत्तता का प्रबंध* शीर्षक परियोजना केस अध्ययनों के विकास के द्वारा स्वायत्तता के प्रबंध की समस्याओं की पहचान के लिए आरंभ की गई। अध्ययन के परिणामों ने स्वायत्त महाविद्यालयों की भिन्नक संरचना को स्पष्ट किया हैं जिसमें प्रबंध में अध्यापकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है।

गुणवत्ता और समता

परिमाणात्मक प्रसार और गुणात्मक सुधार के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान, पेरिस के सहयोग से नीपा ने *"बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता"* पर एक परियोजना का आरंभ किया। यह मुख्य रूप से निर्धारित उपराष्ट्रीय दिक् के अंदर गुणवत्ता की देशकालिक विभिन्नताओं पर केंद्रित था। इस अध्ययन ने इस तथ्य को उजागर किया कि भौगोलिक और साथ ही सामाजिक-आर्थिक भिन्नताओं के कारण विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नीतिगत हस्तक्षेपों की आवश्यकता है।

शैक्षिक विकास की असमानताओं में व्याप्त सामाजिक-आर्थिक असमानताओं से सीधा संबंध है। अनुसूचित जातियां और जनजातियां भारतीय समाज के वंचित सामाजिक-आर्थिक वर्गों में आती हैं। साक्षरता की दर के सूचक पर भी निगाह डालें तो सुस्पष्ट असमानताएं पाई जाती हैं; इसे शैक्षिक विकास के सूचक की तरह भी प्रयुक्त किया जा सकता है। *'भारत में अनुसूचित जातीय और गैर-अनुसूचित जातीय जनसंख्या की साक्षरता के स्तरों की विषमताओं का जिलेवार विश्लेषण'* शीर्षक परियोजना प्राथमिकता के इसी क्षेत्र से संबंधित है। यह अध्ययन इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि अंतराजातीय विषमताएं भी उतनी ही सुस्पष्ट हैं जितनी अंतःजातीय विषमताएं हैं और इसलिए संरक्षणमूलक भेदभाव की नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन आवश्यक है।

'महिला महाविद्यालयों की प्रधानाचार्याओं की प्रशिक्षण-आवश्यकताओं की पहचान' शीर्षक परियोजना एक ओर संस्था के स्तर पर इन समस्याओं का तथा दूसरी ओर महिलाओं की संस्थाओं की विशेष समस्याओं का अध्ययन करने के लिए आरंभ की गई। अध्ययन के परिणामों ने प्रशिक्षण की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे योजना और प्रबंध, दोनों की प्रक्रियाओं में संगणकों के उपयोग, बेरोजगारी के गतिशास्त्र, महिलाओं की भूमिका और अस्मिता, और खासकर उद्यमशीलता की पहचान की है। महिला प्रशासकों की विशिष्ट समस्याओं की भी पहचान की गई है।

1992–93

शैक्षिक सांख्यिकी में सर्वेक्षण की तकनीकें

अनुभवों से पता चलता है कि नीतियों और योजनाओं के निरूपण के लिए आंकड़ों का भंडार अपर्याप्त, पुरातन और अविश्वसनीय है। एक सार्थक आंकड़ाप्रणाली के विकास के लिए कदम के रूप में संस्थान ने यूनेस्को, पेरिस के सहयोग से *'शैक्षिक सांख्यिकी में प्रतिदर्शी सर्वेक्षण की तकनीकों का उपयोग'* शीर्षक से एक परियोजना का आरंभ किया। इस अध्ययन ने भारत में शैक्षिक सांख्यिकी के स्रोतों की विविधता, विद्यमान आंकड़ाप्रणाली की अपर्याप्तताओं, उसकी व्याप्ति और उसकी प्रकृति की पहचान की है। इस अध्ययन ने एक प्रतिदर्शी प्रारूप तथा व्यापक संस्थागत और पारिवारिक प्रश्नावालियों का विकास किया है। स्थानीय विशिष्टताओं के अनुसार किसी संशोधन के बिना या कुछ संशोधन करके इस पद्धति का अनुकरण किया जा सकता है। अध्ययन ने नामांकनों की यथार्थ से अधिक सूचनाएं देने के परिमाणात्मक आयामों, प्रासंगिक आयु से अधिक या कम आयु वालों के नामांकन तथा विद्यालयत्यागियों के परिमाण और साथ ही इन विशेषताओं में पाई जानेवाली आयुविशिष्ट, लिंगविशिष्ट और जाति विशिष्ट भिन्नताओं को स्पष्ट किया है।

कृषि विज्ञान की शिक्षा का अर्थशास्त्र

नीपा ने *कृषि में विश्वविद्यालयस्तरीय शिक्षा के लागत लाभ विश्लेषण* पर एक अध्ययन प्रायोजित किया है। हालांकि कृषि-क्षेत्र एक ग्राम-आधारित उद्योग है, मगर फिर भी कृषिविज्ञान की उच्चशिक्षा अभिजातमुखी है। कमजोर वर्गों के लिए कृषिविज्ञान की शिक्षा सुलभ नहीं है। परिवारों को प्राप्त भारी प्रतिफल और कम लागत अनुदानों में कमी की संभवना के संकेत देती हैं। लेकिन हाल में शुल्कों से इतर निजी लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस कारण लागतों को बढ़ने से रोकने के लिए नीतिगत हस्तक्षेपों की आवश्यकता है ताकि यह लागतें मध्य आयवर्गों तक की क्षमता से बाहर न निकल जाएं। इस आधार पर ही निजीकरण और लागत की पूरी वसूली के कार्यक्रमों की सिफारिश नहीं की गई है। वित्तीय बाधाओं की कम करने के लिए ऋणों की उदार स्वीकृति के सुझाव दिए गए हैं।

जारी अध्ययन

इस समय 16 अध्ययन प्रगति पर हैं। ये अध्ययन भी मोटे तौर पर प्राथमिकता के उन्हीं क्षेत्रों पर केंद्रित हैं जिनका संकेत पहले के अनुच्छेदों में दिया गया, है। जहां तीन अध्ययन शैक्षिक प्रौद्योगिकी की योजना और प्रबंध की समस्याओं पर केंद्रित हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक प्रशासक के देशव्यापी सर्वेक्षण पर भी एक अध्ययन जारी है। *विद्यालय मानचित्रण* संबंधी परियोजना का उद्देश्य स्थानिक योजना की वर्तमान प्रक्रियाओं और पद्धति का मूल्यांकन करना है।

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की पाने के लिए योजना के सिद्धांत, नीति और तकनीकों का निरंतर उन्नयन ही आवश्यक नहीं है, दूसरे देशों के अनुभवों से कुछ सीखना और उनका उपयोग करना भी आवश्यक है। लेकिन विद्यमान स्थिति की आवश्कताएं पूरी करने के लिए मात्र औपचारिक शिक्षा पर्याप्त नहीं है। औपचारिक शिक्षा के पूरक रूप में अनौपचारिक शिक्षा भी आवश्यक है। भारत दूसरे देशों के अनुभवों से कुछ सबक ले सकता है, और देश के राज्य भी ऐतिहासिक अनुभवों और अन्य राज्यों की सफलता की भाषाओं से कुछ सीख सकते है। *'लातीनी अमरीका में अनौपचारिक शिक्षा की योजना और प्रबंध : भारत के लिए इसके सबक और निहितार्थ', 'उत्तरप्रदेश में सभी के लिए बुनियादी शिक्षा', 'सार्वभौम प्रारंभिक शिक्षा की निगरानी के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्शी सर्वेक्षण'* तथा *'पहाड़ी बोड़ो के जीवनमूल्य और उनकी भागीदारी'* संबंधी परियोजनाएं इसी श्रेणी में आती हैं। *'राष्ट्रीय प्रतिदर्शी सर्वेक्षण का उपयोग'* संबंधी परियोजना सार्वभौम प्रारंभिक शिक्षा की प्रगति का मूल्यांकन और उसकी निगरानी के लिए तैयारी की गई हैं। प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनीकरण तब तक नहीं हो सकता जब तक शिक्षा जनता के सभी वर्गों तक न पहुंच जाए। इसी की ध्यान में रखकर *'पहाड़ी बोडों के जीवनमूल्य*

और उनकी भागीदारी' संबंधी योजना का आरंभ किया गया है।

परियोजना *'भारत में शैक्षिक विकास की क्षेत्रीय विषमताएं : आधारभूत स्तर पर समाज कल्याण के संदर्भ में शैक्षिक विषमताओं का अन्वेषण'* की रूपरेखा 'सामाजिक न्यायपूर्ण संवृद्धि, के उद्देश्यों को पाने के उद्देश्य से योजनागत हस्तक्षेपों का विकास करने के लिए तैयार की गई है। यह अध्ययन शिक्षा की विकास के एक वृहत्तर समुच्चय का एक उपसमुच्चय मानता है और इस प्रकार विकासप्रक्रियाओं के संदर्भ में शैक्षिक विकास की प्रक्रिया की विद्यमान विकृतियों की व्याख्या करने का प्रयास करता है।

संसाधनों का उपयोग भी प्रणाली की आंतरिक दक्षता जितना ही महत्वपूर्ण होता है। जहां संसाधनों का आवंटन नीतियों और वैश्लेषिक अध्ययनों के केंद्र में रहा है वहीं उपयोग का पक्ष उपेक्षित रहा है। *संसाधनों का उपयोग* संबंधी अध्ययन इसी कमी को पूरा करने का प्रयास है।

उच्च शिक्षा संस्थाओं में वित्तीय प्रबंध की समस्याएं संबंधी अध्ययन बुनियादी बाधाओं, उच्च शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्यों की रोशनी में भारतीय विश्वविद्यालयों के वित्तीय दायित्व के बदलते संदर्भ की ओर ध्यान दिलाता है। आशा है कि यह अध्ययन मौजूदा सरोकार और रुचि के अनेक परस्पर संबंधित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा।

महाविद्यालयों की स्वायत्तता एक नई धारणा है। इसलिए स्वायत्त महाविद्यालयों में प्रबंध की समस्याएं सरोकार का एक नया क्षेत्र है। स्वायत्त महाविद्यालयों संबंधी परियोजना इसी अनुभूत आवश्यकता की पूरा करती है। इस परियोजना का दूसरा चरण चल रहा है।

वित्तीय बाधाओं को दूर करने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने भी अनेक कार्यक्रमों और नीतियों का निरूपण किया है। वंचित वर्गों की सामाजिक बाधाओं की दूर करना एक नीतिगत सरोकार रहा है। नीपा ने *राष्ट्रीय ग्रामीण प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना का एक मूल्यांकन अध्ययन* इसी संदर्भ में आरंभ किया है।

परियोजना *विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं की पहचान* विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करता है।

पाठ्यचर्या संबंधी आवश्यकताओं की पहचान प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं की पहचान से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। परियोजना *अवरस्नातक स्तर पर पाठ्यचर्या की पुनर्रचना की समस्याएं और संभावनाएं* का उद्देश्य इसी समस्या की छानबीन करना है।

शिक्षा की योजना और प्रशासन में संगणकों का उपयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। शैक्षिक प्रबंध सूचनाप्रणाली शोध का एक प्रमुख क्षेत्र बनकर उभरी है और इस कारण एक व्यापक और मानव शैक्षिक प्रबंध सूचना प्रणाली का विकास अनिवार्य है। संगणक आधारित शैक्षिक योजना संबंधी परियोजना इसी अनुभूत आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास करती है।

नए अध्ययन

इस वर्ष पांच नए अध्ययन भी शुरू किए गए। *भारत के चुनिंदा विश्वविद्यालयों की योजना और विकास* तथा *पिछड़े जिलों में 100 महाविद्यालयों का विकास* संबंधी परियोजनाएं पिछड़े जिलों में उच्च शिक्षा की अनेक समस्याओं पर केंद्रित हैं। परियोजना *आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी और खम्मम जिलों के आदिवासी क्षेत्रों में एक अध्यापक वाले विद्यालयों का मूल्यांकन-अध्ययन* का उद्देश्य विद्यालयों के अध्यापकों की इस विशेष समस्या का अध्ययन करना है। *आधारभूत स्तर पर महिला-कल्याण* संबंधी अध्ययन सामान्यतः महिलाओं के विकास और विशेषकर उनकी शिक्षा की स्वीकृत योजना के प्रति बढ़ते सरोकार की प्रतिक्रियास्वरूप आरंभ किया गया है।

1992–93

वर्ष 2000 तक प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनीकरण : वैकल्पिक नीति समूहों के लिए उनके संसाधन संबंधी निहितार्थ शीर्षक अध्ययन का उद्देश्य सार्वभौम प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित वैकल्पिक नीतिसमूहों के लिए संसाधन संबंधी आवश्यकताओं का आकलन करना है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि संस्थान के शोध-अध्ययन शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में उदीयमान प्रश्नों को प्रतिबिंबित करते हैं। अलग-अलग अध्ययनों के ब्यौरे आगे दिए गए हैं।

पूरे हो चुके अध्ययनों का विहंगावलोकन

1. हरियाणा के चुनिंदा जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों का अध्ययन (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)

इस अध्ययन पर 12,092 रुपये व्यय हुए। परियोजना दल में डॉ. (श्रीमती) सुदेश मुखोपाध्याय (अध्येता, विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा एकक, नीपा), डॉ. (श्रीमती) प्रमिला मेनन (सह-अध्येता, शैक्षिक नीति एकक, नीपा) और डॉ.बी.के.पंडा (वरिष्ठ तकनीकी सहायक, नीपा) शामिल थे।

अध्ययन के उद्देश्य

संबद्ध जिले के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक संदर्भों में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के शैक्षिक हस्तक्षेप के क्षेत्रों की पहचान करना; स्थापना के बाद संस्थान की गतिविधियों और उसे उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं का सर्वेक्षण करना; गतिविधियों के निर्धारण, क्रियान्वयन और निगरानी में जिला, राज्य और राष्ट्र स्तर के संगठनों से संस्थान की प्राप्त प्रशासनिक, वित्तीय और आकदमिक सहायता का अध्ययन करना; इन संस्थानों को प्रभावी बनाने के मकसद से सिफारिश देने के लिए आमतौर पर योजना के क्रियान्वयन के समग्र परिदृश्य का और खासतौर पर चुनिंदा जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों का अध्ययन करना।

प्रमुख निष्कर्ष

ये संस्थान अध्यापक-शिक्षा के पुनर्गठन और पुनर्रचना की रणनीति के तहत जिला योजना को सहायता देने के लिए स्थापित किए गए थे। योजना की रूपरेखा के निर्धारण और उसके क्रियान्वयन के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने तथा अकादमिक और प्रशासनिक सहायता जुटाने के लिए इस बारे में केंद्र सरकार ने पहल की थी। लेकिन अंतिम विश्लेषण में योजना की सफलता राज्य सरकार के प्रयासों पर निर्भर है।

हरियाणा के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों से संबंधित शक्तिसंवर्धन समिति और राज्य सरकार ने आरंभ में तीन शाखाएं खोलने का फैसला इस समझ से लिया कि आगे और शाखाएं खोली जाएंगी। लेकिन उपलब्ध सूचनाओं से स्पष्ट है कि दोनों संस्थानों में केवल दो शाखाएं कार्यरत थीं। यह बात योजना को कार्यरूप देने के बारे में सवाल खड़ा करती है। व्यवहार से स्पष्ट है कि आई. एफ. आई. सी. शाखा और अन्य शाखाओं में पूरे स्टाफ के अभाव में संभव है कि ये संस्थान अध्यापक-प्रशिक्षण संस्थान बनकर रह जाएं। योजना का उद्देश्य निश्चित ही यह नहीं है। अन्य शाखाएं खोलकर और संस्थानों में पूरा स्टाफ भरती करके स्थिति में सुधार लाने के लिए तत्काल कदम उठाना आवश्यक है। आठवीं योजना के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रस्ताव पहले ही सेवाकालीन शाखा को मजबूत बनाने और सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए अतिरिक्त स्टाफ और धन देने की स्वीकृति देने की बातें करते हैं। राज्य की तैयारी के बिना इन उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा सकता।

अध्यापकों की सेवाकालीन शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा व अनौपचारिक शिक्षा के कार्मिकों का प्रशिक्षण इन संस्थानों की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में शामिल हैं। इनसे प्रयोग-क्षेत्र का प्रश्न भी खड़ा होता हैं। ध्यान देने की बात यह है कि किसी भी संस्थान ने प्रयोगक्षेत्र की पहचान या प्रयोगक्षेत्र के लिए योजना की गतिविधियों के लिए कोई कार्य आरंभ नहीं किया है।

इन संस्थानों में अभी तक हस्तक्षेप की योजनाएं बनाने और

सेवाकालीन प्रशिक्षण की नीति तय करने के लिए जिलों और खासकर अध्यापकों के परिदृश्य तैयार नहीं किए हैं। ऐसी गतिविधियों के आरंभ में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद तथा राज्य सरकार के विभाग का और रुचि लेना भी आवश्यक है। इन संस्थानों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रारंभिक स्तर (कक्षा 1-8) तक के अध्यापकों की समेटेंगे लेकिन पाठ्यविवरण केवल कक्षा 1-5 के लिए अध्यापक तैयार करने की बात करता हैं। इस पर ध्यान देना जरूरी है।

2. शैक्षिक सांख्यिकी में प्रतिदर्शी सर्वेक्षण की तकनीकों का उपयोग (यूनेस्को, पेरिस द्वारा प्रायोजित)

इस अध्ययन के लिए यूनेस्को (पेरिस) ने 2.71 लाख रुपये की व्यय राशि प्रदान की थी। शैक्षिक योजना एकक के वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष प्रो. श्रीप्रकाश इस परियोजना के निदेशक थे। सुश्री तरुज्योति बुड़ागोहाईं और सुश्री सुमित्रा चौधरी परियोजना सहायिका थीं। योजना एकक के डॉ.ए.सी. मेहता, डॉ. रंजना श्रीवास्तव और डॉ.एस.एम.ए.आई. ज़ैदी ने प्रो. श्रीप्रकाश की सहायता की।

उद्देश्य

(अ) विद्यमान आंकड़ा प्रणाली के आकार, व्याप्ति और प्रकृति की अपर्याप्तताओं, खासतौर पर एक ओर योजनाओं के लिए आवश्यक आंकड़ों और विद्यमान आंकड़ा प्रणाली से प्राप्त आंकड़ों के बीच की खाई और दूसरी ओर उपलब्ध आंकड़ों की कमियां और सीमाओं, सामयिकता, विश्वसनीयता और प्रतिनिधिकता की स्पष्ट करने के लिए भारत में शिक्षा की विद्यमान आंकड़ा प्रणाली की समीक्षा करना।

(ब) शैक्षिक आंकड़ों के संग्रह के लिए प्रतिदर्शी प्रारूप और प्रश्नावली का विकास तथा सर्वेक्षण की उपयुक्त तकनीकों का निर्धारण ताकि मौजूद कमियों को दूर किया जा सके, योजना और नीतियों के निरूपण के लिए उनकी समय पर उपलब्धता सुनिश्चित हो और उनका एक प्रतिनिधिक चरित्र हो और उनमें पर्याप्त विश्वसनीयता हो।

(स) हस्तक्षेप के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए सार्वभौम प्रारंभिक शिक्षा के कार्यक्रमों की मौजूदा स्थिति, प्रवृत्तियों, शक्तियों और कमजोरियों का मूल्यांकन।

प्रमुख निष्कर्ष

शैक्षिक आंकड़ों की मौजूदा प्रणाली अनेक सीमाओं से ग्रस्त है। इसमें सामाजिक-आर्थिक प्रणालियों की आंकड़े संबंधी आवश्यकताओं और उपलब्ध शैक्षिक आंकड़ों के बीच अनेक कमियां भी पाई जाती हैं। विद्यमान शैक्षिक आंकड़ा प्रणालियों की अहम कमियों का संबंध नामांकनों, विद्यालयत्यागियों और अनुत्तीर्ण छात्रों के आयु और श्रेणी आधारित वर्गीकरण की अनुपलब्धता, औसत विद्यालय उपस्थिति दरों, मान्यतारहित और सहायतारहित निजी संस्थाओं के नामांकनों, निजी शिक्षा व्यय, शैक्षिक आगतों की मदों के अनुसार कीमतों, स्थिर लागत के विस्तृत मदवार वर्गीकरण, छात्रों की उपलब्धि के सामान्य स्तरों और नामांकनों के अल्पाकलन/अत्याकलन संबंधी आंकड़ों की अनुपलब्धता से है।

इसमें प्रणाली संबंधी कुछ प्रमुख प्रश्नों की विवेचना की गई है, जैसे—एक तरफ सरल यदृच्छ प्रतिदर्शन से विलयन का प्रभाव तथा दूसरी तरफ सरल आकलनों में सटीकता संबंधी लाभ और वे अन्य विभिन्न लाभ जो जनसंख्या के स्तरीयकरण से प्राप्त होते हैं। इसके लिए अनुभवाश्रित व्यवहारों तथा प्रायोगिक प्रतिदर्शन से प्राप्त अनुभवों के दृष्टांत दिए गए हैं।

अध्ययन के लिए विकसित प्रतिदर्शी प्रारूप के औचित्य और उसके अनुभवाश्रित व्यवहारों की विस्तृत चर्चा की गई है। दृष्टिकोण की शुद्धता का त्याग करके प्रतिदर्शन की अनेक विधियों को एक समन्वित पद्धति में मिलाया गया है और सहेतुक बहुस्तरीय गुच्छक/संस्तरित व्यवस्थित प्रतिदर्श की

वैधता का अनुभवाश्रित परीक्षण किया गया है जिसके लिए वरीयता प्राप्त प्रतिदर्शी प्रारूप से प्राप्त आंकड़ों का आधार बनाया गया है। प्रतिदर्श में सोद्देश्य ढंग से शामिल किए गए चार राज्यों के प्रतिनिधिक चरित्र का मूल्यांकन करने के लिए सहैतुक चयन के प्रभावों का विश्लेषण किया गया हैं। वास्तव में इस प्रतिदर्श ने उन जनसंख्या-समष्टियों के ऐसे बहुत कुछ सटीक आकलन प्रदान किए है जिनका संबंध आयु, लिंग और जाति संबंधी विशेषताओं के प्रतिदर्शन से है। चार प्रतिदर्षित राज्यों ने कुल मिलाकर पूरे देश के लिए अनुभवाश्रित वैधता से युक्त समष्टिजीय आकलन प्रदान किया है।

प्रतिदर्शन के अगले दो चरणों में प्रतिदर्शित इकाइयों के संस्तरित यदृच्छ चयन ने सहैतुक चयन से प्रतिदर्शन के पहले चरण में प्राप्त परिणामों की भांति ही अच्छे और विश्वसनीय परिणाम दिए हैं। प्रतिदर्शन के अंतिम चरण में विद्यालयों के संस्तरित व्यवस्थित चयन ने जनसंख्या-लक्षणों के ऐसे प्रतिदर्शी आकलन दिए हैं जो युक्तिसंगत ही नहीं बल्कि अत्यंत विश्वसनीय भी हैं। इससे संकेत मिलता है कि शैक्षिक योजना और विकास के लिए सामयिक, विश्वसनीय और पर्याप्त आंकड़ों का भंडार तैयार करने के लिए इस प्रतिदर्शन-विधि पर हम भरोसा कर सकते हैं। प्रतिदर्शन की इकाई को चुनने में यादृष्छिकता को छोड़ देने से प्रतिदर्शी आकलनों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा।

प्रतिदर्श में शामिल चार राज्यों के प्रतिदर्शीत आंकड़ों के चुनिंदा मदों का दृष्टांतमूलक विश्लेषण दिखाता है कि नामांकन के लिए निर्धारित आयु तथा अध्ययन की वास्तविक आयु और श्रेणियों में पर्याप्त अंतर पाया जाता है।

प्रायोजिक सर्वेक्षण इस प्रस्थापना की पुष्टि करता है कि विद्यमान आंकड़ाप्रणाली की अपर्याप्तताओं, सीमाओं और कमियों को एक ऐसी वैकल्पिक आंकड़ा प्रणाली से दूर किया जा सकता है जो जनगणना-आधारित आंकड़ा प्रणाली की अपेक्षा बहुत कम संसाधन-लागत वाले प्रतिदर्शन पर आधारित हो।

यूनेस्को (पेरिस) को तीन रिपोर्टें प्रस्तुत की गई हैं। वह उनके संक्षिप्त और समन्वित संस्करण प्रकाशित करने जा रहा है।

३. 'राजस्थान में लोक जुंबिश और शिक्षाकर्मी परियोजना के समन्वय' का अध्ययन (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)

इस अध्ययन को नीपा ने कुल 80,000 रुपये की लागत से पूरा किया। श्रीमती अंजला मंगलागिरि (अध्येता, अंतर्राष्ट्रीय एकक, नीपा) और श्रीमती कोमल श्रीवास्तव इसके अनुसंधान दल में शामिल थीं।

उद्देश्य

इस अध्ययन के दो उद्देश्य थे। पहला, एक व्याख्यात्मक और वैश्लेषिक प्रयास के रूप में इसमें शिक्षाकर्मी कार्यक्रम की प्रबंधकीय संरचना और कारगुजारी का एक समेकित आकलन किया गया ताकि लोक जुंबिश कार्यक्रम के लिए उससे कुछ सबक हासिल किए जा सकें। दूसरे, उसने शिक्षाकर्मी कार्यक्रम की उन संभावनाओं और व्यावहारिक रणनीतियों की पहचान की जिनको लोक जुंबिश कार्यक्रम में अभीष्टतम परिणाम पाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके।

इस अध्ययन ने शिक्षाकर्मी कार्यक्रम के सकारात्मक अनुभवों का उपयोग किया। साथ ही उसने लोक जुंबिश कार्यक्रम को अन्य शक्तियों के गतिशास्त्र और घात-प्रतिघात के बारे में आगाह किया।

प्रमुख निष्कर्ष

अध्ययन के प्रमुख परिणाम और निहितार्थ इस प्रकार है : (अ) प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षाकर्मी कार्यक्रम के अनुभवों और कार्यों की तथा लोक जुंबिश कार्यक्रम के पहले चरण में प्राथमिक शिक्षा पर उसके जोर को देखते हुए जरूरी है कि लोक जुंबिश कार्यक्रम न केवल शिक्षाकर्मी के ठोस अनुभवों से लाभ उठाए बल्कि उसके साथ घनिष्ठ संबंध बनाकर काम भी करे। इसलिए अध्ययन ने सिफारिश की है कि लोक जुंबिश शिक्षाकर्मी कार्यक्रम से साझे क्षेत्रों में जुड़े और जहां भी

व्यावहारिक हो, शिक्षाकर्मी कार्यक्रम द्वारा पैदा किए या पहचाने गए संसाधनों का उपयोग करे। जैसे लोक जुंबिश के लिए शिक्षाकर्मियों और प्रशिक्षकों का संसाधन-व्यक्तियों के रूप में उपयोग/अंतिम बात, शिक्षाकर्मी कार्यक्रम लोक जुंबिश के लिए सलाहकार निकाय का काम करे। (ब) नीपा को कोई ऐसा ग्रामसमूह या प्रखंड अपनाना चाहिए जहां शिक्षाकर्मी और लोक जुंबिश, दोनों कार्यक्रम जारी हैं ताकि वह शैक्षिक योजना और प्रबंध के सिलसिले में दोनों के सार्थक सहयोग को व्यावहारिक रूप दे सके। (स) अन्य राज्यों के हित में इन प्रयोगों की सफलताओं और असफलताओं को प्रचारित करने के लिए दोनों कार्यक्रमों की अंतराक्षेत्रीय विशिष्टताओं के एक गहन अध्ययन की सिफारिश की गई है। (द) ऐसे सभी प्रयासों की दक्षता और कारगुजारी में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रतिज्ञान एक अहम तत्व होना चाहिए। इसलिए अध्ययन की सिफारिश है कि नीपा जैसे संगठनों को निरंतर मूल्यांकन और समीक्षा के कार्यों में संलग्न किया जाए जिससे तकनीकी आगतों की प्राप्ति के अलावा आत्मनिरीक्षण और मनन की गुणवत्ता भी सुधरेगी।

4. 'बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता का अंतःजनपदीय विश्लेषण' (अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान पेरिस द्वारा प्रयोजित)

इस अध्ययन की डॉ. आर. गोविंद (वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष, विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा एकक, नीपा) और डॉ. एन.वी.वर्गीज (अध्येता, प्रादेशिक प्रणाली एकक, नीपा) में पूरा किया। यह शोध-अध्ययन 'विकासशील देशों में बुनियादी शैक्षिक सेवाओं की गुणवत्ता' के विषय पर अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान, पेरिस के सहयोग से नीपा द्वारा पूरी की जा चुकी एक महत्वपूर्ण परियोजना का अगला चरण था। अध्ययन पर खर्च हुए 47,000 रुपये की राशि 'बुनियादी शैक्षिक सेवाओं की गुणवत्ता' वाली परियोजना की बचत से प्राप्त हुई।

उद्देश्य

इस अनुवर्ती परियोजना का उद्देश्य पिछली शोध-परियोजना में संगृहित आंकड़ों का आगे विश्लेषण करना था। इसके लिए मध्यप्रदेश के पांच अलग-अलग जिलों के पांच इलाकों के बीच पाई जानेवाली भिन्नताओं के व्यष्टिस्तरीय विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित किया गया।

अध्ययन की बुनियादी मान्यता यह थी कि विद्यालय जिस व्यावहारिक संदर्भ में कार्यरत हों उसी में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता का विश्लेषण किया जाना चाहिए। इस चरण में परियोजना ने एक ही इलाके में स्थित विद्यालयों के शिक्षार्थियों की भिन्न-भिन्न उपलब्धियों पर केंद्रित आंकड़ों को आगे विश्लेषित करने का प्रयास किया। यह अध्ययन मध्यप्रदेश के पांच ऐसे चुनिंदा इलाकों में किया गया जो विकास के स्तरों को दृष्टि से भिन्न-भिन्न हैं। ये इस प्रकार हैं:

(अ) मांडला जिले का बैगाचक इलाका जो सबसे कम विकसित, आदिवासी इलाकों में एक है।

(ब) रीवा जिले का रीवा प्रखंड जो अल्पविकसित ग्रामीण क्षेत्रों में एक है।

(स) राजनांदगांव जिले का डूंगरगांव प्रखंड जो विकसित ग्रामीण इलाकों में एक है।

(द) ग्वालियर जिले का डबरा कस्बा जो अर्धनगरीय क्षेत्रों में एक है।

(य) इंदौर जिले का इंदौर नगर जो सबसे विकसित इलाकों में एक है।

इस अध्ययन के फलस्वरूप पांच परियोजना रिपोर्टें सामने आईं। प्रत्येक रिपोर्ट निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करती हैं: (अ) क्षेत्र और बुनियादी ढांचे के सामान्य विकास के संदर्भ में उसकी विशेषताएं, (ब) विद्यालय और उनमें मौजूद सुविधाएं, (स) प्रत्येक विद्यालय की रोजमर्रा की गतिविधियों का विवरण, (द) अध्यापन और अधिगम की प्रक्रिया तथा विद्यालय की शिक्षा के परिणामस्वरूप शिक्षार्थी की उपलब्धियों का विश्लेषण,

और (य) फौरी हस्तक्षेप के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए गुणवत्ता के सुधार की योजनाओं के लिए निहितार्थों का निश्चय।

प्रमुख निष्कर्ष

अध्ययन का प्रमुख निष्कर्ष यह है कि विभिन्न क्षेत्रों में हस्तक्षेपों के क्षेत्रों पर दिए जाने वाले जोर में भी भिन्नता का होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, बैगाचक में बुनियादी सुविधाओं और अध्यापक-प्रशिक्षण का महत्व अधिक है; रीवा प्रखंड में अधिक महत्व बुनियादी सुविधाओं और पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता का है; राजनांदगांव क्षेत्र में और नगरीय क्षेत्रों में प्रधानाध्यापक और विद्यालयों की गतिविधियों का आयोजन अधिक महत्वपूर्ण हैं। अधिकतम प्राथमिकता आंतरिक प्रबंध की देनी होगी। अधिगम के कुल समय में यथासंभव वृद्धि करने के लिए भारी प्रयास आवश्यक हैं। आंतरिकत प्रबंध की संरचनाओं और प्रक्रियाओं को मजबूत बनाना अधिगम के समय को बढ़ाने में बहुत सहायक हो सकता है।

5. भारत में अनुसूचित जातीय और गैर अनुसूघित जातीय जनसंख्या की साक्षरता के स्तरों की विषमताओं का जिलावार विश्लेषण

यह अध्ययन डॉ. वाई.पी. अग्रवाल (अध्येता, विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा एकक, नीपा) द्वारा 1,52, 796/- रुपये की लागत से पूरा किया गया।

उद्देश्य

अनुसूचित जातियों और अन्य वर्गों के बीच विषमताओं की जारी रखने वाले कारकों के उद्‌गम को छानबीन करना; अनुसूचित जातियों के विभिन्न समूहों के बीच साक्षरता-प्रसार के देशकालिक प्रतिमानों की पहचान करना; गैर-अनुसूचित आबादी के बीच समानताओं या असमानताओं की छानबीन करना; साक्षरता के स्तरों में अंतर को मापने के लिए एक उपयुक्त पद्धति का विकास करना; साक्षरता की दरों, विषमता के सूचकांकों और सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं के आपसी संबंधों की प्रकृति की पड़ताल करना; और शैक्षिक विकास के स्तरों की असमानताओं को यथासंभव कम करने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट नीतियां तैयार करना इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य थे।

निष्कर्ष

विभिन्न अनुसूचित जातियों के बीच शैक्षिक विकास के प्रतिमानों का विश्लेषण साफतौर पर दिखता है कि विभिन्न जातिसमूहों द्वारा शैक्षिक सुविधाओं और अन्य प्रोत्साहनों के उपयोग में पर्याप्त असमानता रही है। अंतराजातीय विषमताएं उतनी ही सुस्पष्ट हैं जितनी अंतःजातीय विषमताएं हैं। संरक्षणमूलक भेदभाव की तीखी आलोचना इसी संदर्भ में की जाती रही हैं। अध्ययन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य इस परिकल्पना की स्पष्ट पुष्टि करते हैं कि कुछ जातियों ने दूसरों की अपेक्षा अधिक लाभ उठाए हैं। इस कारण अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास की नीतिगत अनिवार्यताओं पर दो अहम दृष्टियों से विचार करना पड़ेगा। इनमें एक का संबंध अंतराजातीय भेदों से है तो दूसरे का संबंध अनुसूचित जातियों और अन्य समूहों के बीच पाए जानेवाले भेदों से है। कोई भी नीति अगर एक पर ध्यान देती है और दूसरे की उपेक्षा करती है तो वह समता और सामाजिक न्याय के लक्ष्य को पाने में असफल रहेगी।

अनुसूचित जातियों के अंदर भी शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के स्तरों के अनुसार उपसमूहों की पहचान की जानी चाहिए। प्रत्येक उपसमूह की अलग-अलग परिमाण में लाभ प्राप्त होने चाहिए।

विकास के एक न्यूनतम स्तर को पहुंच चुकी जातियों को अनुसूची से बाहर करने की प्रक्रिया पर भी गंभीरता से विचार होना चाहिए। अन्यथा अंतर समूह विषमताएं जारी ही रहेंगी। कुछ लोगों ने सुझाव दिए हैं कि प्रोत्साहन और अन्य संबद्ध लाभ प्रदान करने के लिए परिवार को आधार मानना चाहिए।

अनेक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक सीमारेखा का निर्धारण करना आवश्यक है चाहे उसकी प्रकृति कुछ भी हो और उस सीमा के बाहर लाभों का उपलब्ध होना अपने-आप रूक जाएगा।

सबसे वंचित और कम सांख्या वाली जातियों की समस्याएं बड़ी और बेहतर स्थिति वाली जातियों के मुकाबले एकदम भिन्न होती हैं। इसलिए जरूरी है कि संरक्षणमूलक भेदभाव के रूप में प्रथमोक्त को द्वितीयोक्त के बराबर मानने की नीतियां न अपनाई जाएं।

वंचित समूहों और खासकर कम संख्या वाली जातियों के उत्थान की रणनीतियां तैयार करते समय उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होगा।

अनुसूचित जातियों संबंधी मौजूदा नीतियों में यथार्थ प्रभाव का आकलन किए बिना अधिक से अधिक रियायतें और प्रोत्साहन देने पर अधिक जोर दिया जाता रहा है। इस विश्लेषण की व्याप्ति कम अवश्य है मगर इसके परिणाम दिखाते हैं कि अनुसूचित जातियों के साथ अनेक दशकों तक प्रोत्साहन व्यवहार किए जाने के बावजूद अनुसूचित मानी जानेवाली जातियों के अंदर भी व्यापक असमानताएं मौजूद हैं।

अंतिम बात, यह पाया गया है कि शिक्षा संबंधी बुनियादी ढांचे की पर्याप्त आपूर्ति का उनके भरपूर उपयोग से संबंधित होती आवश्यक नहीं है। बुनियादी ढांचे का प्रावधान सुलभता में वृद्धि की केवल आवश्यक दशा होती है, पर्याप्त दशा नहीं होती। दलित जातियों में शिक्षा की मांग की जगाना भी उतनी ही अहमियत रखता है। इसलिए ऐसे कदम उठाने जरूरी हैं कि सरकारी संगठनों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को आधारभूत स्तर पर मांग के सृजन में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

6. 'महिला महाविद्यालयों की प्रधानाचार्याओं की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं की पहचान'

प्रस्तुत अध्ययन डॉ. (श्रीमती) जया इंदिरेसन (वरिष्ठ अध्येता, उच्च शिक्षा एकक, नीपा) ने एस. एन. डी. टी. विश्वविद्यालय, बंबई के सहयोग से 10,000 रुपये की अनुमानित लागत से पूरा किया।

उद्देश्य

अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित थेः प्राथमिकता के उन क्षेत्रों की पहचान करना जिनमें प्रधानाचार्याएं प्रशिक्षण पाना चाहती हैं; योजना और प्रबंध के विभिन्न पक्षों के संबंध में दक्षता की कमी का आकलन करना; छात्राओं की खास विशेषताओं का निरूपण करना; महिला महाविद्यालयों के प्रशासन में प्रधानाचार्याओं द्वारा महसूस की जा रही समस्याओं की जांचपड़ताल करना; और महिला प्रशासकों द्वारा महसूस की जा रही विशिष्ट समस्याओं का विशिष्ट समस्याओं का विश्लेषण करना।

प्रमुख निष्कर्ष

प्राप्त प्रत्युत्तरों के आधार पर विभिन्न सूचीबद्ध क्षेत्रों में प्रशिक्षण के केंद्रीय पक्षों की पहचान की गई। छात्राओं के रिकार्डों, वित्त, कार्मिकों की पुरस्कृत करने आदि के प्रबंध में संगणकों का व्यवहार एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत महत्वपूर्ण नजर आता है। पहचाने गए दूसरे प्रासंगिक क्षेत्रों में महिलाओं की बेरोजगारी, उद्यमशीलता, महिला प्रशासकों की भूमिका और अस्मिता, दबाव का गतिशास्त्र और मुकद्दमेबाजी, छात्राओं को आकांक्षाओं और आत्मधारणा के मुद्दे शामिल हैं। काम का प्रवाह और पोर्ट फोलियो विश्लेषण, लागत-प्रभाविता का विश्लेषण, पदस्थिति का परिदृश्य और आंकड़ा-भंडार जैसे तकनीकी पक्षों के बारे में ज्ञान और प्रशिक्षण की प्राप्ति को भी प्रशिक्षण के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में पहचाना गया।

प्रधानाचार्याओं ने ऐसे संकेत दिए कि छात्राओं से संबंधित अकादमिक, सामाजिक और व्यावसायिक पहलुओं पर कुछ विषयों को शामिल करना प्रासंगिक होगा। इससे इस तथ्य

की स्वीकृति का संकेत मिलता है कि छात्राओं की कुछ विशेष समस्याएं अवश्य होती हैं।

प्रधानाचार्याएं प्रशासकों के रूप में जिन समस्याओं का और महिला प्रशासकों के रूप में जिन विशेष समस्याओं का सामना करती हैं उनकी पहचान मुक्त प्रत्युत्तरों वाले प्रश्नों पर प्राप्त प्रत्युत्तरों का अंतःवस्तु-विश्लेषण करके की गई। मोटेतौर पर इस समस्याओं की काम से संबद्ध, मूल्यों से संबद्ध, लिंग से संबद्ध और स्वयं से संबद्ध श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया।

प्रशिक्षण संबंधी निहितार्थ

प्रशिक्षण देने योग्य पहलुओं के बारे में कमियों की दृष्टि से प्रशिक्षण की आवश्यकताओं की पहचान की गई। महिला-शिक्षा के सिद्धांतों की ध्यान में रखकर दो से तीन सप्ताह तक के दो प्रतिरूप विकसित किए गए। इनमें एक का संबंध प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण से और दूसरे का संबंध महिला महाविद्यालयों की प्रधानाचार्याओं के प्रशिक्षण से है।

7. कृषि विज्ञान के स्नातकों के लिए रोजगार के अवसर : राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का लागत-लाभ विश्लेषण (नीपा की सहायता योजना के अंतर्गत)

इस अध्ययन को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर बी.सी. मेहता ने दिसंबर 1992 में 63,200/- रुपये की लागत से पूरा किया।

उद्देश्य

अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार थे : (अ) विश्वविद्यालय में शिक्षा की विभिन्न धाराओं और स्तरों पर आनेवाली निजी और सामाजिक लागतों के घटकों का परिमाणीकरण और विश्लेषण करना; (ब) कृषि विज्ञान की शिक्षा के मांग पक्ष का अध्ययन करना ताकि (1) मांग के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान और (2) विश्वविद्यालय के स्नातकों के आय संबंधी परिदृश्यों की तैयारी की जा सके; (स) कृषिविज्ञान की शिक्षा की लागत-प्रभाविता का अध्ययन करना; (द) कृषि स्नातकों की उर्ध्व और क्षैतिज गतिकी का विश्लेषण; (य) चालू वर्ष में कृषि विज्ञान के छात्रों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण करना ताकि प्रवेश नीति का मूल्यांकन किया जा सके और भारत में आर्थिक विकास के सामाजिक उद्देश्यों की पाने के लिए उनके निहितार्थों का पता लगाया जा सके; और (र) इसकी छानबीन करना कि क्या कृषि विज्ञान को शिक्षा का पुनर्विन्यास सामाजिक प्रतिफल में वृद्धि कर सकता है।

निष्कर्ष और सिफारिशें

विश्वविद्यालयों में प्रवेश का प्रतिमान अपेक्षाकृत समृद्ध वर्गों के पक्ष में बहुत अधिक झुका हुआ है। कमजोर वर्गों के छात्र विद्यालयी शिक्षा पाकर इस हालत में आ सकें कि वे कृषिविज्ञान की विभिन्न शाखाओं में प्रवेश पाने की कोशिश कर सकें–इसके लिए राज्य सरकार को कारगर कदम उठाने होंगे। आशा है कि उनके लिए प्रतिफल की दर काफी अधिक होगी क्योंकि अवसर की लागत कम होगी। यह देखकर दुख होता है कि आरक्षणों के बावजूद कमजोर वर्ग पर्याप्त संख्या में इस धारा में प्रवेश नहीं कर पाते हालांकि इस स्थिति में हाल के वर्षों में थोड़ा सा सुधार हुआ है।

चूंकि अधिकांश और खासकर दुग्धविज्ञान और परास्नातक और शोध अध्ययनों के छात्र अपेक्षाकृत समृद्ध वर्गों से आते हैं, इसलिए अनुदान कम किए जा सकते हैं। चूंकि कुछ विषयों में सामाजिक प्रतिफल की दर के कम होने के बावजूद निजी प्रतिफल की घर काफी अधिक है, इसलिए संस्थागत लागत का आंशिक बोझ छात्र या उसके अभिभावकों पर डाला जा सकता है।

शुल्कों को छोड़कर दूसरी निजी लागतों में वृद्धि हुई है। छात्रावासों और पुस्तकालयों के उचित प्रबंध के द्वारा इसे कम करने के तरीके निकालने होंगे। छात्रवृत्तियों में मुद्रास्फीति की दर के अनुसार वृद्धि नहीं होती।

प्रतिफल-दर का विश्लेषण अनेक दोषों से ग्रस्त होता है। **मसलन** शैक्षिक नीतियों और विशेषकर शुल्क राशियों और **छात्रवृत्तियों** के बारे में नीतियों का विकास करते समय **निजी** और साथ ही सामाजिक प्रतिफल की दरों का उपयोग **सावधानी** के साथ किया जाना चाहिए। ध्यान रखें कि **संस्थागत** प्रतिफल की दर को औसत मान होती है और वह **समाज** की सभी वर्गों की नुमाइंदगी नहीं करती। यह अनेक **सरलीकृत** मान्यताओं पर आधारित होती है। जैसे मुद्रा की **समान** और स्थिर सीमांत उपयोगिता, जोखिम के तत्व की **महत्वहीनता**, बाजारों में पूर्ण गतिशीलता को स्थिति आदि। **इस प्रकार** छात्रों के विभिन्न समूहों को विभिन्न प्रतिफल-दरों **की आशा** रहती है। इस कारण औसत निजी प्रतिफल-दर **को शिक्षा** की मांग की अधिक से अधिक एक आवश्यक **दशा माना** जा सकता है और यह निश्चित ही उसकी **पर्याप्त** दशा नहीं है।

ध्यान दें कि जब निजी प्रतिफल की दर ऊंची होती है और **शिक्षा पर** भारी अनुदान दिए जाते है तब भी कमजोर वर्ग **इन अवसरों** का लाभ नहीं उठाते। समाज वैज्ञानिकों और **सामाजिक** कार्यकर्ताओं को इसके कारण पहचानने होंगे। **एक कारण** यह है कि आरंभिक निजी लागत बहुत अधिक **और एकमुश्त** होती है, लागत के निकलने का काल बहुत **लंबा होता** है और परिवेश कमजोर वर्गो के लिए काफी **अजनबी** होता है। **इस** कारण कमजोर वर्ग अगर पूरी सूचना **रखते भी हैं तो भी** इतने लंबे समय तक जोखिम उठाने की **हालत** में नहीं होते।

इन सभी कारणों से निजीकरण और छात्रों से पूरी लागत **वसूल करने को भी** एक न्यायोचित, यथार्थवादी और कारगर **नीतिगत** विकल्प नहीं माना जा सकता जिसके सुझाव नई **आर्थिक** नीति के अनेक समर्थक देते हैं। अगर शुल्कों को **संस्थागत** आवर्ती लागत के लगभग एक प्रतिशत के वर्तमान **स्तर से** अधिक किसी स्तर तक बढ़ाने हों तो भी यह **बढ़ोत्तरी** केवल सीमांत हो सकती है और केवल चरणों में **की जा सकती** है।

वित्त की सुलभता को उदार ऋण-नीतियों के द्वारा आसान और व्यापक बनाना होगा। इसके लिए एक स्वतंत्र शैक्षिक वित्त आयोग स्थापित करने का सुझाव दिया गया है।

विश्वविद्यालयों में दस्तावेजों के रखरखाव को चुस्त बनने के लिए फौरी कदम उठाने की आवश्यकता है। संपत्ति संबंधी जो विवाद पिछले पांच साल से लटका पड़ा है वह विश्वविद्यालय के कार्यकलाप पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। राज्य सरकार को चाहिए कि इस काम को गंभरीता से ले।

इस समय जारी अध्ययन

1. विद्यालय मानचित्रण का अध्ययन

विद्यालय मानचित्रण की परियोजना के लिए ४.८३ लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई। इस अध्ययन को प्रो. एम.एम. कपूर (वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष, प्रादेशिक प्रणाली एकक) चला रहे हैं। परियोजना के मुख्य उद्देश्य ये हैं: विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों में निश्चित मानदंडों और उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं के विशेष संदर्भ में स्थितिपरक योजना की विद्यमान प्रक्रियाओं और पद्धतियों का आलोचनात्मक अध्ययन करना; क्षेत्र में काम कर रहे स्टाफ के मार्गदर्शन के लिए विद्यालय-मानचित्रण की एक हस्तपुस्तिका तैयार करना।

यह अध्ययन केवल विद्यालय स्तर और सामान्य शिक्षा तक सीमित रहेगा। विद्यमान पद्धतियों और प्रक्रियाओं के आलोचनात्मक अध्ययन के लिए इसमें केवल चुने हुए प्रतिनिधि राज्यों की ही शामिल करने का प्रस्ताव है। कुछ चुने हुए राज्यों के नगरीय क्षेत्रों में नगर-योजना के एक भाग के रूप में विद्यालय-मानचित्रण के लिए विशेष अध्ययन किए जाएंगे।

परियोजना में कार्यक्रम सलाहकार समिति की सिफारिश पर दिल्ली और अरुणाचलप्रदेश को भी शामिल किया गया। मिजोरम और तमिलनाडु की प्रखंड योजनाओं की अंतिम रूप दिया गया तथा अरूणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और असम से ऐसी योजनाएं प्राप्त की गईं।

राज्यवार मसविदा रिपोर्टें और प्रखंड-योजनाएं असम, अरुणाचलप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मिजोरम, राजस्थान और तमिलनाडु से प्राप्त हो चुकी हैं। इसके अलावा उड़ीसा, दिल्ली और हरियाणा से राज्यवार रिपोर्टें और विशेषज्ञ प्रखंड-योजनाएं भी प्राप्त हुई हैं। उत्तरप्रदेश ने केवल प्रखंड-योजना भेजी है जबकि बंगाल और जम्मू-कश्मीर ने कोई जवाब नहीं दिया है। इनमें असम, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली की रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक और मिजोरम की प्रखंड-योजनाओं को भी अंतिम रूप दिया जा चुका है।

अन्य राज्यों से मिली राज्यवार मसविदा रिपोर्टें और प्रखंड-योजनाएं अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया में हैं। शेष काम को पूरा करने के लिए उड़ीसा और उत्तरप्रदेश तथा संघीय क्षेत्र दिल्ली की रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया जाना है।

2. द्वितीय अखिल भारतीय शैक्षिक प्रशासन सर्वेक्षण परियोजना

यह परियोजना 19.84 लाख रुपये के बजट के साथ मंजूर की गई थी। इसे प्रो. एम.एम कपूर (वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष, प्रादेशिक प्रणाली एकक) संचालित कर रहे हैं।

सभी राज्यों, संघीय क्षेत्रों और केंद्र में मौजूदा प्रणाली, प्रक्रियाओं और संरचना का निदान करने के लिए तथा उनको राष्ट्रीय शिक्षा नीति की परिकल्पना के अनुसार योजना और प्रबंध की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने के लिए शैक्षिक प्रशासन का एक व्यापक सर्वेक्षण करना इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य है।

यह सर्वेक्षण सभी राज्यों और संघीय क्षेत्रों तथा भारत सरकार की भी समेटेगा। शैक्षिक प्रशासन के सभी क्षेत्र और स्तर इसके दायरे में आएंगे।

इसके लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने 29 अगस्त 1992 की अपनी बैठक की और सिफारिश की कि सर्वेक्षण की पूरा करने का काम दो चरणों में बांट दिया जाए। पहले चरण में राज्यवार रिपोर्टों, केस अध्ययनों, केंद्र की रिपोर्ट और एक चुनिंदा संदर्भ सूची को तैयार करने और अंतिम रूप देने के काम किए जा सकते हैं। दूसरे चरण में राष्ट्रीय स्तर की रिपोर्टों की तैयार और प्रकाशित किया जाएगा। तीन परियोजना अध्येताओं या सह-अध्येताओं और तीन टंककों के मौजूदा स्टाफ के साथ परियोजना के पहले चरण को पूरा करने के लिए समिति ने कुल 54 व्यक्ति-माह की सिफारिश की है।

सर्वेक्षण का काम अब अपने अंतिम चरण में है। 22 राज्यों और संघीय क्षेत्रों से रिपोर्टें मिल चुकी हैं जिनमें पंद्रह को रिपोर्टों की अंतिम रूप दिया जा चुका है। इनके अलावा चार राज्यों या संघीय क्षेत्रों की आंशिक रिपोर्टें मिली हैं। लेकिन बाकी छः राज्यों या संघीय क्षेत्रों अर्थात आंध्रप्रदेश, बिहार, जम्मू-कश्मीर, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल और पांडिचेरी की प्रतिक्रिया उत्साहवर्द्धक नहीं रही है।

केंद्र स्तर की रिपोर्ट तैयार करने का काम शुरू किया जा चुका है। एक परामर्शदाता की पहचान की गई है और उसे चार माह के अंदर निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार रिपोर्ट तैयार करने का काम अनुबंध के आधार पर दिया जा चुका है।

3. लातीनी अमरीका में अनौपचारिक शिक्षा की योजना और प्रबंध : भारत के लिए इसके सबक और निहितार्थ

इस परियोजना को 1,46,200 रुपये की राशि के साथ स्वीकृति दी गई। डॉ. अंजना मंगलागिरि (अध्येता, अंतर्राष्ट्रीय एकक) यह अध्ययन कर रही हैं।

अध्ययन के उद्देश्य इस प्रकार हैं—लातीनी अमरीका में अनौपचारिक शिक्षा की योजनाओं की संरचना और प्रक्रिया की छानबीन करना, इन कार्यक्रमों के प्रबंध और योजना की छानबीन करना, और शिक्षा के क्षेत्र में अंतःक्षेत्रीय समझदारी और सहयोग को बढ़ाने के मकसद से तुलनात्मक शिक्षा शास्त्र के विकास के लिए आवश्यक आगतों की व्यवस्था करना।

यह अध्ययन लातीनी अमरीका में अनौपचारिक शिक्षा की योजना और प्रबंध की रणनीतियों की पड़ताल करता है और इन रणनीतियों पर भारत में दिए जा रहे जोर की रोशनी में विकेंद्रीकरण और समुदाय की भागीदारी को अपना विशेष संदर्भ बनाता है। लातीनी अमरीका का अनुभव दिखाता है कि वहां भारत की तरह अनौपचारिक शिक्षा को एक शैक्षिक कार्यक्रम नहीं माना जाता बल्कि उसे संरचनाबद्ध और मानकीकृत औपचारिक शिक्षाप्रणाली का एक समग्र विकल्प दिया जाता हैं। भारत में अपनाए जा रहे शीर्ष-निर्धारण के दृष्टिकोण के विपरीत लातीनी अमरीका का दृष्टांत विकेंद्रीकरण, जनता की भागीदारी, आत्मीकरण और उसके बाद जनता के अधिकारों के लिए उसकी लामबंदी के कुछ तत्वों से युक्त दिखाई पड़ती है। स्वयं में इस कार्यक्रम पर जोर देने की जगह लातीनी अमरीकी दृष्टांत योजना और प्रबंध की प्रक्रियाओं पर जोर देता है जिससे सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं।

4. शिक्षा संस्थाओं में स्वायत्तता का प्रबंध : स्वायत्त महाविद्यालयों का अध्ययन

स्वायत्त महाविद्यालयों में प्रबंध से संबंधित इस परियोजना के लिए 1,52,100/- रुपये की राशि स्वीकार की गई है। इस परियोजना को डॉ. (श्रीमती) के. सुधाराव (अध्येता, उच्च शिक्षा एकक, नीपा) चला रही हैं।

इस परियोजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं : स्वायत्तता पानेवाली संस्थाओं में स्वायत्तता के व्यवहार की विधियों का अध्ययन करना; महाविद्यालयों की स्वायत्तता के संरचनागत और प्रकार्यात्मक प्रश्नों का विश्लेषण करना; स्वायत्तता के बारे में अध्यापकों और छात्रों के विचारों का विश्लेषण करना; उत्कृष्ट कार्यकलाप से प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े कार्यभारों की पहचान करना; शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार पर स्वायत्तता के प्रभाव के अध्ययन करना; शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए परिवर्तनों का आरंभ करने में स्वायत्तता का व्यवहार करने के बारे में स्वायत्त महाविद्यालयों द्वारा महसूस की जा रही समस्याओं का अध्ययन करना; अंत में, उच्च शिक्षा संस्थाओं में स्वायत्तता के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्वायत्त महाविद्यालयों के लिए आवश्यक प्रबंधकीय सहायता की पहचान करना।

सोद्देश्यात्मक प्रतिदर्शन की विधि अपनाकर और दस्तावेज विश्लेषण की तकनीकों द्वारा तथा प्रबंध-विशेषज्ञों, उच्च शिक्षा निदेशकों, कुलपतियों, संस्थाप्रमुखों, स्वायत्त और अस्वायत्त महाविद्यालयों के अध्यापकों और छात्रों से विचार विमर्श करके सभी श्रेणियों की स्वायत्त संस्थाओं से आंकड़े जमा करना और प्रश्नावली के विश्लेषण द्वारा स्वायत्तता के विभिन्न पक्षों का विस्तृत अध्ययन करना भी इस परियोजना की योजना में शामिल हैं। आंध्रप्रदेश के 6 और तमिलनाडु के 13 महाविद्यालयों से तथा राजस्थान राजकीय महाविद्यालय, अजमेर, राजकीय महाविद्यालय, कोटा और राजकीय महाविद्यालय, बीकानेर से आंकड़े जमा किए जा चुके हैं। आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है और समीक्षाकार्य भी प्रगति पर है।

यह अध्ययन अब अपने अंतिम चरण में है।

5. शिक्षा में संसाधनों का प्रभावी उपयोग : केस अध्ययन

संसाधनों के प्रभावी उपयोग संबंधी यह परियोजना 1,19,100/- रुपये की राशि के साथ मंजूर की गई। डॉ.जे.बी.जी. तिलक (वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष, शैक्षिक वित्त एकक) इस परियोजना के निदेशक हैं।

एक तरफ शिक्षा की संस्थागत लागत और दूसरी तरफ संस्था के उत्पादों के आधार पर शिक्षा की लागत-प्रभाविता का विश्लेषण करना; कालक्रम में किसी विद्यालय में विभिन्न कार्यों के लिए संसाधनों के आवंटन और उपयोग के प्रतिमान का विश्लेषण करना; और आवंटन या उपयोग के प्रतिमानों में भिन्नताओं की व्याख्या करनेवाले कारकों की जांचपड़ताल करना इस अध्ययन के उद्देश्य हैं।

यह अध्ययन एक जिले में संकलित प्राथमिक प्रतिदर्शी आंकड़ों पर आधारित होगा। अध्ययन के लिए अधिकांश आंकड़े जमा किए जा चुके हैं और संगणकों पर उनका विश्लेषण किया जा चुका है। रिपोर्ट लिखने का काम प्रगति पर हैं।

6. उत्तरप्रदेश में सबके लिए बुनियादी शिक्षा

परियोजना 'उत्तरप्रदेश में सबके के लिए बुनियादी शिक्षा' के बारे में नीपा के परामर्शदाता श्री एस.सी. बेहड़ ने एक प्रारंभिक दस्तावेज तैयार किया था।

नीपा के संकाय सदस्यों ने शिक्षा विभाग, उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा तैयार संशोधित परियोजना दस्तावेज को जांचापरखा। उसके आधार पर संकाय ने नीपा तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग में हुई बैठकों में आवश्यक संशोधनों और सुधारों के सुझाव पेश किए। बाद में सभी पक्षों से प्राप्त सुझावों के प्रकाश में योजना के दस्तावेज की विश्व बैंक के विचारार्थ अंतिम रूप दिया गया। नीपा संकाय के सदस्य इन बैठकों और कार्यशालाओं में शामिल हुए।

विश्वबैंक के एक मूल्यांकन-पूर्व दल ने निम्नलिखित क्षेत्रों के बारे में बैठकों और कार्यशालाओं की एक श्रृंखला का आयोजन किया :

> जिला योजनाएं, विद्यालय निर्माण, परियोजनाओं की वित्तव्यवस्था, विद्यालयसंकुल, प्रबंध सूचनाप्रणाली, शोध और निगरानी की क्षमता का मूल्यांकन, अनौपचारिक शिक्षा, पाठ्यपुस्तक परियोजना और महिला शिक्षा।

7. भारत में शैक्षिक विकास की क्षेत्रीय विषमताएं : आधारभूत स्तर पर समाज-कल्याण के संदर्भ में शैक्षिक विषमताओं का अन्वेषण

आधारभूत स्तर पर क्षेत्रीय विषमताओं से संबंधित यह परियोजना 3,48,840/- रुपये की राशि के साथ स्वीकृत की गई। परियोजना दल में परियोजना के निदेशक डॉ.एस.सी. नुना, परियोजना सहायिका सुश्री वासवी सरकार और परियोजना मानचित्रकार श्री जमालुद्दीन फारूकी हैं।

विद्यालय के स्तर पर शैक्षिक विकास की विषमताओं का विश्लेषण करना और इन विषमताओं में कमी लाने के प्रयासों को दिशा देने के लिए व्याख्यात्मक प्रणाली का विकास करना; शिक्षा और विकास के दूसरे क्षेत्रों के अंतःसंबंधों का विश्लेषण करना; और आधारभूत स्तर पर समन्वित योजना का एक ढांचा तैयार करने के लिए विकास-प्रदाय की मौजूदा व्यवस्था का मूल्यांकन करना इस अध्ययन के उद्देश्य हैं।

यह अध्ययन पांचवें अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण से प्राप्त जिलास्तरीय आंकड़ों और परिवारों के सर्वेक्षण द्वारा देश के 15 जिलों से प्राप्त प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित है। अध्ययन अब अपने अंतिम चरण में है।

8. शिक्षा के लिए संगणक-आधारित योजना (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग द्वारा प्रायोजित)

परियोजना 'शिक्षा के लिए संगणक-आधारित योजना' को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग ने 31,21,700/- रुपये की राशि के साथ स्वीकृति दी है।

संगणक-आधारित शैक्षिक योजना (कोप परियोजना) के बारे में हिमाचलप्रदेश, राजस्थान और संघीय क्षेत्र दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया था ताकि वे संगणक-आधारित शैक्षिक योजना की प्रणाली से परिचित हो सकें।

शिक्षा निदेशालय, दिल्ली में इस प्रणाली के प्रदर्शन के बाद संघीय क्षेत्रों में इस प्रणाली को लागू करने का फैसला किया गया। इसके लिए उपनिदेशकों, क्षेत्रीय अधिकारियों और राज्यों के संगणक-आधारित शैक्षिक योजना प्रकोष्ठों के कार्मिकों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया है। आंकड़ा संग्रह के फार्म छापे जा चुके हैं और दिल्ली के शैक्षिक जिलों में आवश्यक हार्डवेयर लगाए जा चुके हैं।

Education
Marg,
D-9373
5-12-96

इटावा (उत्तरप्रदेश) और रांची (बिहार) के लिए आंकड़ा-भंडार तैयार हो चुके हैं। रांची जिले के आंकड़ा-भंडार का बिहार शिक्षा परियोजना में व्यापक उपयोग हो रहा है।

9. सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षा की निगरानी के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्शी सर्वेक्षण, 1991-92 (शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित)

परियोजना 'सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षा की निगरानी के लिए राष्ट्रीय प्रतिदर्शी सर्वेक्षण' को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया है। इसे प्रो. एम. एम.कपूर (वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष, प्रादेशिक प्रणाली एकक) संचालित कर रहे हैं।

अध्ययन के लिए 23.96 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षा की उपलब्धियों पर निगरानी रखने के लिए विद्यालयों में कक्षा 5 तक की या अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों में समकक्ष शिक्षा पूरी करके अर्थात 11-13 आयुवर्ग के बच्चों से संबंधित आंकड़े जमा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतिदर्शी प्रारूप का विकास करना; तथा राष्ट्र, राज्यों और संघीय क्षेत्रों के स्तर पर इस प्रतिदर्शी प्रारूप के आधार पर आंकड़ों का संग्रह, संकलन और विश्लेषण करना इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य हैं।

25 राज्यों और संघीय क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर एक प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की गई और उसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग और परियोजना सलाहकार समिति को भेजा गया।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक बैठक में सार्वभौम प्रारंभिक शिक्षा की निगरानी के अनेक सूचकों पर लिखे गए एक आलेख पर विचार किया गया। 32 राज्यों और संघीय क्षेत्रों के लिए सार्वभौम प्रारंभिक शिक्षा की निगरानी में प्रयुक्त अनके सूचकों (सकल नामांकन अनुपात, प्रवेश की दर, पूर्णता की दर, कक्षावार प्रतिधारण की दर) पर 5 तालिकाएं तैयार की गईं और उनको मंत्रालय भेजा गया।

शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से सलाह-मशिवरा करके और गहन विचारविमर्श के आधार पर इस परियोजना के दूसरे चरण के लिए एक मसविदा परियोजना प्रस्ताव तैयार किया गया और उसे स्वीकृति के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजा गया।

10. शैक्षिक प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन अध्ययन (शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित)

परियोजना 'शैक्षिक प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन-अध्ययन' शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 6,72,000/- रुपये की लागत के साथ स्वीकृत की गई है। परियोजना के निदेशक डॉ. एम. मुखोपाध्याय, सह-अध्येता श्रीमती उषा आयंगर और परियोजना सहायक श्री जयदेवन इस परियोजना दल के सदस्य हैं।

परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित का अध्ययन करना है: विद्यालयों में संचार माध्यमों की सुविधाओं, जैसे—रेडियो और आडियो कैसेट रिकार्डर, टेलीविजन और वीडियो कैसेट प्लेयर की उपलब्धता, विद्यालय में संचार सुविधाओं की उपलब्धता की अवधि, संचार की सुविधाएं देनेवाली योजनाएं; संग्राहक सेटों के व्यवहार की शर्तें और काम की दशाएं; विद्यालयों में इन सेटों के लगाने के स्थान; समयसारणी में की गई व्यवस्था; संचार सुविधाओं के उपयोग से अध्यापकों का परिचय; कार्यक्रम देखने और उनका उपयोग करने की बारंबारता और विधि आदि; सेटों का रखरखाव; बिजली, मरम्मत और बदलाव की व्यवस्था; कार्यक्रमों पर छात्रों और अध्यापकों की प्रतिक्रिया का सामान्य आकलन; प्रासंगिकता, गुणवत्ता, उपयुक्तता आदि का आकलन।

अध्ययन अब अपने अंतिम चरण में है।

11. राष्ट्रीय ग्रामीण प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति का मूल्यांकन-अध्ययन (शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित)

राष्ट्रीय ग्रामीण प्रतिभा खोज की योजना की यह मूल्यांकन

परियोजना स्वीकृत की गई। इस परियोजना दल में डॉ. के. जी. विरमानी, डॉ. (श्रीमती) कुसुम के. प्रेमी और सुश्री वाई. जोसेफीन शामिल हैं।

राज्यों और उनके विभिन्न जिलों में इस योजना के उपयोग की सीमा का पता लगाना; पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों और गैर अनुसूचित जातियों के मुकाबले अनुसूचित जातियों और जनजातियों द्वारा इसके उपयोग की सीमा का पता लगाना; लाभार्थियों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमियों का विश्लेषण करना; प्रतिभा की पहचान के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाई जा रही विधियों की आलोचनात्मक समीक्षा करना और चयन की पद्धति की वैधता का अध्ययन करना; योजना में निर्धारित प्रबंधकीय संरचना का और उसके वास्तविक व्यवहार का भी आलोचनात्मक मूल्यांकन करना और क्रियान्वयन की बाधाओं की पहचान करना; छात्रवृत्तियों के बांटने की कार्यपद्धति का अध्ययन करना और उसे चुस्त बनाने के उपाय सुझाना; योजना के लाभार्थियों की शैक्षिक प्रगति पर योजना के प्रभाव का अध्ययन करना; और विशेषकर नवोदय विद्यालयों की स्थापना के संदर्भ में योजना की प्रासंगिकता का अध्ययन करना।

प्रतिदर्शी प्रारूप में अध्ययन के लिए 10 राज्य और संघीय क्षेत्र चुने गए हैं। तीन प्रश्नावलियां तैयार की गई हैं जिनमें राज्यस्तरीय अधिकारी, विद्यालय के प्रधानाध्यापक और छात्रवृत्ति पानेवाले लाभार्थी के लिए एक-एक प्रश्नावली है। इन साधनों के निरूपण या विकास के लिए प्रारंभिक कार्य प्रगति पर है। पिछले पांच वर्षों अर्थात 1985-86 से 1989-90 तक छात्रवृत्तियों के उपयोग पर इसी काम के लिए तैयार दो प्रपत्रों की सहायता से आंकड़े जमा करने का काम जारी है। मेघालय से सारे आंकड़े पहले ही मिल चुके हैं और मेघालय, उड़ीसा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तरप्रदेश से राष्ट्रीय ग्रामीण प्रतिभा छात्रवृत्ति के लाभार्थियों के चयन के लिए अपनाई जानेवाली कार्यपद्धतियों पर आंकड़े प्राप्त हो चुके हैं।

12. भारतीय विश्वविद्यालयों का वित्तीय प्रबंध (नीपा सहायता योजना के अंतर्गत)

परियोजना 'भारतीय विश्वविद्यालयों का वित्तीय प्रबंध' को नीपा सहायता योजना के अंतर्गत 48,000/- रुपये की राशि के साथ स्वीकृत दी गई। यह अध्ययन डा.मालती सोमैया, भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर द्वारा किया जा रहा है।

भारतीय विश्वविद्यालयों के वित्तीय प्रकार्यों के बदलते संदर्भ और आयामों को उसके अभिप्राय, अंतर्तत्व, सांगठनिक स्थिति और व्यवस्था के संबंध से समझना; वे विश्वविद्यालय जो बाधाओं और सीमाओं के अंदर अपने वित्त का प्रबंध करते हैं उनकी पहचान करना; उस सांगठनिक ढांचे की आलोचनात्मक छानबीन करना जिसके अंदर संस्था के स्तर पर वित्तीय संसाधनों का प्रभावी उपयोग होता है; महाविद्यालय या विभाग आदि जैसी इकाई के स्तर पर वित्तीय प्रत्यायोजन की प्रणाली तथा नीतिगत और व्यावहारिक दिशाओं के विभिन्न आपसी संबंधों की छानबीन करना; और वित्तीय प्रबंध संबंधी कुशलताओं की प्राप्ति के दृष्टिकोण से विश्वविद्यालयों के विभिन्न कार्मिकों के प्रशिक्षण के क्षेत्रों की पहचान करना।

यह अध्ययन इस समय अपने अंतिम चरण में है।

13. तमिलनाडु में शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रबंध (नीपा सहायता योजना के अंतर्गत)

शैक्षिक प्रौद्योगिकी के प्रबंध पर इस परियोजना को अगस्त 1989 में नीपा की सहायता योजना के अंतर्गत 63,000/- रुपये की राशि के साथ स्वीकृति दी गई थी। इस परियोजना की डॉ.सी. सुब्रमण्य पिल्लई (प्रोफेसर और अध्यक्ष, शिक्षाशास्त्र विभाग, कामराज विश्वविद्यालय मदुरै) संचालित कर रहे हैं।

तमिलनाडु में उच्च शिक्षा के स्तर पर रेडियो, टेलीविजन और वीडियो प्रौद्योगिकियों के हार्डवेयर और साफ्टवेयर पक्षों के संदर्भ में अभी तक हो चुकी प्रगति की समीक्षा करना;

संकाय के सदस्यों के लिए ये प्रौद्योगिकियां कितनी उपयोगी रही हैं और उन्होंने इनका कितना उपयोग किया हैं, इसका पता लगाना; इन प्रौद्योगिकियों के प्रबंध में अगर कुछ कमियां रह गई हों तो उनको दूर करना; और शैक्षिक प्रौद्योगिकी संबंधी अध्ययनों के कारगर प्रबंध के लिए उपयुक्त सिफारिशें प्रस्तुत करना इस अध्ययन के उद्देश्य हैं।

आंकड़ों का संग्रह हो चुका है। विश्लेषण से समाने आनेवाली बातों पर विभागाध्यक्षों और महाविद्यालयों के प्राचार्यों के सुझाव और विचार जानने के लिए उनके लिए एक दिन की संगोष्ठी आयोजित की गई। परियोजना की रिपोर्ट लिखने का काम प्रगति पर है।

यह अध्ययन अब अपने अंतिम चरण में है।

14. पहाड़ी बोंडा जाति के जीवनमूल्य और उनकी भागीदारी (नीपा सहायता योजना के अंतर्गत)

जीवनमूल्यों और भागीदारी संबंधी यह शोध परियोजना 11 मई 1990 को नीपा की सहायता योजना के अंतर्गत 50,000 रुपये की व्यय राशि के साथ 18 माह की अवधि के लिए स्वीकृत की गई थी। प्रो.के.एल. महापात्र (अध्यक्ष, सामाजिक अनुसंधान और कार्यवाही संगठन, मुदुलीपाड़ा, कोरापुट, उड़ीसा) इस परियोजना की चला रहे हैं।

यह अध्ययन निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जा रहा हैं: इसका पता लगाना कि अभिभावक अपनी आशाओं की पूर्ति के लिए अपने विद्यालय जानेवाले बच्चों का विद्यालय में क्या ग्रहण करना पसंद करेंगे; इसका पता लगाना कि प्राथमिक शिक्षा वाली आयु के विद्यालयगामी बच्चे घर पर, बस्ती में, खेती में और जंगल में अपने परिवार और गांव के लिए क्या-क्या काम करते हैं; लगभग 20 बोंडा लड़कों और लड़कियों को लेकर इसका प्रयोग करना कि विद्यालय पूर्व शिक्षा के एक वर्ष के चरण में वे किन बातों में सबसे अधिक रुचि लेते हैं; परिवर्तनशील जीवन में अपने लिए मौजूद संभावनाओं तथा शिक्षा और उसमें बच्चों की भूमिका के बारे में बोंडा लोगों के आकलन का पता लगाना; इसका पता लगाना कि बोंडा जाति के लोग किस हद तक आवासी 'आश्रम' और 'सेवाश्रम' विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं; और विद्यालय से निकल आनेवाले या कभी विद्यालय न जानेवाले बच्चे की गतिविधियों के आर्थिक मूल्य का पता लगाना।

दमुरीपाड़ा गांव में विद्यालय के बारे में पाई जानेवाली सजगता को देखते हुए और वहां के ग्रामीणों की सहमति से स्थान हासिल करके उसे विद्यालय बनाने के लिए विकसित किया गया। यह विद्यालय एक प्रेरक अध्यापक को लेकर शुरू किया गया जो बोंडा जाति के जीवन और उनकी भाषा से अच्छी तरह परिचित है। वे पहले महीने में बच्चों को दो समूहों में बांटकर खेलने के लिए ले गए।

यह अध्ययन अब अपने अंतिम चरण में है।

15. पांडिचेरी का शैक्षिक विकास : ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

इस अध्ययन की 2,20,050 रुपये की व्ययराशि के साथ स्वीकृति दी गई। पांडिचेरी विश्वविद्यालय के डॉ.के.एस. मैथ्यू और नीपा के डॉ.ए.मैथ्यू इसका संचालन कर रहे हैं।

पांडिचेरी एक भूतपूर्व फ्रांसीसी उपनिवेश है और इस समय एक संघीय क्षेत्र है। यहां शिक्षाप्रणाली का विकास अनेक सकारात्मक पक्षों के कारण उल्लेखनीय है। भारतीय संघ में विलय के 35 साल के अंदर उसने 55.85 प्रतिशत साक्षरता प्राप्त की जबकि इसका अखिल-भारतीय औसत मात्र 36 प्रतिशत हैं। प्राथमिक नामांकन को देखते हुए पांडिचेरी प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के बहुत करीब लगता है। शैक्षिक सुविधाओं का प्रसार अभूतपूर्व रहा है। अनेक दूसरे राज्यों और संघीय क्षेत्रों की तुलना में शिक्षा के लिए यहां होनेवाला अधिक आवंटन प्रसार की इस गति को सहारा देता रहा है।

फिर भी ऐसा लगता है कि प्रबंध की दक्षता में कमियां भी

हैं जबकि प्रबंध ही प्रणाली की गुणवत्ता और उसके स्वास्थ्य को निर्धारित करता है। शैक्षिक प्रशासन के प्रतिमान, संस्थागत प्रबंध, अध्यापकों की वृत्तिक सक्षमता और उसका उन्नयन, उनकी भर्ती, नियुक्ति, प्रोन्नति और स्थानांतरण समेत कार्मिक नीति और संस्थाओं द्वारा उपलब्ध सुवधाओं का उपयोग भी इसमें आते हैं।

उपरोक्त कारकों के प्रकाश में देखें तो योजना और प्रबंध के सुधार मूलक उपाय आरंभ करने के सिलसिले में पांडिचेरी की शिक्षाप्रणाली का निदान प्रत्यक्ष महत्व रखता हैं। इस परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित अनुसंधान के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं: फ्रांसीसी शासन के अंतर्गत पांडिचेरी के शैक्षिक विकास की नीति और प्रणाली का अध्ययन करना; पांडिचेरी की शिक्षाप्रणाली पर उसके विलय के बाद फ्रांसीसी प्रभावों का अध्ययन करना; 1954 के बाद पांडिचेरी के शैक्षिक विकास की आलोचनात्मक छानबीन; तथा योजना और प्रबंध के केंद्रीय मुद्दों की पहचान करना और नवोदित सरोकारों के प्रकाश में सुधार के उपाय सुझाना।

रिपोर्ट लिखने का कार्य प्रगति पर है।

16. विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं की पहचान (नीपा सहायता योजना के अंतर्गत)

शैक्षिक प्रशासन विभाग, बड़ौदा विश्वविद्यालय की अध्यक्षा डॉ. (श्रीमती) एस. जोशी परियोजना 'विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं की पहचान' का संचालन कर रही है। नीपा ने अपनी सहायता योजना के अंतर्गत इसके लिए 9,800/- रुपये की राशि स्वीकृत की है।

संस्थागत प्रबंध के संदर्भ में परिवर्तन का प्रबंध पूरी दुनिया में अध्ययन का एक प्रमुख क्षेत्र रहा हैं। परिवर्तन की प्रक्रिया को आरंभ और उसका प्रबंध करने में संस्था प्रमुख केंद्रीय भूमिका निभाता है। बुच (1973), हैवलाक (1971), हाउस (1981), मुखोपाध्याय (1981) की श्रेष्ठ समीक्षाएं इसे अच्छी तरह स्पष्ट करती हैं। यह मान्यता कि विद्यालय का प्रधानाध्यापक विभिन्न शास्त्रों के बीच अकादमिक प्रबंध, वित्तीय प्रशासन, बुनियादी सुविधाओं के प्रबंध, कार्मिक-विकास, सहपाठ्यचर्यात्मक गतिविधियों के प्रबंध, बाह्य अनुबंधनों और सबसे बढ़कर, संस्था के निर्माण के लिए मानव-ऊर्जा और भौतिक संसाधनों को इष्टतम सीमा तक बढ़ाने जैसी प्रबंध ाकीय गतिविधियों में पारंगत होता है, कभी-कभी इन प्रध ानाध्यापकों के बारे में सही नहीं पाई जाती।

प्रधानाध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए ऐसे आवश्यक तत्वों की पहचान करना प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य सरोकार है। इसलिए इस अध्ययन का उद्देश्य प्रधानाध्यापकों से अपेक्षित निम्न-लिखित कार्यों को ध्यान में रखकर उनकी प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं की पहचान करना है : (अ) अकादमिक क्षेत्र, (ब) कार्मिक प्रबंध, (स) वित्तीय प्रबंध, (द) विद्यालय तंत्र और बुनियादी ढांचा, (य) अनुबंधन और पारस्परिक संसर्ग, (र) छात्र सेवाएं, (ल) पद्धतिशास्त्रीय क्षमताएं और (व) व्यवहार संबंधी क्षमताएं।

माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के सामने मौजूद समस्याओं की छानबीन करना; प्रधानाध्यापक प्रबंध के जिन प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों में प्रशिक्षण पाना चाहते हैं उनका पता लगाना; और माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के लाभार्थ व्यवस्थित ढंग से तैयार किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम के सुझाव देना इस अध्ययन के उद्देश्य हैं।

यह अध्ययन अपने अंतिम चरण में है।

नए अध्ययन

1. भारत के चुनिंदा विश्वविद्यालयों के परिदृश्य का अध्ययन (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रायोजित)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुरोध पर नीपा ने 9 केंद्रीय और 8 राज्य विश्वविद्यालयों के विकासशील परिदृश्य का एक अध्ययन 7 लाख रुपये की लागत से शुरू की है।

डॉ.जी.डी. शर्मा (वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष, उच्च शिक्षा एकक, नीपा) इस अध्ययन के परियोजना निदेशक हैं।

समग्र विश्वविद्यालय के लिए और अलग-अलग उसके प्रत्येक विभाग या केंद्र के लिए द्वितीयक और प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर भारत के केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों के उद्गम, कारगुजारी की स्थिति और विकास की भावी प्राथमिकता का विश्लेषण करना; प्रतिदर्शित विश्वविद्यालयों के विकास और कारगुजारी पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राज्य सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा दिए गए प्रोत्साहनों के प्रभाव की छानबीन करना; विश्वविद्यालयों की कारगुजारी और विकास पर सांगठनिक संरचना, निर्णय की प्रक्रिया, प्रशासनिक कार्मिकों और तौरतरीकों के प्रभाव की छानबीन करना; विश्वविद्यालयों की कारगुजारी और विकास में संकाय सदस्यों और छात्रों के योगदानों का विश्लेषण करना; विशेषकर किसी विश्वविद्यालय-समूह और सामान्यतः उच्च शिक्षा को प्रभावित करनेवाले महत्वपूर्ण चरों की पहचान करना; केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों के कार्यकलाप में इन प्रमुख चरों की भूमिका की तुलना करना और उनका वैपरित्य दिखाना; पिछली प्रवृत्तियों के आधार पर प्रतिदर्शित विश्वविद्यालयों के भावी विकास का प्रक्षेपण करना और वांछित दिशा में भावी विकास को ले जाने के लिए योजनाएं और कार्यवाही के कार्यक्रम सुझाना; तथा प्रत्येक चुने हुए विश्वविद्यालय का परिदृश्य तैयार करना और प्रत्येक के लिए विशिष्ट नीतियां और कार्यवाही के कार्यक्रम सुझाना इस अध्ययन के उद्देश्य हैं।

आंकड़ों को जमा करने और तालिकाबद्ध करने का काम प्रगति पर है।

2. आंध्रप्रदेश में पूर्वी गोदावरी और खम्मम जिलों के आदिवासी क्षेत्रों में एक अध्यापक वाले विद्यालयों का अध्ययन : आदिवासी कल्याण विभाग, आंध्रप्रदेश सरकार के सहयोग से मूल्यांकन-अध्ययन

इस अध्ययन को कुल 51,150 रुपये की लागत से किया जा रहा है। डॉ. (सुश्री) सुजाता (अध्येता, शैक्षिक प्रशासन एकक, नीपा) परियोजना प्रभारी हैं।

अध्ययन का आरंभ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पाने के उद्देश्य से किया गया: इसके दायरे में विद्यालय से वंचित सारे गांव आए हैं या नहीं और अगर नहीं तो स्थान निर्धारण के ब्यौरों की कमियां। (समष्टिस्तरीय आंकड़े जिला शिक्षाधिकारी, समन्वित आदिवासी विकास अभिकरण से प्राप्त किए जाएंगे।) जिन गांवों में एक अध्यापक वाले विद्यालय खोले गए हैं वहां विद्यालयगामी आयु के सभी बच्चे उनमें जा रहे हैं या नहीं; केवल स्थानीय आदिवासियों को नियुक्त किया गया है और अगर नहीं तो प्रयुक्त विधि और बाहर से आनेवाले आदिवासी की निवास, भाषा आदि की समस्याएं; सभी अध्यापक प्रशिक्षित हैं या नहीं और उनकी कठिनाइयां; अध्यापकों और छात्रों, अध्यापन की गुणवत्ता, संचार की समस्याओं, स्थान और अन्य बुनियादी सुविधाओं की दृष्टि से विद्यालय ठीक से चल रहे हैं या नहीं; क्या आश्रम विद्यालयों और आवासी विद्यालयों में अपव्यय और प्रगतिरोध के कारण तीसरे दर्जे की अपर्याप्त शिक्षा दी जा रही है; वेतन-विवरण और विद्यालयों में अवकाश के दिनों के बढ़ने की समस्याएं; क्या स्थानीय आदिवासियों की नियुक्ति के कारण उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार आया है; क्या वे अपने बंधु-बांधवों की अन्य समस्याओं की हल करने में समर्थ हैं; और आदिवासी 'योग्यता रहित' अध्यापकों और गैर आदिवासी योग्य अध्यापकों के संबंध मधुर हैं या नहीं।

आंकड़ों का संग्रह हो चुका है। प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों का विश्लेषण चल रहा है और रिपोर्ट का मसविदा लिखने का काम शुरू हो चुका है।

3. आधारभूत स्तर पर महिलाओं के कल्याण का अध्ययन (महिला और बाल विकास विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित)

इस अध्ययन की महिला और बाल विकास विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने 2,24,200/-

रुपये की व्ययराशि के साथ स्वीकृति दी है। इस अध्ययन के परियोजना निदेशक डॉ.एस.सी. नुना (अध्येता, प्रादेशिक प्रणाली एकक, नीपा) हैं।

अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार रखे जा सकते हैं : महिला-कल्याण के उस संश्लिष्ट सूचकांक की वैधता स्थापित करना जिसके आधार पर अध्ययन *वुमेन एंड डवलपमेंट* में देश के जिलों को पांच श्रेणियों में बांटा गया है; आधारभूत स्तर पर महिलाओं के कल्याण की प्रकृति का आकलन करना और *सेवाओं के अभिसार* का एक प्रतिरूप तैयार करना ताकि महिला-कल्याण में वृद्धि के लिए योजना की एक समन्वित रणनीति का विकास किया जा सके।

आंकड़े जमा करने का काम जारी है।

4. शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े 100 जिलों में महाविद्यालयों के विकास का अध्ययन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 3.40 लाख रुपये के अनुदान के साथ देश के शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े 100 जिलों में महाविद्यालयों के विकास का एक अध्ययन प्रायोजित किया है। इस अध्ययन के परियोजना निदेशक डॉ.जी.डी. शर्मा (वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष, उच्च शिक्षा एकक, नीपा) हैं।

अध्ययन निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जा रहा है: शैक्षिक और आर्थिक रूप से अल्पविकसित 100 जिलों में सबसे योग्य महाविद्यालयों की पहचान करना; चुने हुए महाविद्यालयों में अकादमिक और बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकताओं के संकेत देते हुए इन महाविद्यालयों के स्थिति संबंधी परिदृश्य तैयार करना; ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र सुझाना जिनमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हस्तक्षेप कर सकता है और इन महाविद्यालयों के विकास में सहायता की विशेष योजनाओं की सिफारिशें करना; संबद्ध जिलों के बुद्धिसंगत पक्षों को ध्यान में रखकर संस्थागत विकास के क्षेत्रों की पहचान करना, पहचाने गए क्षेत्रों के विकास के लिए प्रधानाचार्यों और स्टाफ में योजना और प्रशासन संबंधी तकनीकी प्रज्ञान और कुशलताओं का विकास करना; और महाविद्यालयों की कमियों और विकास के सूचकों का विकास करना। इन सूचकों का उपयोग बाद में दूसरे महाविद्यालय भी अपने विकास की योजनाएं बनाने के लिए कर सकते हैं।

महाविद्यालयों से आंकड़ा संग्रह का काम जारी है।

5. वर्ष 2000 तक प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण का अध्ययन : वैकल्पिक नीति समूहों के लिए उसके संसाधन संबंधी निहितार्थ

नीपा ने 95,000/- रुपये का प्रावधान करके 'वर्ष 2000 तक प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनीकरण : वैकल्पिक नीतिसमूहों के लिए उसके संसाधन संबंधी निहितार्थ' पर एक अध्ययन आरंभ किया है। अध्ययन के परियोजना निदेशक प्रोफेसर श्रीप्रकाश (वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष, शैक्षिक योजना एकक, नीपा) हैं।

नीतिगत परिप्रेक्ष्यों के लिए आवश्यक सहायता के ढांचे का विकास करना; प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए आवश्यक व्यय का विश्लेषण करना और दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में सभी राज्यों और संघीय क्षेत्रों की समेटते हुए नामांकन का राज्यवार प्रक्षेपण करना इस अध्ययन के उद्देश्य हैं जबकि अल्पकालिक परिप्रेक्ष्य में यह अध्ययन केवल पिछड़े राज्यों को ही समेटेगा।

प्रकाशन

किसी शोध-अध्ययन के परिणामों को प्रसारित करना भी स्वयं उस अध्ययन को पूरा करने जितना ही महत्वपूर्ण होता है। शोध-परिणामों को प्रसारित करने को अनेक विधियां हैं और अनेक साधन हैं। आमतौर पर वृत्तिक पत्रिकाओं में प्रकाशित आलेखों और लेखों तथा पुस्तकों के द्वारा शोध के परिणामों को भारी परिमाण में प्रसारित किया जाता हैं।

कार्यकारी और सामयिक आलेखों के द्वारा भी शोध के परिणाम प्रकाशित किए जाते हैं। विनिबंध और अनुलेखित पांडुलिपियां प्रसार की एक और विधि हैं। लेकिन पुस्तकों के प्रकाशन द्वारा विचारों का प्रसार आमतौर पर उसकी कहीं बहुत अधिक सुलभता को सुनिश्चित करता है। रिपोर्ट का यह भाग संस्थान के प्रकाशनों से संबंधित है।

संस्थान ने निम्नलिखित प्रकाशन प्रकाशित किए हैं।

शीलचंद नुना, **रीजनल डिसपैरिटीज इन एजुकेशनल डवलपमेंट,** नीपा, साउथ एशियन पब्लिशर्स, नई दिल्ली (समूल्य)।

योजना प्रक्रिया के आरंभ के साथ भारत ने शैक्षिक विकास के एक नए युग में प्रवेश किया। शैक्षिक विकास की प्रक्रिया जब आगे बढ़ी तो उसमें विकास के चुनिंदा क्षेत्रों के पक्ष में और देश के पिछड़े क्षेत्रों के खिलाफ एक जबरदस्त झुकाव देखा गया। योजना-प्रक्रिया ने इन विकृतियों पर अंकुश लगाने की कोशिश अवश्य की है मगर फिर भी विषमताओं का भारी परिमाण चिंता का विषय है।

समतामूलक संवृद्धि को आज भारत में योजना के प्रमुख उद्देश्यों में एक समझा जाता है। समता और संवृद्धि को मांगों के बीच कहीं कोई अंतर्विरोध नहीं है। दोनों के प्रति पाए जानेवाले सामाजिक सरोकार को इस प्रकार पूरा किया जा सकता है कि दोनों एक-दूसरे को सहारा दें और एक-दूसरे से सहारा पाएं।

शैक्षिक अवसरों की समानता को इसी संदर्भ में भारत की शैक्षिक नीति का एक प्रमुख लक्ष्य माना जाता है। इसके लिए क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने के जी तोड़ प्रयास आवश्यक हैं।

प्रस्तुत पुस्तक एक संकलन है और शिक्षा की दैशिक योजनाओं ओर उसके विकास की अनेकों समस्याओं और प्रक्रियाओं और क्षेत्रीय विषमताओं पर उनके प्रभाव की विवेचना करती है। यह शैक्षिक विकास की क्षेत्रीय विषमताओं की समस्या को उसकी समग्रता में समझने का प्रयास करती है। आशा है कि इससे पुस्तक में विवेचित और विश्लेषित विषय पर नए विचार सामने आएंगे और इस प्रकार 'समतामूलक संवृद्धि' के लक्ष्यों को पाने में सहायता देनेवाली रणनीतियों के विकास का रास्ता तैयार होगा।

रिपोर्ट आफ रीजनल वर्कशाप्स आन इनवायरनमेंटल एजुकेशन फार एजुकेशनल प्लानर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स (सितंबर-अक्टूबर 1991), नीपा और यूनेस्को-यूनेप

यह शैक्षिक योजनाकर्मियों और प्रशासकों के लिए पर्यावरण-शिक्षा पर आयोजित क्षेत्रीय कार्यशालाओं पर प्रस्तुत रिपोर्टों का एक संकलन है। इसमें पर्यावरण-शिक्षा की योजना और प्रबंध पर दक्षिणी, पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में आयोजित कार्यशालाओं पर चार क्षेत्रीय रिपोर्टें शामिल हैं। ये कार्यशालाएं नीपा में मई 1991 में पर्यावरण-शिक्षा पर आयोजित राष्ट्रीय प्रशिक्षण संगोष्ठी की अगली कड़ी थीं और यूनेस्को-यूनेप अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के तत्वाधान में आयोजित की गई थीं।

इस ग्रंथ में हरेक क्षेत्रीय कार्यशाला की कार्रवाइयां दी गई हैं। यह प्रत्येक क्षेत्र में पर्यावरण शिक्षा के मोटे-मोटे सरोकारों और साथ ही पर्यावरण-शिक्षा के विषय-विशिष्ट वादसंवादों को सामने लाता है। कार्यशालाओं के ब्यौरों, उद्देश्यों और विचारविमर्श को सामने रखते हुए यह रिपोर्ट प्रत्येक कार्यशाला के औचित्य, उद्देश्यों, कार्यक्रम की रूपरेखा और प्रमुख बातों को स्पष्ट करती है जिन्हें नीपा के समग्र मार्गदर्शन में स्थानीय योजना समिति ने निर्धारित किया था।

पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्र ने जहां मोटे तौर पर विद्यालय-शिक्षा में पर्यावरण शिक्षा को शामिल करने पर जोर दिया, वहीं पूर्वी क्षेत्र ने इसे उच्च शिक्षा में रखने पर जोर दिया। यह रिपोर्ट औपचारिक और अनौपचारिक पर्यावरण शिक्षा की रणनीतियों, पर्यावरण शिक्षा के लिए अध्यापकों को तैयारी, पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देने में शैक्षिक योजनाकर्मियों और प्रशासकों की भूमिका पर हुए विचार

विमर्श को प्रस्तुत करती है और साथ ही शिक्षा के सभी स्तरों पर पर्यावरण-शिक्षा की योजना और प्रबंध के क्षेत्रीय आयामों को भी स्पष्ट करती है। प्रत्येक कार्यशाला में पर्यावरण और विकास के अहम मुद्दों पर जो वादसंवाद हुए उन्हें भी यह रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

प्रस्तुत प्रकाशन इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि यह भारत के प्रत्येक क्षेत्र में पर्यावरण शिक्षा के विकास और कार्यकलापों को और साथ ही पर्यावरण शिक्षा की योजना और प्रबंध को बल पहुंचाने की राज्यस्तरीय कार्यवाही योजनाओं को भी एक ही जिल्द में प्रस्तुत करती है। देश के चारों क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र में पर्यावरण शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर कार्यरत संसाधन व्यक्तियों की एक विवरणिका भी इसमें शामिल है।

डवलपमेंट आफ एजुकेशन इन इंडिया : 1990-92, नीपा और मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग), नई दिल्ली

यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन के पाचवें सम्मेलन (जेनेवा 1992) में प्रस्तुत की गई थी। इस दस्तावेज के छः खंड हैं जो इस प्रकार हैं–खंड 1 : भारत में शिक्षा : एक विहंगावलोकन; खंड 2 : हाल की प्रवृत्तियां और भविष्य के परिप्रेक्ष्य; खंड 3 : अंतःवस्तु और पाठ्यचर्या; खंड 4 : सांस्कृतिक विकास के लिए शिक्षा; खंड 5 : अंतर्राष्ट्रीय सहयोग; और खंड 6 : बुनियादी शिक्षा के लिए विदेशी सहायता परियोजनाएं।

जर्नल आफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन

संस्थान प्रत्येक तिमाही में **जर्नल आफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन** शीर्षक पत्रिका का प्रकाशन करता है। साथ ही साथ इसके हिंदी संस्करण का प्रकाशन भी किया जाता है। समीक्षित वर्ष में पत्रिका के निम्नलिखित अंक प्रकाशित किए गएः

खंड पांच , अंक 3, जुलाई 1991; खंड पांच, अंक 4, अक्टूबर 1991; खंड छः, अंक 1, जनवरी 1992; खंड छः, अंक 2, अप्रैल 1992; खंड छः, अंक 3, जुलाई 1992

हिंदी पत्रिका : खंड चार, अंक 4, अक्टूबर 1990; खंड पांच, अंक 1, जनवरी 1991; खंड पांच, अंक 2, अप्रैल 1991; खंड पांच, अंक 3, जुलाई 1991.

इस समय निम्नलिखित प्रकाशन प्रेस में हैं:

जर्नल आफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, खंड छः, अंक 4, अक्टूबर 1992

शैक्षिक योजना और प्रशासन, खंड पांच, अंक 4, अक्टूबर 1991

अनुलेखित प्रकाशन (मिमियोग्राफ)

संस्थान ने शोध-अध्ययनों, सामयिक आलेखों और विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अनुलेखित प्रकाशनों की एक शृंखला का प्रकाशन भी किया।

अध्याय 4

व्यावसायिक सहयोग और परामर्शकारी सेवा

राज्य सरकारों और शिक्षा संस्थानों के अनुरोध पर परामर्शकारी सेवाएं प्रदान करना संस्थान के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नीपा के संकाय सदस्यों ने शिक्षा संगठनों को राष्ट्रीय, राज्य, जिला और सांस्थानिक स्तर पर व्यावसायिक समर्थन और परामर्शकारी सेवाएं प्रदान कीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी परामर्शकारी सेवाएं प्रदान की गईं। संकाय सदस्यों द्वारा दी गई परामर्शकारी और व्यावसायिक सेवाओं को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है :

1. विश्लेषण और रिपोर्ट द्वारा;
2. स्थाई, शासी निकाय और सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में भागीदारी;
3. विशेष रूप से गठित समिति की सदस्यता के रूप में।

समीक्षाधीन वर्ष में संकाय सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और भारत में शैक्षिक संगठनों की विभिन्न स्तरों पर परामर्शकारी और व्यावसायिक सेवाएं प्रदान कीं। इनमें राष्ट्रीय शैक्षिक संगठनों जैसे– मानव संसाधन विकास मंत्रालय, योजना आयोग, केब, वित्त आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, राज्य शिक्षा विभाग, एजुकेशनल कंसलटैंट इंडिया लिमिटेड, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, जिला संस्थान, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और विद्यालय शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में मुख्यतः यूनेस्को, एस.आई.डी.ए. और विश्व बैंक की परामर्शकारी और व्यावसायिक सेवाएं प्रदान की गई।

राष्ट्रीय स्तर पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ई.डी.सी.आई.एल और रा.शै.अ.प्र.प. को विशेषज्ञता सेवा प्रदान की गई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को निम्नलिखित क्षेत्रों में परामर्शकारी सेवाएं प्रदान की गईं : शिक्षक प्रशिक्षण समिति और कार्ययोजना की तैयारी; शैक्षिक वित्त और दसवां वित्त आयोग और विदेशी विद्वानों का चयन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को स्वायत्त महाविद्यालयों, अकादमिक स्टाफ कालेजों, पाठ्यक्रमों का व्यावसायीकरण, शिक्षण, अनुसंधान और महिला अध्ययन में सुधार के क्षेत्रों में विशेषज्ञता सेवाएं प्रदान की गई। इ.डी.सी.आई.एल. को मिजोरम विश्वविद्यालय की स्थापना और कोरापुरट, उड़ीसा में शैक्षिक परिसर के विकास के लिए परामर्शकारी सेवा प्रदान की गई। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् को शिक्षक और महिला शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञता सेवा प्रदान की गई।

राज्य स्तर पर राज्य उच्च शिक्षा परिषद और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की राज्य स्तर पर उच्च शिक्षा की योजना, आलेख संशोधन, प्राचार्यों और उप-प्राचार्यों के प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम परिकल्पना के क्षेत्र में विशेषज्ञता सेवा प्रदान की गई। दिल्ली प्रशासन के विद्यालयों को सलाह दिया गया। जि.शि.प्र.सं. की व्यावसायिक सेवा प्रदान की गई। राज्य सरकारों की शिक्षा परियोजना में सेवाएं प्रदान की गई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार करने में सहायता प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त केंद्रीय विद्यालयों को उनके प्रबंधकीय मामलों में सहायता प्रदान की गई।

1992–93

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व बैंक और एस.आई.डी.ए. को सबके लिए शिक्षा परियोजना, जनसंख्या और संसाधन विकास तथा लोग जुंबिश परियोजना के लिए विशेषज्ञता सेवा प्रदान की गई। तालिका 1 में राष्ट्रीय, राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की दी गई व्यावसायिक और परामर्शकारी सेवाओं का विवरण दिया गया है:

तालिका 1

संगठन और क्षेत्रवार परामर्श/व्यावसायिक समर्थन

संगठन	परामर्शकारी/व्यावसायिक सेवाएं
1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय	1. विदेशी विद्वानों का चयन
	2. दसवां वित्त आयोग
	3. शिक्षक प्रशिक्षण पर समिति
	4. शैक्षिक सांख्यिकी
	5. कार्य योजना की तैयारी
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	1. स्वायत्त और अकादमिक स्टाफ कालेज
	2. शिक्षण और अनुसंधान के स्तर में सुधार
	3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पाठ्यक्रमों का व्यावसायीकरण
	4. महिला अध्ययन
3. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद	1. शिक्षक प्रशिक्षण
	2. महिला शिक्षा
4. इ-डी.सी.आई.एल.	1. विश्वविद्यालयों की स्थापना
	2. शैक्षिक परिसरों का विकास
5. राज्य सरकारें	1. राज्य (उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल में शिक्षा परियोजना)
	2. शैक्षिक प्रशासन (अरुणाचल प्रदेश)
6. राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद	1. राज्य उच्च शिक्षा की योजना
	2. सदस्य, शासी निकाय और कार्यकारी समिति
	3. आलेख संशोधन
	4. प्राचार्यों और उपप्राचार्यों के प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम की रूपरेखा
	5. दिल्ली प्रशासन के विद्यालय
7. जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान	1. व्यावसायिक समर्थन सेवा

संगठन	परामर्शकारी/व्यावसायिक सेवाएं
8. इं.गां.रा.मु. विश्वविद्यालय	उच्च शिक्षा के डिप्लोमा में सहयोग
9. केंद्रीय विद्यालय	प्रबंध समिति
10. विश्व बैंक	1. सबके लिए शिक्षा 2. जनसंख्या और उपकरण संसाधन विकास
11. शिक्षा के विकेंद्रीकृत प्रबंध पर केब समिति	लोक जुंबिश परियोजना

शिक्षा के विकेंद्रीकृत प्रबंध पर केब समिति

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अधिकार केब समिति के अध्यक्ष के रूप में अपने सामर्थ्य के तहत एक समिति का गठन किया। कर्नाटक के मुख्य मंत्री श्री वीरप्पा मोइली को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के संदर्भ में शिक्षा की विकेंद्रीकृत व्यवस्था पर मार्गदर्शन सिद्धांतों के प्रतिपादन के लिए इस समिति का गठन किया गया। संस्थान के संकाय सदस्यों ने निम्नलिखित क्षेत्रों में अपना योगदान दिया :

1. अनुसंधान अध्ययन कार्य;
2. स्थायी अतिथि के रूप में समिति की सलाह और सहायता;
3. समिति के लिए पृष्ठभूमि दस्तावेजों की तैयारी;
4. ड्राफ्ट रिपोर्टों की तैयारी।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

संस्थान ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से 'भारत में शैक्षिक विकास 1990-92' विषय पर राष्ट्रीय रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन के 43वें सत्र में प्रस्तुत किया गया।

संस्थान ने शिक्षा विभाग, मा.सं.वि.मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति और सहायता अनुदान समिति (स्वंय सेवी संगठनों को सहायता देने के लिए) की विभिन्न बैठकों में भाग लिया। संस्थान ने संशोधित कार्य योजना 1992 की तैयारी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नीपा संकाय ने 'शिक्षा का प्रबंध' और 'महिला समता के लिए शिक्षा' विषयों पर अध्याय की तैयारी में सहयोग दिया। इसके अतिरिक्त नीपा संकाय ने 'अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की शिक्षा' और 'शिक्षक और उनके प्रशिक्षण' विषयों पर अध्यायों की तैयार में भी सहयोग दिया।

नीपा ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को कार्य योजना के संचालन में भी अकादमिक और व्यावसायिक समर्थन प्रदान किया। राज्य स्तर पर क्रियात्मक योजनाओं, विशेषतः शिक्षा के प्रबंध के संबंध में कार्रवाई योजना की तैयारी के लिए राज्यों के साथ विभिन्न क्षेत्रीय बैठकों में संकाय ने भाग लिया।

योजना आयोग

योजना आयोग द्वारा शैक्षिक योजना के विभिन्न पहलुओं पर गठित कार्य समूहों में संस्थान के संकाय सदस्यों ने सेवाएं प्रदान की। संकाय ने राज्य स्तरीय योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए आयोजित विभिन्न बैठकों में भी भाग लिया।

योजना आयोग द्वारा गठित ''मुक्त शिक्षा कोर ग्रुप'' की बैठकों में संस्थान का प्रतिनिधित्व रहा। इसके अतिरिक्त आठवीं पंचवर्षीय योजना की तैयारी के लिए योजना आयोग द्वारा बुलाई गई बैठकों में भी संस्थान का प्रतिनिधित्व रहा।

1992–93

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

नीपा के संकाय सदस्यों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अकादमिक स्टाफ कालेजों और स्वायत्त महाविद्यालयों के कार्यों की समीक्षा के द्वारा व्यावसायिक समर्थन और परामर्शकारी सेवाएं प्रदान की। विश्वविद्यालयों की स्थापना में भी नीपा संकाय ने परामर्शकारी सेवा प्रदान की। नीपा संकाय ने स्वायत्तता और उत्तरदायित्व की संकल्पना के संचालन में भी मदद की। विश्वविद्यालय वित्त के संचालन में भी नीपा संकाय ने अपना सहयोग दिया। इसके अतिरिक्त समीक्षा समितियों की रिपोर्टों की तैयारी में भी नीपा ने कार्य किया।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

चुने हुए क्षेत्रों में बाह्य सहायता के रूप में प्राथमिक शिक्षा परियोजनाओं के प्रतिपादन में नीपा संकाय ने व्यावसायिक सेवाएं प्रदान की। राज्य के वित्त और सार्वजनिक तथा लैंगिक मसलों के आधारभूत मूल्यांकन विश्लेषण से संबंधित उत्तरदायित्व में अकादमिक सदस्यों ने साझेदारी की। नीपा संकाय ने अनुसंधान अध्ययनों की रूपरेखा तैयार करने में भी सहयोग दिया। नीपा संकाय ने विभिन्न राज्यों के लिए परियोजना मूल्यांकन में भी अपना सहयोग प्रदान किया।

बाह्य अनुदान प्राप्त परियोजनाएं

नीपा संकाय ने उत्तर प्रदेश सरकार को विश्व बैंक से अनुदान प्राप्त करने के लिए "सबके लिए शिक्षा– उत्तर प्रदेश" परियोजना के दस्तावेज तैयार करने में अकादमिक सहायता प्रदान की। इसके अतिरिक्त संकाय ने "लोक जुंबिश" और "दक्षिण उड़ीसा परियोजना" के प्रतिपादन में भी योगदान दिया।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग/परस्पर सहानुभूतिक स्मरण पत्र

एशिया में शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में अनुसंधान और प्रशिक्षण के क्षेत्र में नीपा एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है। संस्थान पारस्परिक रुचि के क्षेत्रों में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सहयोग करता रहा है। संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान, पेरिस और शंघाई शिक्षा संस्थान से अनुसंधान, प्रशिक्षण और शैक्षिक योजना एवं प्रशासन के क्षेत्र में सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए आपसी सहयोग स्मरण पत्र पर हस्ताक्षर किए।

विशिष्ट विदेशी मेहमान/ अनुभवों का आदान-प्रदान

विदेशी शिक्षा संस्थानों के संकायों के साथ अनुभवों के आदान-प्रदान द्वारा संस्थान को बहुत लाभ प्राप्त होता रहा है। इस वर्ष निम्नलिखित विदेशी मेहमानों ने संस्थान का दौरा किया :

- विश्वबैंक में वरिष्ठ समाजशास्त्री, डॉ.मारलेन लाकहीस ने भारत में शैक्षिक विकास के प्रश्नों पर नीपा के संकाय के साथ विचार विमर्श किया (17.9.1992)
- ब्रिटिश कौंसिल एजुकेशन, डिवीजन के श्री केविन ओकोनर ने "सबके लिए शिक्षा" कार्यक्रम के बारे में नीपा के संयुक्त निदेशक के साथ विचार विमर्श किया। (14.10.1992)
- एशियाई विकास बैंक, मनीला के श्री बाब डासन ने नीपा के संकाय के साथ विचार-विमर्श किया और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में बैंक की गतिविधियों से परिचित कराया। (15.10.1992)
- यूनेस्को, पेरिस के डॉ. डब्ल्यू गार्डन और यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली की सुश्री मेरियन हुक ने बाहरी वित्तीय सहायता से लागू की जाने वाली शैक्षिक परियोजनाओं के बारे में नीपा के संयुक्त निदेशक और संकाय के साथ बैठक की।
- नार्थ लंदन विश्वविद्यालय के पुस्तकालय और सूचना अध्ययन केंद्र की अध्यक्षा सुश्री रोजमैरी रैडन ने संयुक्त निदेशक और संकाय से मुलाकात की और विद्यालयों में अधिगम संसाधनों की योजना और विकास के विषय पर उनसे विचार-विमर्श किया।

अध्याय 5

पुस्तकालय, प्रलेखन और अकादमिक समर्थनकारी प्रणाली

पुस्तकालय

संस्थान के पास शैक्षिक योजना, प्रशासन और अंतः शास्त्रीय विषयों का एक समृद्ध पुस्तकालय है। वर्षों के कालक्रम में यह शैक्षिक योजनाकर्मियों, प्रशासकों, विद्वानों, छात्रों और प्रशिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहा है। पुस्तकालय और प्रलेखन सेवाएं वर्ष भर अबाध रूप से चलती रहती हैं।

समीक्षाधीन वर्ष में 604 नई पुस्तकें संगृहीत की गईं। 1992-93 के दौरान पुस्तकालय के भंडार से 898 पुस्तकें निकाल दी गईं। इस समय पुस्तकालय के पास 44,804 पुस्तकों का संग्रह है। इसके अलावा इसमें यूनेस्को, आर्थिक सहयोग-विकास संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यूनीसेफ आदि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों और सम्मेलनों की रिपोर्टों का संग्रह भी है।

पत्रिकाएं

पुस्तकालय/प्रलेखन केंद्र में मुख्यतः शैक्षिक योजना, प्रशासन, प्रबंध और अन्य संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित 350 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाएं मंगाई जाती हैं। इन पत्रिकाओं के सभी महत्वपूर्ण लेखों की अनुक्रमणिकाएं तैयार की जाती हैं। इस साल पत्रिकाओं से 2503 लेखों की अनुक्रमणिका तैयार की गई।

समाचारपत्रों की कतरनें

पुस्तकालय/प्रलेखन केंद्र में पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं के अलावा शैक्षिक योजना और प्रशासन पर समाचारपत्रों की कतरनों का एक विशेष संग्रह भी रखा जाता है। इस समय पुस्तकालय/प्रलेखन केंद्र के पास 150 विषयवार फाइलें मौजूद हैं।

अमुद्रित सामग्री

पुस्तकालय एक बहुमाध्यमी संसाधन केंद्र है। इसके पास वीडियो कैसेटों, आडियो कैसेटों, फिल्मों, माइक्रोफिल्मों और माइक्रोफिचों का संग्रह है। इस समय इसमें 6 फिल्मों, 35 वीडियो कैसेटों, 80 आडियोकैसेटों, 54 माइक्रोफिल्मों और 58 माइक्रोफिचों का संग्रह है।

समसामयिक जानकारी सेवा

किसी विशेष पखवाड़े के दौरान शिक्षा के विषय पर प्राप्त पत्रिकाओं की विषय सूची अंतर्तत्व के बारे में पाठकों को समसामयिक जानकारी सेवा प्रदान करने के लिए पुस्तकालय ने 'पीरियाडिकल्स आन एजुकेशन : टाइटिल्स रिसिव्ड एंड देयर कांटेंट्स' शीर्षक से अपना पाक्षिक अनुलेखित प्रकाशन जारी रखा।

अन्य स्रोत

पुस्तकालय/प्रलेखन केंद्र में रुचिकर दस्तावेजों ओर लेखों तथा नई आनेवाली पुस्तकों ओर पत्रिकाओं के बारे में जानकारी के लिए संगणक वर्ष से मासिक सूची भी तैयार की जाती रही। इस वर्ष पुस्तकालय ने संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के लिए 103 संदर्भसूचियां भी तैयार कीं।

प्रलेखन केंद्र

संस्थान के कार्यक्रमों तथा खासकर राज्यों और संघीय क्षेत्रों

की आवश्यकताओं पर आधारित कार्यक्रमों को संबंधित सूचनाओं का एक कारगर आधार प्रदान करने के लिए पुस्तकालय का प्रलेखन केंद्र शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में केंद्र, राज्यों, संघीय क्षेत्रों, शिक्षा विभागों, जिला शिक्षा अधिकारियों और शिक्षासंस्थाओं द्वारा प्रकाशित संदर्भ-सामग्री का संग्रह करता है। केंद्र का खास ध्यान सूचनाओं के संग्रह, रखरखाव और प्रसार पर है ताकि संस्थान सूचनाओं के शोधन गृह की भूमिका निभा सके।

इस वर्ष केंद्र में 695 नए दस्तावेज आए। इस समय केंद्र में 13,649 दस्तावेज हैं। इनमें राज्यों के गजेटियर, राज्यों की जनगणना की हस्तपुस्तिकाएं, शैक्षिक सर्वेक्षण, राज्यों की शैक्षिक योजनाएं, बजट दस्तावेज, राज्यीय विश्वविद्यालयों की हस्तपुस्तिकाएं, बुनियादी स्रोतग्रंथ और संदर्भसूचियां, प्रेस कतरनें, राज्यों की शैक्षिक नियमावालियां, कानून, नियम कायदे, तकनीकी-आर्थिक और प्रतिदर्शी सर्वेक्षण, जिलों के गजेटियर, जिलों में जनगणना की हस्तपुस्तिकाएं, वार्षिक योजनाएं, शैक्षिक योजनाएं, जिला ऋण-योजनाएं, प्रमुख बैंकों की रिपोर्टें, जिला प्रतिदर्शी सर्वेक्षण, जिला शैक्षिक सर्वेक्षण, जिला सांख्यिकीय हस्तपुस्तिकाएं, गांव और प्रखंड स्तर की योजनाएं और अध्ययन, अनुसंधानों और परियोजनाओं की रिपोर्टें, संसाधन अन्वेषण अध्ययन, तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण, नीपा के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की रिपोर्टें, नीपा के शोध-अध्ययन, नीपा द्वारा आयोजित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के भागीदारों द्वारा प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध इत्यादि शामिल हैं।

प्रलेखन केंद्र निम्न उपायों से शैक्षिक योजना और प्रशासन संबंधी प्रवर्तनकारी अनुभवों और नवाचारों के बारे में सूचनाओं का प्रसार करता है :

1. शोधकर्ताओं और संकाय सदस्यों के बीच चुनिंदा सूचनाओं के प्रसार की सेवा;
2. 'एजुकेशन इन इंडिया : करेंट प्रेस क्लिपिंग सर्विसेज' नामक मासिक सूची का प्रकाशन;
3. प्रलेखन सूचियां
4. प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए संदर्भसूचियों का संकलन।

प्रलेखन सेवाएं

यह शिक्षा नीति, योजना और प्रबंध के कार्मिकों और विद्वानों, दोनों के लाभार्थ प्रकाशन की एक श्रृखंला है। प्रकाशन का पहला अंक स्टाफ के विकास पर एक टीकायुक्त संदर्भसूची पर केंद्रित है। दूसरा अंक शिक्षा के बारे में जे. पी. नायक के विचारों पर है। इसमें जे. पी. नायक द्वारा लिखित पुस्तकें और लेख भी शामिल हैं।

संगणक केंद्र

संस्थान के पास एक सुसज्जित संगणक केंद्र है जो विभिन्न प्रशिक्षण, शोध और अन्य गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान करता है। इसमें निम्नलिखित प्रणालियां उपलब्ध हैं :

पी सी/ए टी-80286	05
पी सी/ए टी-80386	04
पी सी / एक्स टी	12

प्रकाशन के वेंचुरा साफ्टवेर से युक्त डी. टी. पी. प्रणाली संस्थान के अपने प्रकाशन-कार्य की जरूरतें पूरा करती है। उपरोक्त हार्डवेयर के अलावा संगणक केंद्र में नवीनतम पी सी आधारित साफ्टवेयर पैकेज, लोटस 1-2-3 (रिला.3), डी-बेस चार, एस पी. एस. एस. पी. सी + (वे. 4), साफ्टकैल्क, साफ्टवर्ड, साफ्टबेस और वर्डस्टार (रिला. 6) जैसे मैनुअल भी उपलब्ध हैं। प्रोग्रामान के लिए कोबोल, फोरट्रान, पास्कल और 'सी' कंपाइलर्स का उपयोग किया जाता है। यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इ. एस. सी. ए. पी., यू. एन. एफ. पी. ए. आदि से उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाजनक अनेक साफ्टवेयर भी प्राप्त हुए हैं। शैक्षिक और संबद्ध आंकड़ों के परिमाणात्मक विश्लेषण के लिए इनका उपयोग किया जा रहा है।

मानचित्रण कक्ष

मानचित्रण कक्ष प्रशिक्षण और शोध के लिए चित्रांकन की सुविधाएं प्रदान करता है। इस कक्ष ने चित्रों, ग्राफों, चार्टों, तालिकाओं और पारदर्शी चित्रों के द्वारा आंकड़ों और सूचनाओं की प्रस्तुति की नई विधियों का विकास किया है। इनका प्रयोग विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और शोध परियोजनाओं में दृश्यचित्र प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। इस कक्ष ने हिंदी में 'सबके लिए शिक्षा : सचित्र प्रस्तुतीकरण' को पेश किया है। यह ग्रंथ पिछले 40 वर्षों के शैक्षिक आंकड़े प्रस्तुत करता है।

हिंदी कक्ष

संस्थान का हिंदी कक्ष न केवल विभिन्न प्रकाशनों को हिंदी में लाने में सहायता देता है बल्कि सरकार की राजभाषा नीति को लागू करने का साधन भी है। इस वर्ष राजभाषा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से राजभाषा क्रियान्वयन समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं। समिति की सिफारिश पर हिंदी आशुलिपि और टंकण में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया। हिंदी दिवस भी मनाया गया।

इस वर्ष हिंदी में पत्रिका के चार अंक प्रकाशित किए गए। कक्ष ने श्री पी. एन. त्यागी की एक पुस्तक 'सबके लिए शिक्षा : सचित्र प्रस्तुतिकरण' का प्रकाशन भी किया। इस वर्ष विनिबंध 'एजुकेशन इन 2000 ए. डी.' का हिंदी में अनुवाद किया गया।

अध्याय 6

संगठन, प्रशासन और वित्त

नीपा सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय है और इसे भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अनुदान-सहायता प्राप्त होती है। इसकी एक परिषद्, एक कार्यकारी समिति, एक वित्त समिति और एक योजना ओर कार्यक्रम समिति है जो इसके प्रमुख निकाय हैं। संस्थान का निदेशक प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होता है और वह भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसकी सहायता के लिए एक संयुक्त निदेशक होता है। कुल सचिव कार्यालय का प्रमुख और पूरे प्रशासन का प्रभारी होता है।

परिषद

परिषद संस्थान का शीर्ष निकाय है। इसका प्रमुख भारत सरकार द्वारा मनोनीत एक अध्यक्ष होता है। नीपा का निदेशक परिषद् का उपाध्यक्ष होता है। परिषद में राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय शिक्षा प्रणालियों के कार्यपालक और प्रमुख शिक्षाशास्त्री सदस्य होते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष; भारत सरकार के चार सचिव (शिक्षा, वित्त कार्मिक और योजना आयोग); राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के निदेशक; राज्यों और संघीय क्षेत्रों से छः शिक्षा सचिव, छः शिक्षा निदेशक; छः प्रमुख शिक्षाशास्त्री; कार्यकारी समिति के सभी सदस्य और नीपा संकाय के तीन सदस्य परिषद के सदस्य होते हैं। नीपा का कुलसचिव परिषद के सचिव का काम करता है।

परिषद का प्रमुख कार्य संस्थान के उद्देश्यों को आगे बढ़ाना तथा संस्थान के मामलों पर आम निगरानी रखना है।

31 मार्च 1993 की स्थिति के अनुसार परिषद के सदस्यों की सूची परिशिष्ट-I में दी गई है।

कार्यकारी समिति

संस्थान का निदेशक इसका पदेन अध्यक्ष होता है। सचिवों द्वारा नामांकित व्यक्ति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग); वित्त और योजना आयोग; किसी राज्य का एक शिक्षा सचिव; एक प्रमुख शिक्षा शास्त्री; किसी राज्य सरकार का एक निदेशक तथा शैक्षिक योजना और प्रशासन में सक्रिय रुप से संलग्न राज्य शिक्षा संस्थान का एक निदेशक; नीपा का संयुक्त निदेश, नीपा की परिषद में शामिल तीन में से दो संकाय सदस्य भी कार्यकारी समिति के सदस्य होते हैं। नीपा का कुलसचिव कार्यकारी समिति के सचिव का काम करता है।

कार्यकारी समिति परिषद के मामलों और धन के प्रबंध के प्रति उत्तरदायी होती है। उसे परिषद की सभी शक्तियों के व्यवहार के अधिकार प्राप्त हैं। 31 मार्च, 1993 की स्थिति के अनुसार कार्यकारी समिति के सदस्यों की सूची परिशिष्ट-II में दी गई हैं।

वित्त समिति

वित्त समिति को अध्यक्ष नियुक्त करता है। इसमें संस्थान के निदेशक की पदेन अध्यक्षता में पांच सदस्य होते हैं। वित्त सलाहकार तथा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत परिषद-सदस्य इसके सदस्य होते हैं। नीपा का कुल सचिव वित्त समिति का सचिव होता है।

वित्त समिति खातों और बजट आकलनों की छानबीन करती हैं और नए व्यय तथा अन्य वित्तीय विषयों पर प्रस्तावों की सिफारिश करती है। 31 मार्च 1993 की स्थिति के अनुसार वित्त समिति के सदस्यों की सूची परिशिष्ट-III में दी गई है।

योजना और कार्यक्रम समिति

संस्थान का निदेशक योजना और कार्यक्रम समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। नीपा के संयुक्त निदेशक अकादमिक एककों के अध्यक्ष; मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग), योजना आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक-एक प्रतिनिधि; किसी विश्वविद्यालय का कुलपति (अध्यक्ष द्वारा मनोनीत); राज्य सरकारों के दो शिक्षासचिव और दो शिक्षा निदेशक (भारत सरकार द्वारा मनोनीत); अध्यक्ष द्वारा मनोनीत छः शिक्षाशास्त्री/समाजवैज्ञानिक/प्रबंध विशेषज्ञ (जिनमें से दो महिलाओं या लड़कियों की शिक्षा से, एक अनुसूचित जातियों ओर जनजातियों की शिक्षा से और एक अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबद्ध हों) इस समिति के सदस्य होते हैं। नीपा की परिषद के अध्यक्ष, और भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) योजना और कार्यक्रम समिति के सदस्यों को मनोनीत करते हैं। इस समिति के सदस्यों की सूची परिशिष्ट-IV में दी गई है।

योजना और कार्यक्रम समिति से अपेक्षा की जाती है कि वह संस्थान के विभिन्न कार्यक्रमों को स्वीकृत करेगी, अंतिम रूप देगी और उनकी समीक्षा करेगी; संस्थान के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक अकादमिक परिप्रेक्ष्यों और योजनाओं का विकास करेगी; संकाय द्वारा योजनाबद्ध शोध, प्रशिक्षण, प्रसार और सलाहकार कार्यक्रमों की प्रतिवर्ष समेकित करेगी; उनका अध्ययन करेगी तथा कमियों और प्राथमिकता के क्षेत्रों की पहचान करेगी।

अकादमिक एकक

संस्थान का संकाय निम्न 8 अकादमिक एककों में विभाजित है—शैक्षिक योजना, शैक्षिक प्रशासन, शैक्षिक वित्त, शैक्षिक नीति, विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रादेशिक प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय एकक। अध्याय 1 में इन एककों के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण दिया गया है।

वरिष्ठ अध्येता इन अकादमिक एककों के प्रमुख हैं। केवल शैक्षिक नीति का प्रमुख अध्येता है। अकादमिक एकक पूरी जिम्मेदारी के साथ विभिन्न प्रशिक्षण और शोध कार्यक्रम की तैयार और लागू करते हैं। इसके अतिरिक्त एकक सौंपे गए क्षेत्रों में परामर्शकारी ओर सलाहकारी सेवाएं भी प्रदान करते हैं।

कार्यदल और समितियां

समय-समय पर संस्थान के निदेशक द्वारा विशेष कार्यक्रमों के लिए विशेष कार्यदलों और समितियों का गठन किया जाता है।

विभिन्न शोध-परियोजनाओं के लिए सलाह देने तथा उनकी प्रगति पर निगरानी रखने के लिए परियोजना सलाहकार समितियां गठित की जाती हैं। इसके सदस्य संबद्ध क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं।

निदेशक की अध्यक्षता में एक शोध-अध्ययन सलाहकार परिषद अध्ययनों के लिए सहायता की योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करता हैं। दूसरों के अलावा अकादमिक एककों के अध्यक्ष भी इसके सदस्य होते हैं और कुल-सचिव इसका सदस्य-सचिव होता है।

प्रशासनिक ढांचा

प्रशासन और वित्त प्रखंड की चार अनुभागों और दो कक्षों में संगठित किया गया है। ये इस प्रकार हैं—अकादमिक प्रशासन, लेखा, कार्मिक प्रशासन, सामान्य प्रशासन, प्रशिक्षण कक्ष और समन्वय कक्ष। अकादमिक प्रशासन और समन्वय कक्ष सीधे कुलसचिव को अपनी रिपोर्ट देते हैं। कार्मिक

और समान्य प्रशासन के प्रखंड और प्रशिक्षण कक्ष प्रशासनिक अधिकारी की निगरानी में चलते हैं और कुलसचिव इनका प्रभारी होता है। वित्त अधिकारी वित्त और लेखा अनुभाग का प्रभारी होता है। 31 जनवरी 1993 को कार्यकारी कुलसचिव की सेवानिवृत्ति के बाद वित्त अधिकारी ही कार्यकारी कुलसचिव का काम करते रहे।

31 मार्च, 1993 की संस्थान के स्टाफ की सदस्य संख्या 180 थी। संस्थान में विभिन्न श्रेणियों के कार्मिकों की संख्या नीचे दी गई है :

पद	संख्या
संकाय	34
अकादमिक समर्थन सेवा	27
प्रशासन और वित्त	36
सचिवालय और तकनीकी स्टाफ	38
समूह घ	45
योग	180

स्टाफ में परिवर्तन

प्रो. सत्यभूषण
नीपा के निदेशक, 31 मई 1992 की सेवानिवृत्त हुए।

डॉ. ब्रह्मप्रकाश
18 जनवरी 1993 से एशियाई विकास बैंक, मनीला के शिक्षा विभाग में कार्य करने के लिए नीपा से त्याग पत्र दिया।

डॉ. जी.डी. शर्मा
प्रतिनियुक्ति के आधार पर 1 फरवरी 1993 से भारतीय शिक्षा संस्थान, पुणे के निदेशक पद पर कार्यरत हैं।

डॉ. एम. मुखेपाध्याय
प्रतिनियुक्ति के आधार पर 29 जनवरी 1993 से राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं।

के.एल. दुआ
प्रशासनिक अधिकारी और कार्यकारी कुलसचिव, के रूप में 31 जनवरी 1993 को सेवानिवृत्त हुए।

बी.एच. श्रीधर
सिस्टम एनालिस्ट के पद पर 18 जनवरी 1993 को सेवानिवृत्त हुए।

विदेश यात्राएं

1. डॉ. आर.गोविंद
   अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान, पैरिस में आवासी छात्रवृत्ति लेकर 14 जनवरी 1993 से विशेष अवकाश पर।

   साक्षरता और सतत शिक्षा के लिए कार्मिक योजना और प्रबंध संबंधी क्षेत्रीय कार्यशाला, बैंकाक, में 27-29 अगस्त, 1992 के दौरान प्रशिक्षण की सामग्री तैयार करने के लिए यूनेस्को द्वारा आमंत्रित।

2. प्रो. श्री प्रकाश
   आगत-निर्गत तकनीक पर सेविल, स्पेन में 28 मार्च से 1 अप्रैल, 1993 तक आयोजित दसवें अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सत्र की अध्यक्षता की। सम्मेलन के पूर्ण सत्र और कार्यशाला सत्र में एक-एक आलेख प्रस्तुत किया।

3. डॉ. जया इंदिरेसन

16 सितंबर 1992 से 21 अक्तूबर 1992 तक शास्त्री भारत-कनाडा संस्थान की यात्रा। विशेष अवकाश पर 22 अक्तूबर 1992 से 24 नवंबर 1992 तक अमरीका और जर्मनी के विभिन्न विश्वविद्यालयों का भ्रमण किया। अकादमिक आदान-प्रदान और संस्थानिक निर्माण के लिए सिंगापुर राष्ट्रीय विश्व-विद्यालय में 7 से 10 अप्रैल 1992 तक आयोजित कार्यशाला में भाग लिया और "भारत के तकनीकी संस्थानों में छात्र गतिशीलता" पर आलेख प्रस्तुत किया।

4. डॉ. वाई. पी. अग्रवाल

जनसंख्या, शिक्षा, पोषाहार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानव संसाधन की रणनीति पर आलेख तैयार करने के लिए 7 दिसंबर 1992 से 28 दिसंबर 1992 तक विश्वबैंक, वाशिंगटन की यात्रा की।

अध्ययन-अवकाश

1. डॉ. कुसुम के. प्रेमी

'देश के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों के बच्चों के शैक्षिक विकास की समस्या और रणनीतियां' विषय पर पुस्तक लिखने के लिए 1 मई 1992 से 31 अगस्त 1992 तक अध्ययन- अवकाश दिया गया।

2. डा. सुषमा भागिया

ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय, कनाडा के सहयोग से 'प्रवर्तन और वर्ष 2000 की पाठ्यचर्या' विषय पर पुस्तक लिखने के लिए अध्ययन-अवकाश को 7 मई 1992 तक बढ़ाया गया।

परिसर सुविधाएं

संस्थान के पास चार कार्यालय भवन हैं; पूरी तरह सुसज्जित और स्नानघरों से युक्त 48 कमरों वाला एक सात मंजिला छात्रावास है और एक आवासीय परिसर है जिसमें टाइप I के 16 क्वार्टर, टाइप II, III, IV और V के 8-8 क्वार्टर तथा एक निदेशक-आवास है।

छात्रावास भवन के विस्तार और उन्नयन का काम इस समय पूरी तेजी से जारी है और शीघ्र ही उसके पूरे होने की आशा है। पूरा होने के बाद इसमें वार्डेन का आवास, संकाय के लिए अतिथि आवास की सुविधा और अतिरिक्त ब्लाक होंगे। भोजन कक्ष का विस्तार और मनोरजन कक्ष आदि भी इन कार्यों में शामिल हैं।

वित्त

इस वर्ष संस्थान को 166.00 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ (इसमें गैर योजना अनुदान 93.00 लाख और योजना अनुदान 73.00 लाख रुपये का था) जबकि 1991-92 में अनुदान में 185.25 लाख रुपए (गैर योजना के अंतर्गत 95.28 लाख और योजना के 89.97 लाख रुपए) प्राप्त हुए थे। वर्ष के आरंभ में संस्थान के पास 25.00 लाख रुपए (गैर योजना के अंतर्गत 8.50 लाख और योजना 16.50 लाख रुपये) की रकम थी। वर्ष में कार्यालय और छात्रावास की प्राप्तियां 22.70 लाख रुपये रही। इस प्रकार कुल प्राप्ति 213.70 लाख रुपए रही। वर्ष के दौरान सरकारी अनुदानों में से कुल 178.69 लाख रुपये खर्च हुए जबकि 1991-92 के दौरान यह खर्च 193.02 लाख रुपये था।

संस्थान के पास 54.59 लाख रुपये की रकम बकाया थी और वर्ष के दौरान अन्य संगठनों द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों/अध्ययनों के लिए 23.59 लाख रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्राप्त हुई। वर्ष के दौरान प्रायोजित कार्यक्रमों और अध्ययनों पर 36.41 लाख रुपये व्यय हुए।

वर्ष के दौरान सरकारी अनुदानों में से कुल (योजना और गैर योजना, दोनों मदों में) कुल 178.69 लाख रुपये खर्च किए गए जबकि 1991-92 में यह खर्च 193.02 लाख रुपए का था। इसके अलावा अन्य संगठनों से सहायता प्राप्त कार्यक्रमों और अध्ययनों पर 37.41 लाख रुपये खर्च किए गए। सरकारी अनुदानों और सहायता प्राप्त कार्यक्रमों अध्ययनों, दोनों के अंतर्गत कुल मिलाकर 215.10 लाख रुपए की राशि खर्च हुई।

संस्थान की वार्षिक लेखा का लेखापरीक्षण संबंधी वक्तव्य और लेखा परीक्षण के प्रमाणपत्र परिशिष्ट VI में दिए गए हैं।

अनुबंध-I

वर्ष 1992-93 में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशिविरों/संगोष्ठियों/सम्मेलनों की सूची

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	तिथि तथा अवधि	प्रतिभागियों की संख्या
1	2	3	4
डिप्लोमा कार्यक्रम			
राष्ट्रीय डिप्लोमा		8 फरवरी 1992 से	14
1.	जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में बारहवां डिप्लोमा कार्यक्रम, दूसरा चरण (विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा एकक)	10 मई 1992 (40 दिन)	
	चरण III	28-31 जुलाई 1992 (4 दिन)	14*
2.	जिला शिक्षा अधिकारियों व अन्य कार्मिकों के के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन में तेरहवां डिप्लोमा (चरण I) (विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा एकक)	2 नवंबर 1992 से 29 जनवरी 1993 (89 दिन)	25
	चरण II	30 जनवरी 1993 से 29 अप्रैल 1993 (61 दिन)	25*
योग	2	194	39

1	2	3	4
अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा			
3.	शैक्षिक योजना और प्रशासन में आठवां अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम (चरण I तथा चरण II) (अंतर्राष्ट्रीय एकक)	3 फरवरी 1992 से 2 अगस्त 1992 (124 दिन)	13
4.	शैक्षिक योजना ओर प्रशासन में नौवां अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम (चरण-I)	1 फरवरी 1993 से 30 अप्रैल 1993 (59 दिन)	6
योग	**2**	**183**	**19**
II. विषयगत कार्यक्रम			
विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के लिए संस्थागत योजना			
5.	केंद्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन के सहयोग से तिब्बती केंद्रीय विद्यालयों के प्रमुखों, प्रधानाध्यापकों व प्राचार्यों के लिए शैक्षिक योजना तथा प्रबंध पर बैठक व प्रशिक्षण कार्यक्रम, (अंतर्राष्ट्रीय एकक)	13-16 अप्रैल 1992 (4 दिन)	24
6.	माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रमुखों के लिए संस्थागत योजना तथा प्रबंध में दूसरा अभिविन्यास कार्यक्रम (शैक्षिक प्रशासन एकक)	8-26 जून 1992 (19 दिन)	22
7.	केंद्रीय विद्यालयों के वरिष्ठ प्राचार्यों और शिक्षा अधिकारियों के लिए उनकी उभरती भूमिकाओं के परिप्रेक्ष्य में अभिविन्यास पाठ्यक्रम (अंतर्राष्ट्रीय एकक)	2-6 नवंबर 1992 (5 दिन)	20
8.	ए.ई.जी.सी. अणुशक्ति नगरबंबई के कनिष्ठ महाविद्यालयों व केंद्रीय विद्यालयों के प्राचार्यों के लिए शिक्षा में उत्कृष्ट प्रबंध पर कार्यशाला (अणुशक्ति शैक्षिक सोसाइटी, बंबई के सहयोग से) (क्षेत्र आधारित-बंबई) (अंतर्राष्ट्रीय एकक)	18-19 मई, 1992 (12 दिन)	37
योग	**4**	**40**	**103**

1	2	3	4
प्र.शि.सा. और व्यष्टि स्तरीय योजना			
9.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के शिक्षा शिक्षा विभाग के सहयोग से द्वीप समूह के संसाधन व्यक्तियों के लिए सब के लिए शिक्षा की व्यष्टि स्तरीय योजना विषय पर अविन्यास कार्यक्रम (क्षेत्र आधारित–पोर्टब्लेयर) (प्रा.प्र. एकक/शैक्षिक नीति एकक)	14-25 सितंबर 1992 (12 दिन)	26
10.	जिला स्तर पर प्रां.शि.सार्वजनीकरण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (शैक्षिक योजना एकक)	7-12 सितंबर 1992 (6 दिन)	11
11.	शैक्षिक सांख्यिकी में प्रतिदर्श सर्वेक्षण तकनीक के इस्तेमाल पर राष्ट्रीय कार्यशाला (शैक्षिक योजना एकक)	1-3 मार्च, 1993 (3 दिन)	24
योग	**3**	**21**	**61**
जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की योजना तथा प्रबंध (डाइट)			
12.	जि.शि.प्र.सं. के संकाय की योजना तथा प्रबंध विभाग के कर्मिकों के लिए पांचवां प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रा.प.एकक)	7-23 अक्तूबर 1992 (17 दिन)	28
13.	जि.शि.प्र.सं. (राजस्थान, केरल, तमिलनाडु) के संकाय की योजना तथा प्रबंध शाखा के लिए छठवां प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रा.प्र.एकक)	15 फरवरी 1993 से 5 मार्च, 1993 (19 दिन)	30
योग	**2**	**36**	**58**

1	2	3	4
जि.शि.प्र.सं. के पुस्तकालयों का प्रबंध			
14.	जि.शि.प्र.सं. के पुस्तकालयों की योजना व प्रबंध (पुस्तकालय व प्रलेखन केन्द्र)	14-25 सितंबर 1992 (12 दिन)	15
	योग 1	**12**	**15**
अनौपचारिक/प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता			
15.	राजस्थान में अनौपचारिक शिक्षा के निदेशकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम (क्षेत्र आधारित-उदयपुर) (विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा एकक)	17-20 अगस्त 1992 (4 दिन)	31
16.	साक्षरता व सतत शिक्षा कार्यक्रम के कार्यकर्त्ताओं के लिए योजना तथा प्रबंध में क्षेत्रीय कार्यशाला (यूनेस्को द्वारा प्रायोजित) (विद्यालय व अनौपचारिक शिक्षा एकक)	3-14 अगस्त 1992 (12 दिन)	17
योग	**2**	**16**	**48**
अल्पसंख्यकों और महिलाओं के लिए शिक्षा की योजना व प्रबंध			
17.	अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित संस्थानों के प्रमुखों के लिए शैक्षिक योजना व प्रबंध में अभिविन्यास कार्यक्रम (शैक्षिक नीति एकक)	18-29 मई 1992 (12 दिन)	18
18.	शैक्षिक योजना और प्रबंध में लिंग भेद विरोधी चेतना पर अभिविन्यास कार्यक्रम (अंतर्राष्ट्रीय एकक)	22-26 फरवरी 1993 (5 दिन)	15
19.	शिक्षा और महिला के विकास के लिए क्षेत्रवार योजना पर राष्ट्रीय कार्यशाला (प्रादेशिक प्रणाली एकक)	7-10 दिसंबर 1992 (4 दिन)	34
योग	**3**	**21**	**67**

1	2	3	4
वंचित वर्गों और आदिवासियों की शिक्षा			
20.	दूरवर्ती क्षेत्रों में शिक्षा की योजना और प्रबंध पर कार्यशाला (शैक्षिक नीति एकक)	17-20 नवंबर 1992 (4 दिन)	33
21.	विकलांग बालकों की शिक्षा की योजना संबंधी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए समन्वित क्षेत्र प्रणाली पर जिला स्तर के शिक्षा अधिकारियों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम (क्षेत्र आधारित—मैसूर) (विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा एकक)	21-23 सितंबर 1992 (3 दिन)	21
22.	जिलों/राज्यों के आदिवासी कल्याण अधिकारियों और आश्रम विद्यालयों के प्रमुखों के लिए सांस्थानिक योजना व प्रबंध में अभिविन्यास कार्यक्रम (शैक्षिक प्रशासन एकक)	11-22 जनवरी 1993 (12 दिन)	31
23.	'आंध्र प्रदेश के आदिवासी जिलों– खमम्म और गुंटूर में एक मात्र शिक्षक कार्यप्रणाली' परियोजना के क्षेत्रीय अन्वेषकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम (शैक्षिक प्रशासन एकक)	17-21 अगस्त 1992 (5 दिन)	3
योग	**4**	**24**	**88**
शिक्षा की जिला स्तरीय योजना			
24.	जिला स्तरीय शैक्षिक योजना पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (शैक्षिक योजना एकक और प्रादेशिक प्रणाली एकक द्वारा आयोजित)	6-11 जुलाई 1992 (6 दिन)	8
योग	**1**	**6**	**8**

1	2	3	4
आर्थिक नीतियां और शिक्षा में संसाधनों का उपयोग			
25.	आठवीं पंचवर्षीय योजना में नई आर्थिक नीतियां और शैक्षिक वित्त पर बैठक (शैक्षिक वित्त एकक)	28-30 सितंबर 1992 (3 दिन)	43
26.	विद्यालयों में संसाधन उपयोग पर दूसरा अभि-विन्यास कार्यक्रम (शैक्षिक प्रशासन एकक)	1-5 फरवरी 1992 (5 दिन)	25
27.	शिक्षा पर जनसांख्यिकीय दबाव विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (शैक्षिक योजना एकक)	15-19 मार्च 1993 (5 दिन)	3
28.	भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का शिक्षा पर प्रभाव विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (शैक्षिक योजना एकक)	4-6 जनवरी 1993 (3 दिन)	54
29.	शैक्षिक सांख्यिकी और विशेष रूप से भारत में वित्तीय सांख्यिकी पर संगोष्ठी (शैक्षिक वित्त एकक)	1-2 फरवरी 1993 (2 दिन)	50
योग	5	18	175
शिक्षा की नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा			
30.	संशोधित नीतियां और कार्ययोजना 1992 के क्रियान्वयन पर राष्ट्रीय कार्यशाला (शैक्षिक नीति एकक)	16-19 मार्च 1993 (4 दिन)	7
योग	1	4	7
शैक्षिक योजना और प्रबंध में संगणक का प्रयोग			
31.	कोप परियोजना के क्रियान्वयन पर अभिविन्यास कार्यक्रम (कोप परियोजना)	4-5 जून 1992 (2 दिन)	4

1	2	3	4
32.	प्रबंध सूचना प्रणाली में संगणक प्रयोग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (शैक्षिक योजना एकक)	16-27 नवंबर 1992 (12 दिन)	10
33-35	कोप कक्ष (दिल्ली) के लिए तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम	3 दिसंबर 1992 (1 दिन)	14
	(कोप परियोजना–तीन कार्यक्रम)	4 दिसंबर 1992 (1 दिन)	28
		21-31 दिसंबर 1992 (11 दिन)	7
योग	**5**	**27**	**63**

उच्च शिक्षा की योजना और प्रबंध

36.	उत्कल विश्वविद्यालय के सहयोग से उत्कल विश्व-विद्यालय, उड़ीसा में स्वायत्त योजनाओं के क्रियान्वयन पर अभिविन्यास कार्यक्रम (क्षेत्र आधारित-भुवनेश्वर) (उच्च शिक्षा एकक)	3-6 जून 1992 (4 दिन)	36
37.	राजस्थान में महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों व उप-प्रधानाचार्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम (क्षेत्र आधारित-अजमेर) (उच्च शिक्षा एकक)	13-18 जुलाई 1992 (6 दिन)	31
38.	महिला महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों के लिए शैक्षिक योजना और प्रबंध में अभिविन्यास कार्यक्रम (एस.एन.डी.टी.महिला विश्वविद्यालय के सहयोग से (क्षेत्र आधारित-बबंई) (उच्च शिक्षा एकक)	17-29 अगस्त 1992 (13 दिन)	24
39.	मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, राजस्थान और महाविद्यालय शिक्षा निदेशालय के सहयोग से शैक्षिक प्रशासन पर अभिविन्यास कार्यक्रम (क्षेत्र आधारित-उदयपुर) (उच्च शिक्षा एकक)	1-7 सितंबर 1992 (7 दिन)	36

1	2	3	4
40.	अकादमिक स्टाफ कालेज (राजस्थान विश्वविद्यालय) और महाविद्यालय शिक्षा निदेशालय के सहयोग से शैक्षिक प्रशासन पर अभिविन्यास कार्यक्रम (क्षेत्र आधारित-जयपुर) (उच्च शिक्षा एकक)	2-8 नवंबर 1992 (7 दिन)	30
41.	स्वायत्त महाविद्यालयों की योजना और प्रबंध पर अभिविन्यास कार्यक्रम (उच्च शिक्षा एकक)	23 नवंबर 1992 से 4 दिसंबर 1992 (13 दिन)	50
42.	स्वायत्तता की योजना पर अभिविन्यास कार्यक्रम (क्षेत्र आधारित-जयपुर) (उच्च शिक्षा एकक)	15-16 जनवरी 1993 (2 दिन)	50
43.	महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन पर राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम (उच्च शिक्षा एकक)	25 जनवरी 1993 से 12 फरवरी 1993 (19 दिन)	49
44.	शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े 100 जिलों में महाविद्यालयों के विकास पर अभिविन्यास कार्यक्रम (उच्च शिक्षा एकक)	22-28 मार्च 1993 (7 दिन)	12
45.	योजना और प्रशासन विषय पर अकादमिक स्टाफ कालेजों के निदेशकों की बैठक (उच्च शिक्षा एकक)	23-24 जुलाई 1992 (2 दिन)	38
योग	**10**	**80**	**356**

दूरवर्ती शिक्षा की योजना और प्रबंध

46.	दूरवर्ती शिक्षा की योजना और प्रबंध पर राष्ट्रीय कार्यशाला (शैक्षिक प्रशासन एकक)	9-11 सितंबर 1992 (3 दिन)	19
योग	**1**	**3**	**19**

1	2	3	4
अन्य कार्यक्रम			
47.	संसाधन व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण कार्यप्रणाली पर अभिविन्यास कार्यक्रम (शैक्षिक प्रशासन एकक)	15-19 फरवरी 1993 (5 दिन)	22
48.	यूनेस्को द्वारा प्रायोजित चीन के वरिष्ठ शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक योजना और प्रशासन पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (शैक्षिक योजना एकक और अंतर्राष्ट्रीय एकक द्वारा)	8 दिसंबर 1992 से 7 जनवरी 1993 (31 दिन)	7
योग	**2**	**36**	**29**
कुल योग	**48**	**721**	**1155**

* इस सूची में पहले से जारी दो डिप्लोमा पाठ्यक्रम शामिल हैं। (एक राष्ट्रीय और एक अंतराष्ट्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम)

नीपा के सहयोग से विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची

1. मध्यप्रदेश के आदिवासी कल्याण विभाग के शिक्षा अधिकारियों के लिए प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा विकेंद्रीकरण और व्यष्टि स्तरीय योजना पर अभिविन्यास कार्यक्रम (25-29 मई 1992)

2. अरुणाचल प्रदेश के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम (शिक्षा विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा इटानगर में दो कार्यक्रमों का आयोजन) 26 मई से 6 जून 1992)

3. प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा भोपाल में मध्य प्रदेश आदिवासी कल्याण विभाग के क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारियों और प्रधानाध्यापकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम (22-26 जून 1992)

4. चंडीगढ़, राज्य शिक्षा संस्थान द्वारा चंडीगढ़ के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्यों के लिए संस्थानिक योजना और मूल्यांकन पर कार्यशाला (21-24 दिसंबर 1992)

5. लोक जुंबिश परियोजना राजस्थान द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारियों के लिए विद्यालय मानचित्रण और व्यष्टि स्तरीय योजना पर जयपुर (8-10 अक्तूबर 1992) और तिलोनिया (22-23 जनवरी 1993) में प्रशिक्षण कार्यक्रम

अनुबंध-II

प्रशिक्षण सामग्रियों की सूची

- शिक्षा में शोधप्रणाली का सिंहावलोकन
- अनुसंधान प्रश्नावलियों/उपकरणों का विकास
- सांख्यिकी आंकड़ों का स्वरूप और प्रायिकता वितरण
- शैक्षिक आंकड़ों की प्रस्तुति और विश्लेषण
- विद्यालय शिक्षा से संबंधित विस्तृत सांख्यिकी
- बहिर्वेशन और तथ्य विश्लेषण
- पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा
- सबके लिए शिक्षा का परिप्रेक्ष्य
- शैक्षिक सांख्यिकी में प्रतिदर्श सर्वेक्षण तकनीक : विधियां और व्यवहार
- विकास : संकल्पना और दर्शन
- शैक्षिक योजना के प्रकार
- शिक्षा की मांग : संकल्पना, माध्यम और माप
- शैक्षिक योजना के लिए जनसांख्यिकीय विश्लेषण
- योजना : आर्थिक, शैक्षिक तथा जनशक्ति–संकल्पना माध्यम और दर्शन
- विकास का प्ररिप्रेक्ष्य : संकल्पना, दर्शन और अनुभव
- नई आर्थिक नीतियां और शिक्षा में वित्त की व्यवस्था
- जिला स्तर पर शैक्षिक योजना के लिए संदर्शिका
- नामांकन प्रक्षेपण के आधार पर छात्रों की संख्या में उतार-चढ़ाव
- शिक्षा सें आंतरिक क्षमता
- शिक्षा में विकेंद्रीकरण और सूक्ष्म स्तरीय योजना : प्रत्यात्मक व प्रासंगिक विचार
- शैक्षिक कार्यक्रमों का संचारेक्षण और मूल्यांकन : संकल्पना और विधियां
- सबके लिए शिक्षा : विकासशील देशों में प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा की भूमिका
- शैक्षिक गुणवत्ता के संकेतक
- शैक्षिक समता के माप की विधियां
- संचारेक्षण और मूल्यांकन : संकल्पना, माध्यम, बेसिक शिक्षा से सबंधित सिद्धांत और पद्धति
- विद्यालय मानचित्रण : विकासशील देशों के लिए पाठ
- शैक्षिक योजना : संकल्पना, माध्यम, प्रक्रिया, उत्पाद और कारक
- शैक्षिक विकास में विषमताएं : विकासशील देशों के अनुभव और नीतिगत परिप्रेक्ष्य
- शैक्षिक विकास के लिए संसाधन की मांग और उपयोग : सार्वभौमिक परिप्रेक्ष्य
- शैक्षिक विकास में संसाधन उपयोग के प्रतिमान और लागत प्रभाविता : सार्वभौमिक परिप्रेक्ष्य
- शिक्षा प्रणाली के प्रबंध में संरचना और संयोजन
- बेसिक शिक्षा के लिए वित्त की व्यवस्था
- विकास का प्रबंध : अंतर्राष्ट्रीय अनुभव
- शैक्षिक प्रबंध : संकल्पना, सिद्धांत और माध्यम

1992–93

- शैक्षिक नेतृत्व से जुड़े मुद्दे : शिक्षा में अंतर्वैयक्तिक संबंध
- विकासशील देशों में कार्य-संस्कृति की संकल्पना
- कार्य के लिए अभिप्रेरणा–अंतर्राष्ट्रीय अनुभव
- शैक्षिक प्रबंध सूचनाप्रणाली
- शैक्षिक संगठनों से संबंधित विवादों के प्रबंध कौशल
- विकास का प्रसार : प्रबंधकीय माध्यम
- भारत में विकेंद्रीकृत शिक्षा के सिद्धांत और व्यवहार : वर्तमान स्थिति
- मानव विकास सूचकांक

अनुबंध–III

संकाय का अकादमिक योगदान

डॉ. जी. डी. शर्मा

पुस्तकें, प्रकाशन, अनुसंधान लेख और रिपोर्टें

"हायर एजुकेशन : रिसोर्स ऑर पालिसी क्रंच", *यूनीवर्सीटी न्यूज़,* 1992

"राइट टू एजुकेशन : कोर्ट सक्सीडेड, हेव्यर अकादमिया फेल्ड", *यूनीवर्सीटी न्यूज़,* 1992

"क्वालिटी एसुरेंस इन चेंजिंग वर्ल्ड, हायर एजुकेशन एट क्रॉसरोड", ग्लोबल सम्मेलन, कनाडा में प्रो. एस. के. खन्ना के साथ (26-28 मई, 1992)

"स्टाफ् डवलपमेंट प्रोग्राम इन हायर एजुकेशन : एन इंडियन एक्सपिरियंस", सी.पी.डी.एच.ई. नई दिल्ली, कॉमनवेल्थ आफ लर्निंग व यू.जी.सी. नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित

"स्टाफ् डवलपमेंट प्रोग्राम इन हायर एजुकेशन : एन इंडियन एक्सपिरियंस" कामनवेल्थ आफ लर्निंग यू.जी.सी.सी.पी.डी. एच.ई, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सम्मेलन में प्रस्तुत

"चेंजिंग स्निारिओ आफ हायर एजुकेशन इन नाइनटीज़ : इंडिया", प्रो.एस. के खन्ना के साथ 1992 (मिमियोग्राफ़)

प्रशिक्षण सामग्री

सांस्थानिक योजना पर माड्यूल

मौजूदा संसाधनों का प्रभावशाली उपयोग

आंतरिक दक्षता के संकेतक

परामर्श और अकादमिक सहयोग

प्रस्तावित मिजोरम विश्वविद्यालय के लिए गठित समिति की सिफ़ारिशों पर रिपोर्ट की तैयारी-एजुकेशनल कंसल्टेंट आफ इंडिया लिमिटेड

चीन सरकार के विद्वानों का चयन-मानव संसाधन विकास मंत्रालय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग—स्वायत महाविद्यालयों और अकादमिक स्टाफ़ महाविद्यालयों की समीक्षा के लिए गठित समिति

आंध्र प्रदेश में उच्च शिक्षा की योजना-राज्य उच्च शिक्षा परिषद, आंध्रप्रदेश

राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय-उच्च शिक्षा व्यावसायिक विकास केंद्र (सी. पी. डी. एच. ई.), मद्रास विश्वविद्यालय-स्वायत्त महाविद्यालय आयोग, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय-अकादमिक स्टाफ़ महाविद्यालयों की सलाहकारी समिति के विशेषज्ञ, राजस्थान लोक सेवा आयोग, दौलत राम कालेज-शासी निकाय के सदस्य

अन्य अकादमिक गतिविधियां

पंद्रह विभिन्न संस्थानों, मुख्य रूप से अकादमिक स्टाफ़ कालेजों, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा निदेशक राजस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में उद्घाटन/समापन भाषण और व्याख्यान

1992–93

डॉ. के. जी. विरमानी

प्रशिक्षण सामग्री

विकास का परिप्रेक्ष्य : संकल्पनाएं, दर्शन और अनुभव (सह-लेखक)

विकास का प्रसार : सार्वभौमिक परिप्रेक्ष्य में संकल्पनाएं, वर्तमान स्थिति और माध्यम (सह लेखक)

शैक्षिक प्रबंध : संकल्पनाएं, सिद्धांत और माध्यम

शैक्षिक प्रबंध सूचना प्रणाली

बेसिक शिक्षा का प्रबंध : संरचना, अभिकरण और अधिकर्त्ता

शिक्षा की विकेंद्रीकृत प्रणाली का प्रबंध : समाजवादी व अन्य ऐसे देशों के संदर्भ में इस संकल्पना की कार्यक्षमता

व्याख्यान नोट

विकास का प्रबंध : अंतर्राष्ट्रीय अनुभव

शैक्षिक प्रबंध : संकल्पना, सिद्धांत और माध्यम

शैक्षिक नेतृत्व के मुद्दे : शिक्षा में अंतर्वैयक्तिक संबंध

विकासशील देशों में कार्यसंस्कृति

कार्य के लिए अभिप्रेरणा-अंतर्राष्ट्रीय अनुभव

शैक्षिक प्रबंध सूचनाप्रणाली

शैक्षिक संगठनों से संबंधित विवादों के प्रबंध कौशल

विकास का प्रसार : प्रबंधकीय माध्यम

परामर्श और अकादमिक सहयोग

सदस्य, शासी परिषद्, दिल्ली रा.शै.अ.प्र.प.

सदस्य, कार्यकारी समिति, दिल्ली, रा.शै.अ.प्र.प.

सदस्य, वित्तीय और संस्थागत मामलों की स्थाई समिति, दिल्ली

सदस्य, कार्यक्रम सलाहकार समिति, रा.शै.अ.प्र.प., मोती बाग (रा.शै.अ.प्र.प. दिल्ली)

विभिन्न चयन समितियों के सदस्य

अध्यन, विद्यालय प्रबंध समिति, केंद्रीय विद्यालय पुष्प बिहार, नई दिल्ली

सदस्य, विद्यालय प्रबंध समिति, केंद्रीय विद्यालय

मस्जिद मोठ, नई दिल्ली

अन्य अकादमिक गतिविधियां

कई शैक्षिक व सामान्य प्रबंध संस्थानों में संकाय सदस्य के रूप में दौरा किया

प्रो. श्रीप्रकाश

पुस्तकें, प्रकाशन, अनुसंधान लेख और रिपोर्टें

"स्पेशियल लोकेशनल पैटर्न आफ एजुकेशनल इंस्टीटयूशन्स इन इंडिया-ए स्टडी आफ डाइवर्जेन्स बिटवीन ओपटिमल एंड एक्चूयल पैटर्न्स, *रीजनल डिसपैरीटी इन एजुकेशनल डेवलपमेंट,* संपादक : एस.सी.नुना, नीपा 1993

जनर्लाइस्ड डॉयनामिक लिंकेज पैटर्न एज ए बेस आफ कनवडर्जेंस आफ अनवैलेंस्ड टू बैलेस्ड ग्रोथ थ्योरी : सब मैथडोलौजिकल एंड थ्योरीटिकल इशूज विद एपलिकेशन टू इंडियन इकॉनमी" *इंटरनेशनल जर्नल आफ डवलपमेंट प्लानिंग लिटरेचर,* जिल्द 6, अंक 3-4

'यूनीवर्सलाइजेशन आफ एलिमेंटरी एजुकेशन : ए सिंपल जर्नल इक्यूलिविरियम टाइप पॉलिसी मॉडल" *मैनपावर जर्नल,* जिल्द XXVIII, अंक-2.

"डैमोग्रॉफिक ट्रांजीशन इन इंडिया एंड इट्स इंपलिकेशन फॉर एजुकेशन", *पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन,* जिल्द 8, अंक 3-4, जुलाई-अक्तूबर 1992

"ए डिकंपोजीशन माडल आफ ग्रोथ आफ लिटरेसी इन इंडिया" *जर्नल आफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन,* जिल्द 5 अंक 2

"इंडिकेटर्स आफ एजुकेशनल डवलपमेंट : एनालिसिस आफ एवरेज कंपलीटेड स्कूल इयर्स इन इंडिया, *जर्नल आफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन,* जिल्द VII, अंक 1, जनवरी 1993

"नो डवलपमेंट स्ट्रेटजी इज रिलेवेंट फार आल टाइम्स" साक्षात्कार, अमृत संदेश, रायपुर मध्य प्रदेश, 16 दिसंबर 1992

प्रशिक्षण सामग्री

शैक्षिक सांख्यिकी में प्रतिदर्श सर्वेक्षण तकनीक : तकनीक और व्यवहार

विकास : संकल्पना, और दर्शन

शैक्षिक योजना : संकल्पना, माध्यम, प्रक्रिया, उत्पाद और कारक

शैक्षिक योजना के प्रकार

शिक्षा की मांग : संकल्पना, अभिगम व माप

शैक्षिक योजना के लिए जनसांख्यकीय दबाव

परामर्श और अकादमिक सहयोग

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–विश्वविद्यालय स्तर पर **अर्थशास्त्र** में शिक्षण और अनुसंधान के स्तर में सुधार; **वाणिज्य**, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के अवस्नातक स्तर के **पाठयक्रम** के व्यावसायीकरण पर गठित समिति को परामर्श **और** अकादमिक समर्थन

भारतीय अनुपयुक्त अर्थशास्त्र अनुसंधान परिषद–"केंद्रीय सरकार के संस्थानों/प्रयोगशालाओं में अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में कार्यरत मानवशक्ति की प्रवृत्तियां" परियोजना की सलाहकार समिति; यू.एन.डी.पी. के तहत 'मानव विकास संकेतक' अध्ययन की राष्ट्रीय परियोजना सलाहकार समिति

मानव संसाधन विकास मंत्रालय–ज्ञापन तैयान करने के लिए दसवें वित्त आयोग की बैठक में भाग लिया।

योजना आयोग–"साक्षरता के लिए संसाधन"

महाराष्ट्र राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद–जिला शिक्षा अधिकारियों का प्रशिक्षण (प्राथमिक शिक्षा)

विश्व बैंक परियोजना–'उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा' के कार्यान्वयन के मूल्यांकन और संचारेक्षण के उद्देश्य से सांस्थानिक समताओं का मूल्यांकन" पर परियोजना

अन्य अकादमिक गतिविधियां

मार्च 1993 में स्पेन में आगत-निर्गत तकनीक विषय पर आयोजित 10 वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के "रूपांतरण, समन्वयन और संरचनात्मक सामंजस्य" सत्र में "थियोरेटिकल बेस आफ एजुकेशन-इकानॉमी नेक्सस एंड मिथाडॉलाजी फार एकांउटिंग आफ लिंकेज-इफेक्ट इन एन इनपुट-आउटपुट फ्रेमवर्क" शीर्षक से आलेख प्रस्तुत किया; आर्थिक विकास पर आयोजित सत्र की अध्यक्षता की, 'आगत-निर्गत समाश्रयों का संकलन-अंतर्राष्ट्रीय संप्रेक्ष्य' पर विशेषरूप से आयोजित सत्र में विशेष आमंत्रण पर "कंपाइलेशन आफ इनपुट आउटपुट टेबल्स इन इंडिया" विषय पर व्याख्यान दिया।

4-6 जनवरी 1993 के दौरान 'भारतीय अर्थव्यवस्था उदारीकरण और शिक्षा के क्षेत्र में उसके निहितार्थ, विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में "लिबरेलाइजेशन आफ इंडियन इकानॉमी एंड रिलवांस आफ नेहरू–महालनोबिस स्ट्रेटजी आफ डवलपमेंट" विषय पर मुख्य आलेख प्रस्तुत किया।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली में आयोजित संगोष्ठी में "एजुकेशन सब्सिडी इन इंडिया-इसूज आफ सब्सिडी इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर" विषय पर आलेख प्रस्तुत किया। (15 मई 1992)

शैक्षिक प्रबंध पर कार्ययोजना की चर्चा के लिए उत्तरी राज्यों के शिक्षा सचिवों के लिए आयोजित कार्यशाला में भाग लिया, नई दिल्ली (29 अक्तूबर 1992)

रेल परिवहन और अर्थिक विकास पर आयोजित पूर्व-संगोष्ठी कार्यशाला में भाग लिया, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (2 नवंबर 1992)

प्रो. एम. एम. कपूर

पुस्तकें, प्रकाशन, अनुसंधान लेख और रिपोर्टें

नानफार्मल एजुकेश्न इन इंडिया : ऐन इवैल्यूएशन; ए कांप्रेहेंसिव नेशनल लेबल रिपोर्ट; नीपा (1992) मिमियोग्राफ)

डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकेशनल प्लानिंग इन एजुकेशन, एन एनोटेड बिबिलियोग्राफी, नीपा (1992) (मिमियोग्राफ)

प्रशिक्षण सामग्री

शैक्षिक कार्यक्रमों का संचारेक्षण और मूल्यांकन : संकल्पना और विधियां

शिक्षा में विकेंद्रीकरण और व्यष्टि स्तरीय योजना : संकल्पनात्मक और प्रासंगिक विचार

परामर्श और अकादमिक सहयोग

स्वीडन अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (एस.आई.डी.ए)–राजस्थान में सबके लिए शिक्षा के लिए लोक जुंबिश परियोजना में व्यष्टि स्तरीय योजना और विद्यालय मानचित्रण

विश्व बैंक–उत्तर प्रदेश में सबके लिए शिक्षा परियोजना के लिए संस्थानिक क्षमता का अध्ययन

सदस्य, अरुणाचल प्रदेश शैक्षिक प्रशासन कार्य दल, अरुणाचल प्रदेश सरकार

सदस्य, बिहार, जम्मू और कश्मीर व अरुणाचल प्रदेश के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की शिक्षक प्रशिक्षण समर्थ समिति

सदस्य, मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग, की समिति, जि.शि.प्र.सं. स्थापना की पुनरीक्षण योजना

सदस्य, कोप और शैक्षिक सांख्यिकी के सकेंद्रण पर समिति, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

सदस्य, कार्यक्रम सलाहकारी समिति जि.शि.प्र.सं. दिल्ली (राजेंद्र नगर, केशवपुरम और मोती बाग)

सदस्य, आलेख संशोधन समिति, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली

सदस्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्यों और उप-प्राचार्यों के प्रशिक्षण के लिए कार्यदल

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1992) की कार्ययोजना की तैयारी के लिए गठित समिति से जुड़े रहे।

अन्य अकादमिक गतिविधियां

"भारत में शैक्षिक प्रशासन : समस्याएं और परिप्रेक्ष्य" पर भारतीय शिक्षा मंडल, नई दिल्ली द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी, नई दिल्ली (13 सितंबर, 1992)

'प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनीकरण के लिए व्यष्टि स्तरीय योजना : संकल्पना और प्रणाली', मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा व्यष्टि स्तरीय योजना की परियोजनाओं के संचारेक्षण और तैयारी की विधियों के लिए आयोजित विशेषज्ञों की बैठक में भाग लिया। (2-3 फरवरी 1993)

रा.शै.अ.प्र.प. के द्वारा अनौपचारिक शिक्षा में अनुसंधान की स्थिति पर राष्ट्रीय परिसंवाद में 'स्टेटस आफ रिसर्च इन मैनेजमैंट आफ नान फार्मल एजुकेशन इन इंडिया : करैंट स्टेटस एंड फ्यूचर फ्रेमवर्क'। (10-11 फरवरी 1993)

रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों और शिक्षक विद्यालयों के कालेजों के प्राचार्यों के लिए सांस्थानिक योजना पर आयोजित कार्यशाला में भाग लिया। (22 फरवरी 1993)

उत्तर प्रदेश में 'सबके लिए शिक्षा' परियोजना के अंतर्गत विश्व बैंक द्वारा 'परियोजना तैयारी' और 'परियोजना मूल्यांकन मिशन' पर आयोजित बैठकों में भाग लिया।

विदेशी अनुदान द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना के प्रतिपादन के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित बैठकों में भाग लिया।

शिक्षा विभाग, अरुणाचल प्रदेश द्वारा इटानगर में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्यों के लिए आयोजित अभिविन्यास कार्यक्रम में संसाधन व्यक्ति के रूप में कार्य किया। (26 मई से 6 जून 1992)

प्रशासन अकादमी, भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश के आदिवासी कल्याण विभाग के शिक्षा अधिकारियों के लिए आयोजित दो प्रशिक्षण कार्यक्रमों में संसाधन व्यक्ति के रूप में कार्य किया। (25-29 मई 1992 और 22-26 जून 1992)

यूनेस्को द्वारा 'साक्षरता कार्यक्रम के लिए परियोजना योजना और प्रबंध' के संबंध में आयोजित साक्षरता और सतत शिक्षा पर क्षेत्रीय कार्यशाला में संसाधन व्यक्ति के रूप में कार्य किया। (3-14 अगस्त, 1992)

रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा राजस्थान में अनौपचारिक शिक्षा के मूल्यांकन में संसाधन व्यक्ति के रूप में कार्य किया। (14-15 सितंबर, 1992)

'अंडमान और निकोबार रेडियो, पोर्टब्लेयर से 'अंडमान और निकोबार में सबके लिए शिक्षा' पर प्रसारण। (23 सितंबर 1992)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित शिक्षा सचिवों के सम्मेलन में भाग लिया। (29-30 अक्तूबर, 1992)

क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल, रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा जि. शि.प्र.सं. के प्राचार्यों के लिए आयोजित अखिल भारतीय बैठक में भाग लिया। (3-4 नवंबर 1992)

राज्य शिक्षा संस्थान, चंडीगढ़ द्वारा 'सांस्थानिक योजना और मूल्यांकन' विषय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में संसाधन व्यक्ति के रूप में कार्य किया। (21-24 दिसंबर 1992)

विश्व बैंक परियोजना : उत्तर प्रदेश में 'सबके लिए शिक्षा' परियोजना पर प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा की तैयारी के लिए आयोजित बैठक में भाग लिया, लखनऊ। (7-9 जनवरी 1993)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा व्यष्टि स्तरीय योजना परियोजनाओं की तैयारी और संचारेक्षण की विधियों की तैयारी के लिए आयोजित बैठक में संसाधन व्यक्ति के रूप में कार्य किया। (2-3 फरवरी 1993)

डॉ. जया इंदिरसेन

पुस्तकें, प्रकाशन, अनुसंधान लेख और रिपोर्टें

फिलिप जी अल्टबाख और सुमा चिटनीस द्वारा संपादित पुस्तक "रिफोर्म एंड इनोवेशन इन हायर एजुकेशन" में "क्वेस्ट फार क्वालिटी : इंटरवेन्शंस वर्सेस इंपैक्ट" सेज प्रकाशन, 1993, नई दिल्ली

बी.एल. माथुर द्वारा संपादित पुस्तक 'लैंडमार्क्स इन मैनेजमैंट-खंड X, शिक्षा का प्रबंध में "रोल आफ प्रिंसिपल्स फार फैकल्टी डवलपमेंट, अरिहंत प्रकाशन, जयपुर, 1993

"व्हाट आर कालेज प्रिंसिपल्स डुइंग फार फैकल्टी डवलपमेंट?" *न्यू फ्रंटियर्स इन एजुकेशन,* खंड 22, 1992

1992–93

"ह्वाट एल्स रिफामर्स एंड इनोवेशंस इन हायर एजुकेशन *इंडसट्रियल इकानामिस्ट,* खंड 25, 1992

"पर्सीव्ड वर्क एनवायरमेंट आफ वूमैन प्रिंसिपल्स" *यूनीवर्सीटी न्यूज,* खंड 30, 1992

"सिग्निफिकेंट एडवांसेस इन हायर एजुकेशन", *इंडस्ट्रियल इकानामिस्ट,* रजत जयंती विशेषांक, 1993

पुस्तक समीक्षा

फिंशर कोमेरान की पुस्तक "प्लानिंग इंपैरिटिव्स फार दि 1990", जर्नल आफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जुलाई 1992

परामर्श और अकादमिक सहयोग

राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन–छात्र गतिशीलता पर अध्ययन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग–महिला अध्ययन केंद्रों के लिए समीक्षा समिति

अन्य अकादमिक गतिविधियां

सिंगापुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में अकादमिक विनिमय और संस्था निर्माण पर आयोजित कार्यशाला में भाग लिया तथा भारतीय तकनीक संस्थानों में छात्र गतिशीलता पर आलेख प्रस्तुत किया। (7-10 अप्रैल 1992)

प्रौढ़ कार्य मूल्यों व छात्र अधिगम अभिविन्यास पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया। (मनिटोबा विश्वविद्यालय, विनिपेग, 16 अक्तुबर 1992)

मिशीगन विश्वविद्यालय में छात्र अधिगम में अंतर सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, पर संगोष्ठी।(28 अक्तूबर 1992)

संसद के उपभवन में "पर्यावरण शिक्षा व विकासशील देश" पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया। (12 मई 1992)

एजुकेशन कंसलटेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा "अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की भारत में शिक्षा" : अवसर और रणनीति" पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया। (5 मार्च, 1993)

लोगों में सामजिक चेतना और व्यावसायिक प्रतिक्रिया पर योजना और वास्तुकला विद्यालय द्वारा आयोजित, संगोष्ठी, (23 मार्च 1993)

अध्ययन कुशलताओं के विकास पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया, राष्ट्रीय खुला विद्यालय। (26 मार्च, 1993)

उच्च शिक्षा विकास और अनुसंधान केंद्र, मनिटोवा विश्वविद्यालय, कनाडा में शास्त्री भारतीय कनाडा संकाय अनुसंधान उपाधि के अंतर्गत मानद प्राचार्य

डॉ. एम. मुखोपाध्याय

पुस्तकें, प्रकाशन, अनुसंधान लेख और रिपोर्टें

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए 'मिडिया एंड टैक्नोलोजी' के अप्रैल अंक का संपादन

"एजुकेशनल टैक्नोलोजी" के अप्रैल, मई और जून के अंकों का संपादन

अन्य अकादमिक गतिविधियां

दिनांक 30 मई 1992 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में संगणक शिक्षा के शिक्षण पर एक दिन की कार्यशाला का निर्देशन

मिदनापुर में संपूर्ण साक्षरता कार्यक्रम का समापन

दिनांक 11 अगस्त 1992 को पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले में संपूर्ण साक्षरता कार्यक्रम प्रचार अभियान दल के बाह्य मूल्यांकन पर आयोजित बैठक में भागीदारी

भारत में प्रारंभिक शिक्षा की अतिरिक्त मांगों के प्रबंध पर नीपा में आयोजित संगोष्ठी में भागीदारी

मिदनापुर में संपूर्ण साक्षरता कार्यक्रम का मूल्यांकन कार्य पूरा किया

डॉ. जे.बी.जी. तिलक

पुस्तकें, प्रकाशन, अनुसंधान आलेख और रिपोर्टें

एजुकेशनल प्लानिंग एट ग्रासरूट्स, नई दिल्ली : आशीष पब्लिशिंग हाउस, 1992

रूरल अर्बन इनइक्वालिटीज़ इन एजुकेशन : ए स्टडी आन रिटर्न टू एजुकेशन, ह्यूमन कैपिटल फार्मेशन एंड अर्निंग्स डिफरनशियसंस, मोनोग्राफ श्रृखला सं. 2, धारवाड़ : बहुशास्त्रीय अध्ययन संस्थान, 1992

"बजेटरी रिफार्म्स एंड सब्सीडिज इन हायर एजुकेशन" *इकानामिक एंड पोलिटिकल वीकली* 28 (6) (फरवरी 1993) 245-48

"प्राइवेटाइजेशन आफ हायर एजुकेशन" हायर एजुकेशन इन इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव ' टूवर्डस द टवेंटी फर्स्ट सेंचुरी (संपादक जेड मोरसी एंड पी.जी. अल्टबाख), न्यूयार्क : एडवेंट बुक, और पेरिस : यूनेस्को, 1993, पृ. 59-71 (*जर्नल आफ हायर एजुकेशन* 16 (2) (बसंत 1993) : पृ. 239-58)

"फायनेंसिग हायर एजुकेशन इन इंडिया" *"हायर एजुकेशन रिफार्म इन इंडिया : एक्सपिरियंस एंड पर्सपेक्टिव"* में अध्याय 2 (संपादक एस. चिटनीस एंड पी.जी. अल्टबाख) नई दिल्ली, सेज, 1993, पृ. 41-83.

इ. किंग और एम.ए. हिल द्वारा संपादित *'वूमेंस एजुकेशन इन डवलपिंग कंट्रीज'* में "ईस्ट एशिया", बाल्टीमोर, जान हापकिंस विश्वविद्यालय प्रेस, 1993, पृ. 247-84

"इनवेसटमेंट इन एजुकेशन इन ईस्ट एशिया" *एशियन इकानामिक बुलेटिन* (सिंगापुर) 9 (3) मार्च 1993, पृ. 301-22

"फायनेंसिंग एलिमेंट्री एजुकेशन इन द एर्थ फाइव इयर प्लान", *जर्नल आफ एजुकेशन एंड सोशल चेंज,* 6 (3), अक्तूबर-दिसंबर 1992, पृ. 69-80 (एन.वी. वर्गीस के साथ)

"एजुकेशन एंड वेज अर्निग्स", *इनसाइक्लोपीडिया आफ एजुकेशनल रिसर्च* (मुख्य संपादक : एम.सी. अविकन) न्यूयार्क : मैकमिलन, अमेरीकन शैक्षिक अनुसंधान संघ के लिए, 1992, पृ. 419-23 (जार्ज सकारोपाउलस के साथ)

"इनवेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डवलपमेंट इन इंडिया" *एशियन इकानामिक्स* (दक्षिण कोरिया) संख्या 82 (सितंबर 1992) पृ. 40-65

"फ्राम इकानमिक ग्रोथ टू ह्यूमन डवलपमेंट : ए कमेंट्री आन रिसेंट इंडैक्सेस आफ डवलपमेंट, *"इंटरनेशनल जर्नल आफ सोशल इकानामिक्स* 19 (2), 1992, पृ. 31-42

"डवलपमेंट आफ एजुकेशन इन एशिया", एशियन इकानामीज (दक्षिण कोरिया) सं. 80 (मार्च 1992) पृ. 57-107

"एजुकेशन, हैल्थ, न्यूट्रीशन एंड डैमोग्राफिक चेंजेस : ए रिव्यू आफ एविडेंस आन एशिया, *"इंडियन जर्नल आफ लेबर इकानामिक्स* 35 (2) अप्रैल-जून 1992, पृ. 113-22

"स्टूडेंट लोन्स इन फायनेंसिंग हायर एजुकेशन इन इंडिया" *हायर एजुकेशन* 23 (4) जून 1992, स्टूडेंट लोन्स इन डवलपिंग कंट्रीज" पर विशेषांक (सं. एम. वूडहाल) पृ. 389-404

यूटिलाइजेशन आफ रिर्सोसेज इन एजुकेशन *"एजुकेशनल हेराल्ड* 7 (1) अक्तूबर 1992 (वार्षिक अंक) पृ. 28-33

1992–93

"दि कैपीटेशन की कालेजेस: सम इशू," *जर्नल आफ हायर एजुकेशन* 16 (1) शरद 1992, पृ. 129-36 (*यूनीवर्सीटी न्यूज़* 30 (51) 21 दिसंबर 1992 1-6 में भी प्रकाशित)

"डिस्क्रीमेंट्री प्राइसिंग इन एजुकेशन" *जर्नल आफ एजुकेशन एंड सोशल चेंज* 6 (1) अप्रैल-जून 1992, पृ. 43-67 (एन. वी. वर्गीस के साथ)

इफैक्टस आफ एडजस्टमैंट आन एजुकेशन : ए रिव्यू आफ एशियन एक्सपिरिएंस" ('द इपैक्ट आफ अस्ट्रिटी, एडजस्टमेंट एंड रिस्ट्रकचरिंग आन एजुकेशन : आपशंस फार पालिसी मेकरर्स, डोनर्स एंड इंटरनेशनल कारपोरेशन' पर यूनेस्को नीतिगत परिचर्चा आलेख के लिए पृष्ठभूमि आलेख, पेरिस : यूनेस्को (जनवरी 1993)

"इकानामिक रिफार्म्स एंड इनवेस्टमेंट पोलिसीज इन एजुकेशन", राजस्थान आर्थिक संघ के रजत जयंती वर्ष सम्मेलन में विशेष व्याख्यान, जयपुर, राजस्थान विश्वविद्यालय (12-14 मार्च 1993) (मिमियो)

"एजुकेशन एंड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट", *प्रोसपेक्टस* (यूनेस्को) 22 (4) 1992 (प्रेस में)

"फंडिंग हायर एजुकेशन : सम इशूज एंड प्रोपोसल", विश्वविद्यालयों के वित्तीय और अकादमिक प्रशासन पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी : गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान (1993 मार्च) (मिमियोग्राफ)

"एजुकेशन एंड अनइंप्लायमेंट इन इंडिया," *न्यू एजुकेशन जर्नल/एजुकेशन एंड सोसाइटी,* 1992 (प्रेस में)

"एजुकेशन एंड पोलिटिकल डवलपमेंट इन एशिया" तुलनात्मक शिक्षा पर आठवीं विश्व कांग्रेस, प्राग, चैकोस्लाविया, चार्ल्स विश्वविद्यालय (जून 1992) (मिमियोग्राफ)

पुस्तक समीक्षा

"बंगलादेश : लोकेशनल एंड टैक्नोलोजिकल रिव्यू" (विश्व बैंक) *इकानामिक्स आफ एजुकेशन रिव्यू* 11 (3) 1992, पृ. 272-73

'द चाइल्ड एंड द स्टेट इन इंडिया' (एम. वाइनर) *जर्नल आफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन* 30 (2) 1992 पृ. 77-78

'थींकिग अबाउट ग्रोथ' (एम. अबरामोवित्ज) और रिस्टोरिंग इकानामिक इक्यूलिबिरियम (टी. डबल्यू शूल्ज) *जर्नल आफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन* 7 (1) जनवरी 1993, पृ. 143-46

"इकानामिक चैलेंजेस इन हायर एजुकेशन" (सी.टी. क्लोफेल्टर) और कीपींग कालेजस अफोंडेबल (एम.एस. मैकपरसन और एम.ओ. स्कैपिरो), *जर्नल आफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन* 6 (3) जुलाई 1992, पृ. 326-27

"फायनेंसिंग आफ एजुकेशन" (एम. मुजामिल) *एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज,* 1992

"इकानामिक वैल्यू आफ एजुकेशन" (सं.एमब्लाग.) और इकानामिक्स, कल्चर एंड एजुकेशन : मार्क ब्लाग के सम्मान में निबंध (सं.जी.के.शा) *जर्नल आफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन* 6 (2) अप्रैल 1992, पृ. 213-16

'एजुकेशनल फार डवलपमेंट' (जी सकारोपाउलस एंड एम. वूडहाल), *जर्नल आफ सोशल एंड एकानामिक स्टडीज* (1992-93)

प्रशिक्षण सामग्री

नई आर्थिक समस्याएं और शिक्षा के लिए वित्त की व्यवस्था (नीपा में आयोजित संगोष्ठी के लिए)

शिक्षा में संसाधनों का प्रभावी उपयोग (नीपा में आयोजित कार्यशाला के लिए)

परामर्श और अकादमिक सहयोग

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की विभिन्न समितियों के लिए

अर्थशास्त्रीयों और शिक्षाविदों के साथ दसवें वित्त आयोग की बैठक में भाग लिया।

शिक्षा, समन्वय और अंतराष्ट्रीय सहयोग पर विशेषज्ञों की परामर्शकारी बैठक के उपसभापति

सत्यवती कालेज और इंदिरा गांधी खेल और भौतिक शिक्षा संस्थान के शासी निकाय के सदस्य (दिल्ली विश्वविद्यालय)

अन्य अकादमिक गतिविधियां

उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में विश्वविद्यालयों के अकादमिक और वित्तीय प्रशासन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया। इलाहाबाद : गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान और भारतीय आर्थिक शोध संस्थान (23-24 मार्च 1993)

राजस्थान आर्थिक संघ के रजंत जयंती सम्मेलन में भाग लिया। जयपुर : राजस्थान विश्वविद्यालय (12-14 मार्च 1993) (विशेष व्याख्यान दिया)

शैक्षिक सांख्यिकी विशेष रूप से वित्तीय सांख्यिकी पर नई दिल्ली : राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान में आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया। (1-2 फरवरी 1993)

भारतीय समाज में श्रमिक अर्थव्यवस्था पर आयोजित वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (2-4 जनवरी 1993)

'जनशक्ति और रोजगार का आर्थिक पुर्नगठन पर प्रभाव' पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया। भारतीय अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान (3-4 दिसंबर 1992)

'शिक्षा एक मूलभूत अधिकार' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय विचारमंच में भाग लिया। नई दिल्ली : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय विश्वविद्यालय संघ (5-6 सितंबर 1992)

नई आर्थिक नीतियों का जनशक्ति पूर्वानुमान प्रणालियों पर प्रभाव, नई दिल्ली : इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। इंडसट्रियल डवलपमेंट सर्विसेज लिमिटेड (अप्रैल 1992)

शिक्षाविदों और अर्थशास्त्रियों के साथ दसवें वित्त आयोग की बैठक में भाग लिया। नई दिल्ली, विज्ञान भवन (5 मार्च 1993)

'उच्च शिक्षा का वित्तयन' पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित कुलपतियों के सम्मेलन' में भाग लिया। पांडिचेरी : पांडिचेरी विश्वविद्यालय (23 फरवरी 1993)

शिक्षा, समन्वय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेषज्ञों की परामर्श बैठक में भाग लिया ; यूनेस्को व्यू, पेरिस : यूनेस्को, 21-24 सितंबर 1992 (बैठक के उपसभापति के रूप में चयन)

डॉ. श्रीमती कुसुम के प्रेमी

पुस्तकें, प्रकाशन, अनुसंधान लेख और रिपोर्टें

"सोर्स बुक आन एनवायरमैंटल एजुकेशन फार एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन", (सह-संपादन) यूनेस्को (मिमियोग्राफ)

"प्रोटेक्टिव डिस्क्रीमिनेशन एंड रीजनल डीसपैरीटीज इन एजुकेशन', ए केस स्टडी ट्राइब्स इन इंडिया" एस.सी. नूना की पुस्तक *"रीजनल डिसपैरीटीज इन एजुकेशन"* में, 1993

"यूनीवर्सल प्राइमरी एजुकेशन इन रिमोट एरियास : ए केस स्टडी आफ लद्दाख (लेह)" *न्यू फ्रंटियर्स इन एजुकेशन,* खंड XXLI अंक-1, जनवरी-मार्च 1992, अगस्त 1992 में प्रकाशित

"एजुकेशन फार आलः दि कांसर्न एरियास *"डैमोग्राफी इंडिया",* खंड 20, अंक 1, 1991, जुलाई 1992 में प्रकाशित

'इक्युटी एंड एफिशियंसी : फैक्टर्स अफैक्टिंग इंटर्नल एफिशियंसी आफ एजुकेशनल सिस्टम्स इन रिमोट एरियास" *पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन,* खंड 9, अंक 2, 1993

"ट्रेनिंग आफ टीचर्स एजुकेटर्स : प्लानिंग एंड मैनेजमेंट डाइमेंशन" सोर्स बुक आफ एनवायरमेंट एजुकेशन फार टीचर्स एजुकेटर्स, यूनेस्को (मिमियोग्राफ)

"एजुकेशनल सिचुयेशन आफ चाइल्ड इन इंडिया : एन ओवरव्यू" *चाइल्डस इन इंडिया,* एन.आई.पी.पी.सी.डी. (प्रेस में)

"एजुकेशन आफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स : पोलिसीस एंड इशूज" डॉ. आत्मा राम, *इशूज़ इन एजुकेशन* में (प्रेस में)

प्रशिक्षण सामग्री

शिक्षा में विषमता : विकासशील देशों के अनुभव और नीति-प्ररिप्रेक्ष नीपा (मिमियोग्राफ)

परामर्श और अकादमिक सहयोग

महिला अध्ययन विभाग, रा.शै.अ.प्र.प. को विभिन्न अध्ययनों और प्रशिक्षण नियमावली की तैयारी में सहायता व परामर्श; भा.स.वि.अ.प. को अनुसंधान अध्ययनों की समीक्षा में सहायता

सदस्य, कार्यक्रम सलाहकार समिति, जि.शि.प्र.सं., केशवपुरम

सदस्य, शिक्षा समिति, जि.शि.प्र.सं., दिल्ली

अन्य अकादमिक गतिविधियां

रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा "महिला शिक्षा और विकास के वर्गीकरण के लिए प्रशिक्षण नियमावली को अंतिम रूप" देने के लिए आयोजित कार्यशाला में भाग लिया। (29 मार्च से 3 अप्रैल 1993 तक)

जन स्वास्थ्य विभाग, हवाई विश्वविद्यालय द्वारा "स्वास्थ्य सेवाओं का वितरण : सामाजिक-सांस्कृतिक पहलू" पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया। (22-26 जून, 1992)

रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा ग्रामीण और दूरवर्ती क्षेत्रों के वंचित समूहों और लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा के लिए नवाचार प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत प्रमुख कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण सामग्री का विकास (4 और 5 अक्तूबर 1992)

रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा संशोधित "राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कार्ययोजना : महिला समता के लिए शिक्षा" विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लिया। (2-4 दिसंबर 1992)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दिल्ली, बंगलौर और कलकत्ता में कार्य योजना के परिचालन के लिए आयोजित क्षेत्रीय कार्यशालाओं में भाग लिया।

रेडियो पोर्ट ब्लेयर पर "दूरवर्ती क्षेत्रों में शैक्षिक विकास" विषय पर वार्ता

डॉ. (श्रीमती) सुषमा भागिया

पुस्तकें, प्रकाशन, अनुसंधान लेख और रिपोर्टें

'डिसिजन मेकिंग' पर स्वयं अधिगम माड्यूल, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक, दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय

प्रशिक्षण सामग्री

चीन में शैक्षिक योजना और प्रबंध के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए यूनीसेफ द्वारा शैक्षिक योजना और प्रबंध पर प्रायोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 'विकासशील देशों में प्रौढ़ व अनौपचारिक शिक्षा की भूमिका' विषय पर प्रशिक्षण सामग्री का विकास।

शिक्षा और महिला विकास पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में महिला साक्षरता के कार्यक्रमों और प्रौढ़ शिक्षा विकास के अभिकरणों से संबंध विषय पर प्रशिक्षण सामग्री का विकास

परामर्श और अकादमिक सहयोग

दिल्ली में साक्षरता गतिविधियों की संपूर्ण साक्षरता अभियान के लिए मूल्यांकन प्रणाली विकसित करने के संदर्भ में दिल्ली साक्षरता समिति को व्यावसायिक समर्थन (11-25 नवंबर 1992)

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, भारत सरकार को संपूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के लिए राज्य संसाधन केंद्रो के कार्मिकों के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में अकादमिक संसाधन सहायता, भुवनेश्वर (23-27 मार्च 1993)

अन्य अकादमिक गतिविधियां

दिल्ली में संपूर्ण साक्षरता अभियान के लिए मूल्यांकन प्रणाली तैयार करने के लिए दिल्ली साक्षरता समिति द्वारा अनुसंधान प्रस्तावों के विकास के माध्यम से साक्षरता गतिविधियों की मजबूती प्रदान करने के लिए आयोजित बैठकों में भाग लिया। (11-25 नवंबर 1992)

भारतीय राष्ट्रीय आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दक्षिण और मध्य एशिया में यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए राष्ट्रीय आयोग की उप-क्षेत्रीय बैठक में आए पंद्रह विद्वानों के साथ परिचर्चा में भाग लिया। (2 फरवरी 1993)

चीन गणराज्य के वरिष्ठ शैक्षिक अधिकारियों के लिए यूनीसेफ द्वारा शैक्षिक योजना और प्रबंध पर प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में संसाधन व्यक्ति के रूप में कार्य किया और विकासशील देशों में प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा भूमिका पर आलेख प्रस्तुत किया। (8 दिसंबर 1992 से 7 जनवरी 1993)

"सबके लिए शिक्षा में भूमिका और अनुकरण", "परिवर्तन का प्रबंध" और "समय प्रबंध" पर प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संपूर्ण साक्षरता कार्यक्रम के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण पर आयोजित कार्यक्रम में आलेख प्रस्तुत किया, भुवनेश्वर (23-27 मार्च, 1993)

डॉ.आर.एस. शर्मा

पुस्तकें, प्रकाशन, अनुसंधान लेख और रिपोर्टें

पुस्तक समीक्षा

"फिफ्टी इयर्स आफ इंडियन जर्नल आफ एडल्ट एजुकेशन" सचदेव जे.एल. सुभाष, डी. *जर्नल आफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन*, जिल्द 5, अंक 3, जुलाई 1991

प्रशिक्षण सामग्री

"शैक्षिक व्यवस्था के प्रबंध में संरचना और संयोजन"

"शैक्षिक योजना का संचारेक्षण और मूल्यांकन"

परामर्श और अकादमिक सहयोग

शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन के शिक्षण और गैर शिक्षण कार्मिकों के लिए पद सृजन के मानदंडो के लिए गठित समिक्षा समिति का सदस्य

शिक्षा विभाग, बिहार सरकार को राज्य में 16 जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना में परामर्श

उपकरणों की समीक्षा : दिल्ली प्रशासन के विद्यालयों के लिए सांस्थानिक समीक्षा; राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा शुरू की गई परियोजना; दिल्ली प्रशासन

परियोजना निष्पादन के लिए उपकरणों और रूपरेखा की विधियां तैयार करने में परामर्श : यू.एन.डी.पी. दक्षिण उड़ीसा शिक्षा परियोजना के लिए शिक्षा विभाग के प्राधिकारियों को परामर्श, उड़ीसा सरकार

रा.शै.अ.प्र.प. शिक्षक प्रशिक्षक विभाग, नई दिल्ली

जि.शि.प्र.स., पुराना राजेंद्र नगर, नई दिल्ली

डी.ए.वी. संस्थान प्रबंध समिति, चित्रगुप्त मार्ग, नई दिल्ली

डॉ.वाई.पी. अग्रवाल

पुस्तकें, प्रकाशन, अनुसंधान और रिपोर्टें

परियोजना रिपोर्ट "डिस्ट्रिक्टवाइज एनालिसीस आफ द

डिस्पैरिटीस इन द लिटरेसी रेट्स आफ शेडुल्ड एंड नान शेडुल्ड पापुलेशन इन इंडिया" (मिमियोग्राफ)

जकार्ता, इंडोनेशिया में प्रस्तुत करने के लिए स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय द्वारा जनसंख्या पर तैयार राष्ट्रीय आलेख में "एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डवलपमेंट" शीर्षक से लेख (मई 1992)

भारत में विश्व बैंक मिशन के लिए "भारत में शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्रों की समीक्षा, विषय पर अध्ययन

परामर्शकारी और अकादमिक सहयोग

सदस्य, राष्ट्रीय केंद्रिक दल, बिहार शिक्षा परियोजना/जनसंख्या और मानव संसाधन विकास विभाग, विश्व बैंक द्वारा "मानव संसाधन विकास" विषय पर आयोजित विशेषज्ञ दल की बैठक में परामशकारी सेवा विश्व बैंक की परियोजना– "उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा" के लिए परामर्शकारी सेवा

एजुकेशनल कांसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के तत्वाधान में उड़ीसा के कोरापुट में शैक्षिक संघटन के विकास के लिए प्रस्तावित परियोजना की रूपरेखा तैयार करने में परामर्शकारी सेवा

अन्य अकादमिक गतिविधियां

जनसंख्या और मानव संसाधन विकास विभाग, विश्वबैंक, वाशिंगटन द्वारा मानव संसाधन विकास विषय पर आयोजित विशेषज्ञदल की बैठक में भाग लिया। (7-28 दिसंबर 1992)

'उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परियोजना' की तैयारी के लिए भारत सरकार, विश्वबैंक, उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य संगठनों की संयुक्त बैठक में भाग लिया।

डी.पी.इ.पी. के प्रतिपादन के संबंध में शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित बैठकों में भाग लिया। (जनवरी-मार्च 1993)

डॉ. (श्रीमती) के. सुधा राव

पुस्तकें, प्रकाशन, अनुसंधान लेख और रिपोर्टें

आटोनामस स्कीम : मिथ्स एंड रियल्टीज : *यूनीवर्सीटीज न्यूज,* ए.आई.यू., मई दिल्ली, मार्च 1993

प्रशिक्षण सामग्री

ऑनस आफ एफलिएटिंग सिस्टम आफ कालेजेस इन इंडिया

रीस्ट्रक्चरिंग आफ कोर्सेज एट अंडरग्रेजुएटलेवल : वाये एंड हॉउ?

गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया : मैप्स एंड गैप्स

आटोनमस स्कीम इंप्लिमेंटेशन : स्टेट आफ आर्ट

डॉ. एन.वी. वर्गीज

पुस्तकें, प्रकाशन, अनुसंधान लेख और रिपोर्टें

"एजुकेशन प्लानिंग एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल", जे.बी.जी. तिलक की *एजुकेशनल प्लानिंग एट ग्रासरूट्स* में, नई दिल्ली, आशीष पब्लिशिंग, 1992 (अध्याय 5, पृष्ठ 61-80)

"ओमेन एंड वर्क ' एन एक्सामिनेशन आफ फीमेल मैसगीनालांइसेशन थीसिस इन द इंडियन कांटेक्स्ट", ए.एन. शर्मा और एस. सिंग (सं.) *वूमेन एंड वर्क: चैंलिंग स्निारियो इन इंडिया* में, (इंडियन जर्नल आफ लेबर इकानॉमिक्स जिल्द 34) दिल्ली, बी.आर. पब्लिशिंग पृ.सं. 58-70

"इंटर डिस्पिलिनरी एंड एजुकेशनल रिसर्च इन इंडिया", *पर्सपेक्टिक्स इन एजुकेशन,* जिल्द 8, सं. 2,1992

"क्वालिटी आफ प्राइमरी एजुकेशन : एन एंपिरिकल स्टडी", (आर. गोविंद के साथ) *जर्नल आफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन,* जिल्द 6, सं. 1,1992

"डिस्क्रीमिनेट्री प्राइसिंग इन एजुकेशन" (जे.बी.जी. तिलक के साथ), *जर्नल आफ एजुकेशन एंड सोशल चेंज,* जिल्द 6, अंक 1, 1992 पृ.सं. 15-34

"लैनडिंग फार लर्निंग : ए कमेंट्री (समीक्षा लेख), *पर्सपेक्टिक्व इन एजुकेशन,* जिल्द 8, अंक 3-4, 1992, पृ.सं. 233-244

पुस्तक समीक्षाएं

इकानॉमी, प्लानिंग एंड पालिसीज (पी.आर.जी. नायर) *जर्नल आफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन,* जिल्द 6, अंक 1, 1992, पृ. सं. 97-98

सोशल डायमेंशस आफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमैंट इन इंडिया (आई.एल.ओ—ए.आर.टी.इ.पी.), *जर्नल आफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन,* जिल्द 6, अंक 3, पृ. 322-23

क्वालिटी आफ प्राइमरी एजुकेशन : ए स्टडी आफ सलेक्टेड स्कूल्स इन बैगाचाक, मध्य प्रदेश, (आर. गोविंद के साथ), नई दिल्ली, नीपा, 1992 (मिमियोग्राफ)

क्वालिटी आफ प्राइमरी एजुकेशन : ए स्टडी आफ सलेक्टेड स्कूल्स इन रीवा ब्लाक, मध्य प्रदेश (आर. गोविंद के साथ), नई दिल्ली, नीपा, 1992 (मिमियोग्राफ)

क्वालिटी आफ प्राइमरी एजुकेशन : ए स्टडी आफ सलेक्टेड स्कूल्स इन डोंगरगांव ब्लाक, मध्यप्रदेश (आर. गोविंद के साथ), नई दिल्ली नीपा, 1992 (मिमियोग्राफ)

क्वालिटी आफ प्राइमरी एजुकेशन : ए स्टडी आफ सलेक्टेड स्कूल्स इन डाबरा टाउन, मध्य प्रदेश (आर. गोविंद के साथ), नई दिल्ली, नीपा, 1992 (मिमियोग्राफ)

क्वालिटी आफ प्राइमरी एजुकेशन : ए स्टडी आफ सेलेक्टेड स्कूल्स इन इंदौर सिटी, मध्य प्रदेश (आर. गोविंद के साथ), नई दिल्ली, नीपा, 1992 (मिमियोग्राफ)

साक्षरता पर गठित एन.डी.सी. समिति के लिए "फायनेंसिंग एलिमेंट्री एजुकेशन इन द एर्थ फाइव इयर प्लान" पर जे.बी.जी. तिलक के साथ आलेख तैयार किया। नीपा, 1992 (मिमियोग्राफ)

अन्य अकादमिक गतिविधियां

'सबके लिए शिक्षा' विषय पर राष्ट्रीय कार्यशिविर (धूमकुरिया परियोजना), भोपाल, अगस्त 1992

'शिक्षा में व्यक्ति स्तरीय योजना' पर कार्यशिविर, उदंग, पश्चिम बंगाल, 19-22 अक्टूबर 1992

"मानव शक्ति और नई आर्थिक नीति में रोजगारपरक निहितार्थ" विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी (आई.ए.एम.आर, नई दिल्ली 12-13 दिसंबर, 1992)

"निजी प्रयास और सार्वजनिक नीति" विषय पर संगोष्ठी, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली, 12-13 दिसंबर, 1992

विश्वविद्यालय श्रम अर्थव्यवस्था सम्मेलन, ज.ने. विश्वविद्यालय, नई दिल्ली 2-4 जनवरी, 1993

'शिक्षा में जिला स्तरीय योजना विषय पर कार्य शिविर (धूमकुरिया परियोजना) भोपाल, 29-30 जनवरी, 1993

आधारभूत सर्वेक्षण पर कार्यशिविर लखनऊ, 2-3 मार्च, 1993

उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा परियोजना की तैयारी में योगदान अप्रैल 1992

डॉ. एस.सी. नुना

पुस्तकें, प्रकाशन, अनुसंधान लेख और रिपोर्टें

सोर्सबुक ऑन इनवॉयमेटल एजुकेशन फार एलिमेंटरी टीचर एजुकेटर्स (सह संपादन) यूनेस्को (मिमियोग्राफ)

रीजनल डिस्पैरिटीज इन एजुकेशनल डवलपमेंट (सं.), साउथ एशियन पब्लिशर, नई दिल्ली, 1993 पृ. सं. XXVI + 500

डवलपमेंट आफ एजुकेशन इन इंडिया : 1990–1992, नीपा और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली (टायल और जेम्स के साथ) पृ. सं. 54

"इंट्रोडक्टरी ओवरव्यू" एस.सी. नुना (सं.), *रीजनल डिस्पैरिटीज इन एजुकेशनल डवलपमेंट* में, साउथ एशियन पब्लिशर्स, नई दिल्ली पृ. सं. XVII – XXVI.

"प्लानिंग फार मिनीमाइजेशन आफ रीजनल डिस्पैरिटीज इन एजुकेशनल डवलपमेंट, एस.सी. नुना (सं.), *रीजनल डिस्पैरिटीज इन एजुकेशनल डेवलपमेंट,* साउथ एशियन पब्लिशर्स, नई दिल्ली पृ.सं. 55-77

'ट्राइबल एजुकेशन' प्लानिंग इंटरवेंशस इन द कांटेक्स्ट आफ रीजनल डिस्पैरिटीज", एस.सी. नुना (सं.), *रीजनल डिस्पैरिटीज इन एजुकेशनल डवलपमेंट* में, साउथ एशियन पब्लिशर्स, नई दिल्ली, पृ. सं. 207-227

परामर्शकारी और अकादमिक सहयोग

अध्यक्ष, सेंटर फार डवलपमेंटल इनीशिएटिव्स, जी-14, के. ब्लाक, साकेत, नई दिल्ली,

"शिक्षा का भूगोल" पर गठित एन.ए.जी.आई. आयोग के सह-अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश की महिला सामख्या परियोजना के सलाहकार परिषद् में सदस्य

अन्य अकादमिक गतिविधियां

"महिला और विकास के संकेतक" विषय पर रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली में आयोजित कार्यशिविर में संसाधन व्यक्ति (17-18 फरवरी, 1993)

डॉ. के. सुजाता

पुस्तकें, प्रकाशन, अनुसंधान लेख और रिपोर्टें

"टीचर्स इन ट्राइबल सब-प्लान एरिया", *जर्नल आफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन,* जिल्द-VI, अंक 4, अक्तूबर, 1992

अन्य अकादमिक गतिविधियां

धूमकुरिया परियोजना के संबंध में यूनेस्को दल के साथ मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों का दौरा किया।

डॉ. (श्रीमती) सुदेश मुखोपाध्याय

पुस्तकें, प्रकाशन, अनुसंधान लेख और रिपोर्टें

इंबैलेंसेज इन एजुकेशन एंड रिहैविलिटेशन आफ डिसैबुल्ड : द नेशनल स्नारियो" एस.सी. नुना (सं.) *"रीजनल डिस्पैरिटीज इन एजुकेशनल डवलपमेंट"* में साउथ एशियन पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली और नीपा, 1993, पृ. सं. 228-242

" एडेप्टिंग एड्स मैटेरियल फार ट्रेनिंग आफ कम्यूनिटी हेल्थ वर्कर्स", *मीडिया एंड टेक्नॉलाजी,* जनवरी 1993

अन्य अकादमिक गतिविधियां

"शिक्षा और महिला विकास की योजना" पर आयोजित कार्यशिविर में "महिलाओं और विकलांगों की शिक्षा" विषय पर आलेख प्रस्तुत किया। 1992

बंगलूर में एन.ओ.आर.ए.डी. द्वारा प्रायोजित कार्यशिविर में "समुदाय आधारित पुनर्वास के लिए सहायक माध्यम के रूप में क्षेत्र प्रणाली" विषय पर आलेख प्रस्तुत किया, 1992

सी.इ.इ. अहमदाबाद में फरवरी 1993 में 'पर्यावरण शिक्षा के लिए दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के केंद्रिक कार्यक्रम' पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में "अनौपचारिक शिक्षा की योजना और प्रबंध : कुछ केंद्रिक रणनीतियां" विषय पर आलेख प्रस्तुत किया।

सी.इ.इ. अहमदाबाद में फरवरी 1993 में "पर्यावरण क्षेत्र

और अनौपचारिक पर्यावरण शिक्षा के लिए केंद्रिक कार्य" विषय पर आलेख प्रस्तुत किया।

डॉ. (श्रीमती) अंजना मंगलागिरि

पुस्तकें, प्रकाशन अनुसंधान लेख और रिपोर्टें

पुस्तक समीक्षा

स्टोर्मिंग द टावर : ओमेन इन द एकेडमिक वर्ल्ड : एस. लाई और बी.ई. ओलियरी, लंदन, कोगन पेज, 1990, *जर्नल आफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन,* जिल्द VII, अंक 1, जनवरी, 1993

परामर्शकारी और अकादमिक सहायोग

यू.एन.डी.पी. नई दिल्ली के तत्वाधान में दक्षिण उड़ीसा शिक्षा परियोजना के लिए बेसिक शिक्षा पर अध्ययन और क्षेत्र कार्य में परामर्शकारी सेवा

सामाजिक सुरक्षा कवच के तहत "शैक्षिक योजना में लैंगिक मुद्दे" के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों में राष्ट्रीय कार्य दल की सदस्या और उड़ीसा राज्य में कार्यदल की प्रमुख

महिला सामाख्या मानव संसाधन विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय संसाधन दल की सदस्या,

अन्य अकादमिक गतिविधियां

उड़ीसा सरकार और भारत सरकार द्वारा प्रायोजित, यू.एन.डी. पी. तथा जर्मन अधिकरण के तकनीकी सहयोग से भुवनेश्वर में आयोजित कार्यशिविर में *"दक्षिण उड़ीसा शिक्षा परियोजना अध्ययन"* के निष्कर्षो को प्रस्तुत किया। (30 नवंबर-4 दिसंबर 1992)

लोक जुंबिश परिषद, जयपुर में "व्यक्ति स्तरीय योजना और विद्यालय मानचित्रण" पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में संसाधन व्यक्ति (8-10 अक्टूबर 1992).

सामाजिक विकास पर कार्यशाला में संसाधन व्यक्ति, इंडियन सोसायटी फार अपलायड बिहेवरियल साईस, नई दिल्ली, 4 मार्च 1993

साक्षरता गतिविधियों को मजबूती प्रदान करने के लिए अनुसंधान प्रस्तावों के विकास पर दिल्ली साक्षरता समिति द्वारा आयोजित बैठकों में भाग लिया।

सुश्री निर्मल मल्होत्रा

पुस्तकें, प्रकाशन, अनुसंधान लेख और रिपोर्टें

"इन्फोर्मेशंस प्राब्लम्स आफ एजुकेशनिस्ट इन इंडिया" *यूनीवर्सीटी न्यूज,* खंड 30, अंक 8, 17 फरवरी 1992

"इन्फोर्मेशंस सर्विसेज एंड यूसर रिसपोंस", *यूनीवर्सीटी न्यूज,* खंड 31, अंक 2, 11 जनवरी 1993

परामर्श और अकादमिक सहयोग

राज्य शिक्षा संस्थान, चंडीगढ़; डाइट, मोती बाग, विद्योदय, कोचीन; राष्ट्रीय ओपन स्कूल; रा.शै.अ.प्र.प., और डेलनेट को परामर्श व व्यावसायिक सेवाएं प्रदान कीं।

डॉ. अरूण सी. मेहता

पुस्तकें, प्रकाशन, अनुसंधान लेख और रिपोर्टें

"ए नोट आन एजुकेशनल स्टैटिक्स इन इंडिया", जेपा, अंक VII, जनवरी 1993

"डिस्ट्रिक्ट वाईस पापुलेशन प्रोजेक्शंस फार राजस्थान, 1991 सेंसस", *राजस्थान इकॉनामिक जर्नल,* सं. 1, जनवरी 1991 (अगस्त 1992 में प्रकाशित)

यूनेस्को प्रायोजित परियोजना-"शैक्षिक सांख्यिकी में प्रतिदर्श सर्वेक्षण तकनीक का प्रयोग" के एक अध्याय में सह लेखन

1992–93

प्रशिक्षण सामग्री

डायगनॉस्टिक एंड प्लानिंग मॉडल फार इंटिग्रटेड प्लानिंग आफ लिटरेसी एंड यू.पी.इ इन रीजनल वर्कशाप ऑन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट आफ लिटरेसी एंड कंटीन्यूइंग एजुकेशन'', नीपा, नई दिल्ली, 3-14 अगस्त 1992.

भारत में वित्तीय सांख्यिकी के विशेष संदर्भ में शैक्षिक सांख्यिकी पर आयोजित संगोष्ठी में ''भारत में शैक्षिक सांख्यिकी'' विषय पर लेख, नीपा नई दिल्ली, 1-2 फरवरी 1993

'स्टूडेंट फ्लो एस ए बेस टू इनरोलमेंट प्रोजेक्शंस', चीन के अधिकारियों के लिए कार्यक्रम, नीपा, नई दिल्ली

प्रैक्टिकल इक्सरसाइसेज ऑन यूस आफ कंप्यूटर्स इन एजुकेशन (15 अभ्यास), नीपा, नई दिल्ली

'शिक्षा में जनसांख्यिकीय दबाव पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 'इनरोलमेंट प्रोजेक्शंस एंड गोल्स आफ इ.एफ.ए', शीर्षक से एक लेख, नीपा, नई दिल्ली

अन्य अकादमिक गतिविधियां

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद और रीजिना विश्वविद्यालय, कनाडा द्वारा ''विश्वविद्यालयों का संगणकीकरण : भारत-कनाडा परिप्रेक्ष्य'' पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया। (15-17 फरवरी 1993)

हरियाणा में शिक्षा और महिला विकास के विभिन्न संकेतकों के बारे में राज्य/जिला विवरणी को अंतिम रूप से तैयार करने के लिए रा.शै.अ.प्र.प. नई दिल्ली में आयोजित कार्य शिविर में भाग लिया। (17-18 फरवरी 1993)

डॉ. (श्रीमती) रंजना श्रीवास्तव

पुस्तकें, प्रकाशन, अनुसंधान लेख और रिपोर्टें

''स्टेट प्राबलम्स आफ एजुकेशन एंड सैंपलिंग प्रोसीजर'', *सैमपल सर्वे टेकनीक इन एजुकेशनल एटैस्टिक्स,* यूनेस्को (मिमियोग्राफ)

''इलुस्ट्रेटिव डाटा एनालिसीस : गुजरात'' *सैमपल सर्वे टेकनीक इन एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स,* यूनेस्को, (मिमियोग्राफ)

पालिसी स्टडीज इन एजुकेशन, रिप्रेसेंटेशन आफ पब्लिक, मैनेसेरियल एंड टेक्नीकल इंटरेस्ट्स इन पॉलिसी एडाप्शन एंड पॉलिसी एडजुडिकेशन'', एम.एड. पाठ्यक्रम, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक,

''प्रोफेशनल डायनमिक्स-प्लानिंग, एजुकेशन एंड आपरेशनल प्लानिंग एट क्लास रूम एंड इंस्टयूशनल लेवल; यूज आफ टेकनालॉजी इन मैनेजमेंट'', एम.एड. पाठ्यक्रम, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक.

प्रशिक्षण सामग्री

''एजुकेशनल प्लानिंग इन इंडिया'', डिप्लोमा कार्यक्रम, नीपा (मिमियोग्राफ)

एजुकेशनल प्लानिंग प्रासेजेस, नीपा (मिमियो)

एर्थ फाइव इयर प्लान, नीपा (मिमियो)

इफिशंसी इन एजुकेशन, नीपा (मिमियो)

प्लानिंग फार 1990 एंड बियोंड (मिमियो)

डायगनोस्टिक एंड प्रोजेक्शन टैक्नीक : डैमोग्रफिक एनालिसिस, कोहोर्ट एनालिसिस, प्रायर्टीजेशन एंड टारगेट सेटिंग, नीपा (मिमियो)

इंटरनेशनल एक्सपिरियंसेस इन एजुकेशनल प्लानिंग प्रोसेस, नीपा (मिमियो)

इंटरनल इफिशंसी आफ एजुकेशन, नीपा (मिमियो)

डिसपैरीटीज़ इन एजुकेशन, नीपा (मिमियो)

मेसरमैंट आफ इंटरनल इफिशंसी आफ एजुकेशन-ए रिव्यू, नीपा (मिमियो)

परामर्श और अकादमिक सहयोग

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा डिप्लोमा में परामर्श सेवाएं

बी-एड चयन समिति, शिक्षा विभाग, केंद्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय

अन्य अकादमिक गतिविधियां

विश्व बैंक और राजस्थान जन प्रशासन संस्थान द्वारा सामाजिक सैक्टर के लिए परियोजना स्थायित्व पर आयोजित प्रशिक्षकों की कार्यशाला में भाग लिया, जयपुर (28 अप्रैल 8 मई 1992)

रा.शै.अ.प्र.प. में शिक्षा और महिलाओं के विकास के लिए क्षेत्रीय योजना और आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लिया। (7-10 दिसंबर, 1992)

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा डिप्लोमा पाठयक्रम में संसाधन संकाय

डॉ. (श्रीमती) प्रमिला मेनन

प्रशिक्षण सामग्री

प्रारंभिक शिक्षा शिक्षकों के लिए पर्यावरण शिक्षा पर स्रोत पुस्तक में 'मोबीलाइजिंग कम्यूनिटी सपोर्ट फार कनर्सवेशन : पार्टीसिपेशन एंड एजुकेशन''

''सोर्स बुक आन एनवायरमेंटल एजुकेशन फार एलिमेंट्री टीचर एजूकेटर्स'' (सह-सं) यूनेस्को, (मिमियो)

अन्य अकादमिक गतिविधियां

दिल्ली में संपूर्ण साक्षरता अभियान में मूल्यांकन व्यवस्था तैयार करने के लिए राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान और दिल्ली साक्षरता समिति की बैठकों में भाग लिया। (21 अक्तुबर 1992)

महिला समता के लिए शिक्षा के विशेष संदर्भ में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्यवन और संशोधित कार्ययोजना' पर रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लिया। (2-4 दिसंबर 1992)

रा.शै.अ.प्र.प. में 'प्रमुख अधिकारियों के लिए ग्रामीण और दूरवर्ती क्षेत्रों में वंचित समूहों और लड़कियों के लिए प्राइमरी शिक्षा के विकास के लिए नई अग्रगामी परियोजना में प्रशिक्षण सामग्री के विकास के लिए आयोजित कार्यशाला में भाग लिया। (4-5 फरवरी, 1993)

साक्षरता और सतत शिक्षा की योजना और प्रबंध पर यूनेस्को द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय कार्यशाला में भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में भाग लिया, नीपा

डॉ.एस.एम.आई.ए. ज़ैदी

पुस्तकें, प्रकाशन, अनुसंधान आलेख और रिपोर्टें

'प्राब्लमस आफ वेस्टेज इन स्कूल एजुकेशन ड्राप आउटस एट इलिमेंट्री लेवल' *जर्नल आफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन;* जिल्द V, अंक 2, अप्रैल 1991

पुस्तक समीक्षा

'एजुकेशन, रिलीजन एंड माडर्न ऐज (एम.एस.खान द्वारा) *जर्नल आफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन,* जिल्द VI, अंक 3, जुलाई 1992,

'वॉन स्कूल मैनी कल्चर्स (ओ.इ.सी.डी.) *जर्नल आफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन,* खंड VI, अंक 4, अक्तूबर 1992.

प्रशिक्षण सामग्री

'भारत में विकेंद्रीकृत शिक्षा की योजना की पद्धति और सिद्धांत : वर्तमान स्थिति' पर स्वयं अध्ययन आलेख

'प्रतिदर्श सर्वेक्षण की आवश्यकता और विभिन्न सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में प्रतिदर्श सर्वेक्षण तकनीक' (सह लेखक)

अन्य अकादमिक गतिविधियां

विश्वविद्यालयों का कंप्यूट्राइजेशन : इंडो-कनाडा परिप्रेक्ष्य' गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद द्वारा इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित संगोष्ठी में भाग लिया, नई दिल्ली (15-17 फरवरी 1993)

इंदिरागांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के स्नातक छात्रों के लिए पाठ्यक्रम सं.इ.एस.ओ-02 (भारत में समाज) के ब्लाक 4 और 5 के प्रश्न बैंक का विकास, नई दिल्ली

सुश्री.वाई.जोसेफिन

पुस्तकें, प्रकाशन, अनुसंधान आलेख और रिपोर्टें

'क्रिटिकल एनलिसिस आफ फाइनेंशियल पोलिसीज़ इन वूमेन एजुकेशनल डवलपमेंट'', *न्यू फ्रंटियर्स इन एजुकेशन*

परिशिष्ट–I

नीपा परिषद के सदस्य

(31 मार्च 1993)

अध्यक्ष

श्री अर्जुन सिंह, मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली

उपाध्यक्ष

निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

पदेन सदस्य

प्रो. जी. राम. रेड्डी	अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली
श्री एस. वी. गिरि	शिक्षा सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
श्री एस. के .बनर्जी	वित्त सलाहकार, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
श्री ए. आर. बंधोपाध्याय	अतिरिक्त सचिव, जन शिकायत और प्रशासनिक सुधार विभाग, कमरा सं 514, सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली
डॉ. एन. के. सेनगुप्ता	सचिव, योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली
डॉ. के. गोपालन	निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली

शिक्षा सचिव

श्री सी. के. संगतम	शिक्षा सचिव और आयुक्त, शिक्षा विभाग, नागालैंड सरकार, सिविल सचिवालय, कोहिमा-797001
श्री आर. के. श्रीवास्तव	विशेष आयुक्त और सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार पटना-800015
श्री देव स्वरूप	आयुक्त और सचिव, शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002
श्री एम. वी. गार्दे	सचिव (विद्यालय और उच्च शिक्षा) मध्यप्रदेश सरकार, डी-2/13, चार इमली, भोपाल-462004
श्री के. एस. सरमा	सचिव, शिक्षा विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद-500022
श्रीमती एन. सत्यवती	आई.ए.एस., शिक्षा सचिव, शिक्षा विभाग, प्रधान सचिवालय, पांडिचेरी-605001

शिक्षा निदेशक/डी.पी.आई

श्री हरण थांगा	विद्यालय निदेशक (माध्यमिक, प्राथमिक तथा प्रौढ़, मिजोरम) आइज़ोल-790001
श्रीमती गौरी नाग	निदेशक, जन शिक्षा, पश्चिम बंगाल सरकार तथा पदेन सचिव, शिक्षा विभाग, राईटर भवन, कलकत्ता-700001
श्री बी. पी. खंडेलवाल	शिक्षा निदेशक, उत्तरप्रदेश, 18-पार्ट मार्ग, लखनऊ-226001 (कैंप कार्यालय, मुख्यालय–इलाहाबाद)
श्री पी. एस भारद्वाज	निदेशक, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर
श्री के. के. विजयकुमार	निदेशक, जन शिक्षा, जगाथी, त्रिवेंद्रम-695014
श्री जी. डी. शर्मा	शिक्षा निदेशक, लक्षद्वीप (संघशासित प्रदेश) कवारती-682555

विख्यात शिक्षाविद्

डॉ. पी. सी. जोशी	(भूतपूर्व निदेशक, आर्थिक विकास संस्थान) फ्लैट नं. 109 साक्षरा अपार्टमेंट्स, ए-3, पश्चिम बिहार, नई दिल्ली
प्रो. बिपिन चंद्र	ऐतिहासिक अध्ययन केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई महरौली रोड, नई दिल्ली

1992–93

प्रो. प्रभात पटनायक	आर्थिक अध्ययन और योजना केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई महरौली रोड, नई दिल्ली
प्रो. पोरोमेश आचार्य	भारतीय प्रबंध संस्थान, डायमंड हारबर मार्ग, जोका, पोस्ट बाक्स सं. 16757, अलीपुर पोस्ट आफिस, कलकत्ता-700027
प्रो. कृष्णकुमार	शिक्षा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
श्री एम. पी. परमेश्वरन	केरल शास्त्र साहित्य परिषद, तिरूवनंतपुरम, केरल
	नीपा के संकाय सदस्य
डॉ. जी. डी. शर्मा (31 जनवरी 1993 तक)	वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष, उच्च शिक्षा एकक
डॉ. के. जी. विरमानी (1 फरवरी 1993 से)	वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय एकक
डॉ. (श्रीमती) कुसुम के. प्रेमी	अध्येता और अध्यक्ष, शैक्षिक नीति एकक
डॉ. अरुण सी. मेहता	सह अध्येता, शैक्षिक योजना एकक

कार्यकारी समिति के सदस्य (उपरोक्त में शामिल नहीं)

डॉ. आर. वी. वैद्यनाथ अय्यर	संयुक्त सचिव (योजना), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
श्री एम. आर. कोलहाल्कर	सलाहकार (शिक्षा), योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली
डॉ. एल. पी. पांडेय	निदेशक (प्राथमिक शिक्षा), उत्तरप्रदेश सरकार, शिक्षा निदेशालय, निशात गंज, लखनऊ
श्री. डी. ए. पनीरसीवम	निदेशक, रा.शै.अ.प्र.प., 6, आई.टी.आई. परिसर, कालेज मार्ग, मद्रास
श्री बलदेव महाजन	संयुक्त निदेशक, नीपा, नई दिल्ली
	सचिव
कुलसचिव	नीपा, नई दिल्ली

परिशिष्ट–II

कार्यकारी समिति के सदस्य

(31 मार्च 1993)

1. निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और
प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली
अध्यक्ष

2. डॉ. आर. वी. वैद्यनाथ अय्यर
संयुक्त सचिव (योजना)
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन
नई दिल्ली

3. श्री एस. के. बनर्जी
वित्त सलाहाकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
शिक्षा विभाग
शास्त्री भवन
नई दिल्ली

4. श्री एम. आर. कोलहाटकर
सलाहकार (शिक्षा)
योजना आयोग
योजना भवन
नई दिल्ली

5. श्री देव स्वरूप
आयुक्त तथा सचिव (शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार
शिमला-171002

6. श्री एल. पी. पांडेय
निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)
उत्तर प्रदेश सरकार
शिक्षा निदेशालय
निशातगंज
लखनऊ

7. श्री डी. ए. परीनसीवम
निदेशक
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद
6, आई.टी.आई. परिसर
कालेज मार्ग
मद्रास

8. प्रो. कृष्णकुमार
शिक्षा विभाग
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली

9. श्री बलदेव महाजन
संयुक्त निदेशक
नीपा
नई दिल्ली

10. डॉ. जी. डी. शर्मा (31 जनवरी 1993 तक)
वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष
उच्च शिक्षा एकक
नीपा
नई दिल्ली

11. डॉ. के. जी. विरमानी (1 फरवरी 1993 से)
वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष
अंतर्राष्ट्रीय एकक
नीपा
नई दिल्ली

12. डॉ. (श्रीमती) कुसुम के. प्रेमी
अध्येता और अध्यक्ष
शैक्षिक नीति एकक
नीपा, नई दिल्ली

13. कुलसचिव सचिव
नीपा
नई दिल्ली

परिशिष्ट-III

वित्त समिति के सदस्य

(31 मार्च 1993)

1.	निदेशक राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	श्री एस. के. बनर्जी वित्त सलाहार मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग नई दिल्ली	
3.	डॉ. आर. वी. वैद्यनाथ अय्यर संयुक्त सचिव (योजना) मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग नई दिल्ली	
4.	श्री बलदेव महाजन संयुक्त निदेशक नीपा नई दिल्ली	
5.	श्री सी. के. संगतम शिक्षा सचिव सीविल सचिवालय नागालैंड सरकार कोहिमा-797001	
6.	कुलसचिव नीपा	सचिव

परिशिष्ट-IV

योजना और कार्यक्रम समिति के सदस्य

(31 मार्च 1993)

1. निदेशक अध्यक्ष
नीपा
नई दिल्ली

2. श्री बलदेव महाजन
संयुक्त निदेशक
नीपा
नई दिल्ली

3. डॉ. आर. वी. वैद्यनाथ अय्यर
संयुक्त सचिव (योजना)
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
शिक्षा विभाग
शास्त्री भवन
नई दिल्ली

4. श्री एम. आर. कोलहाटकर
सलाहकार (शिक्षा)
योजना आयोग
योजना भवन
नई दिल्ली

5. श्री वाई. एन. चतुर्वेदी
सचिव
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह जफर मार्ग
नई दिल्ली

6. श्रीमती एम. वी. गर्दे
प्रधान सचिव (उच्च शिक्षा)
मध्य प्रदेश सरकार
वल्लभ भवन
भोपाल-462004

7. श्री के. विजयकुमार
सचिव
सामान्य शिक्षा विभाग
केरल सरकार
तिरूवनंतपुरम-650001

8. श्रीमती मंजु गुप्ता
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय
हरियाणा सरकार
30, बे बिल्डिंग, सेक्टर-17
चंडीगढ़-160017

9. श्री सी. ए. देवकर
निदेशक (प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा)
महाराष्ट्र सरकार
17-अंबेडकर रोड
पुणे-411001

10. डॉ. सनत कुमार विश्वास
नाभिकीय वैज्ञानिक
पी-19, पुरानी बालीगंज रोड
कलकत्ता

11. डॉ. सत्यपाल रूहेला
प्रोफेसर (शिक्षा)
उच्च अध्ययन संस्थान (शिक्षा)
जामिया मिल्लिया इस्लामिया
जामिया नगर
नई दिल्ली

12. श्री शकील अहमद
कुलपति
बिहार विश्वविद्यालय
मुज्जफरपुर

13. डॉ. (श्रीमती) गार्गी
भूतपूर्व कुलपति
बुंदेलखंड विश्वविद्यालय
झांसी

14. डॉ. (श्रीमती) आर. डेबी
प्रोफेसर (शिक्षा)
गुवाहाटी विश्वविद्यालय
पोस्ट आफिस, गोपीनाथ बोर्डोलोई नगर
गुवाहाटी-781014 (असम)

15. डॉ. राजेंद्र जैन
अध्यक्ष
अंतर्राष्ट्रीय विधि परिसंघ
शाखा इंदौर
उज्जैन

16. डॉ. के. जी. विरमानी
वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष
अंतर्राष्ट्रीय एकक
नीपा
नई दिल्ली

17. श्री एम. एम. कपूर
वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष
प्रादेशिक प्रणाली एकक
नीपा
नई दिल्ली

1992–93

18. प्रो. श्रीप्रकाश
वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष
शैक्षिक योजना एकक
नीपा
नई दिल्ली

19. डॉ. जी. डी. शर्मा (31 जनवरी 1993 तक)
वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष
उच्च शिक्षा एकक
नीपा
नई दिल्ली

19. डॉ. जया इंदिरेसन (1 फरवरी 1993 से)
वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष
उच्च शिक्षा एकक
नीपा
नई दिल्ली

20. डॉ. जे. बी. जी. तिलक
वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष
शैक्षिक वित्त एकक
नीपा
नई दिल्ली

21. डॉ. कुसुम के. प्रेमी
अध्येता और अध्यक्ष
शैक्षिक नीति एकक
नीपा
नई दिल्ली

22. डा. (श्रीमती) सुषमा भागिया
अध्येता और प्रभारी
विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा एकक
नीपा
नई दिल्ली

23. सुश्री के. सुजाता
अध्येता
शैक्षिक प्रशासन एकक
नीपा
नई दिल्ली

24. कुलसचिव सचिव
नीपा

परिशिष्ट–V

संकाय और प्रशासनिक स्टाफ
(31 मार्च 1993)

बलदेव महाजन, संयुक्त निदेशक

शैक्षिक योजना एकक

श्रीप्रकाश, वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष
अरुण सी. महेता, सह-अध्येता
रंजना श्रीवास्तव, सह-अध्येता
एस.एम.आई.ए.ज़ैदी, सह-अध्येता
प्रभा देवी अग्रवाल, वरिष्ठ तकनीकी सहायक

शैक्षिक प्रशासन एकक

सी. मेहता, अध्येता (अवकाश पर विदेश में)
के. सुजाता, अध्येता
वाई. जोसेफिन, सह-अध्येता
मंजू नरूला, वरिष्ठ तकनीकी सहायक

शैक्षिक वित्त एकक

जे.बी.जी. तिलक, वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष
ए. नरेंद्र रेड्डी, वरिष्ठ तकनीकी सहायक

शैक्षिक नीति एकक

कुसुम. के. प्रेमी, अध्येता और अध्यक्ष
प्रमिला मेनन, सह-अध्येता
नलिनी जुनेजा, सह-अध्येता
एम.मालिक, वारिष्ठ तकनीकी सहायक

विद्यालय और अनौपचारिक शिक्षा एकक

सुषमा भागिया, अध्येता
वाई. पी. अग्रवाल, अध्येता
सुदेश मुखोपाध्याय, अध्येता
रश्मी दीवान, वरिष्ठ तकनीकी सहायक
वी. पी. एस. राजू, वरिष्ठ तकनीकी सहायक

उच्च शिक्षा एकक

जया इंदिरेसन, वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष
के. सुधा राव, अध्येता
कौसर विजारत, वरिष्ठ तकनीकी सहायक

प्रादेशिक प्रणाली एकक

एम. एम. कपूर, अध्येता और अध्यक्ष
आर. एस. शर्मा, अध्येता
एस. सी. नुना, अध्येता
एन. वी. वर्गीस, अध्येता
जयश्री जलाली, सह-अध्येता (अध्ययन अवकाश पर)
कमलकांत बिस्वाल, वरिष्ठ तकनीकी सहायक

अंतर्राष्ट्रीय एकक

के. जी. विरमानी, वरिष्ठ अध्येता और अध्यक्ष
अंजना मंगलागिरि, अध्येता
सुनीता चुग, वरिष्ठ तकनीकी सहायक

पुस्तकालय और प्रलेखन केंद्र

निर्मल मल्होत्रा, पुस्तकाध्यक्ष
एन. डी. कांडपाल, प्रलेखन अधिकारी
दीपक मकोल, व्यावसायिक सहायक

हिंदी कक्ष

एस. बी. राय, हिंदी संपादक

1992–93

प्रकाशन एकक

एम.एम.अजवानी, सहायक प्रकाशन अधिकारी

अकादमिक समर्थन

अरुण सी. मेहता, प्रभारी, इ.डी.पी.आर. एकक (19 अक्तूबर 1992 से)
पी. एन. त्यागी, मानचित्रकार (संगणक अनुप्रयोग)
बी. के. पांडा, वरिष्ठ तकनीकी सहायक (समन्वयन)
योगेश्वर प्रसाद, प्रशिक्षण सहायक

प्रशासन और वित्त

ओ. पी. शर्मा, कार्यवाहक कुलसचिव
जी. एस. भारद्वाज, कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
टी. आर. ध्यानी, अनुभाग अधिकारी
एम. एल. शर्मा, अनुभाग अधिकारी
एस. आर. चौधरी, अनुभाग अधिकारी
पी. मणि, अनुभाग अधिकारी

अनुसंधान परियोजना स्टाफ

परियोजना अध्येता

जे. सी. गोयल
नीलम सिन्हा

परियोजना सह-अध्येता

एम. एम. रहमान
आर. एस. त्यागी
ए. सत्यपती
जी. पी. सिंह
एस. मजूमदार
मो. अंसारी, प्रेाग्राम अधिकारी (प्रोग्राम सिस्टम्स)
रघुराम राव
नियाज खान

परियोजना सहायक

पुष्पा कथूरिया
तरुज्योति बुड़ागोहाई
वासवी सरकार
ए. के सिन्हा
जार्ज मैथ्यू
अंजना सलूजा
मो. जमीर
के. दक्षिण मूर्ति
विनय कुमार
पी. के मिश्रा
एम. एम. जोशी
रोहिणी रमा
सोनिया बत्रा
गुलाम हैदर
विश्वबंधु
जमालुद्दीन फारुकी (परियोजना मानचित्रकार)

परिशिष्ट-VI

वार्षिक लेखा और लेखा परीक्षा रिपोर्ट : 1992-1993

1992–93

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना
वार्षिक लेखा :
1.4.1992 से 31.3.1993 तक की

प्राप्तियां		
अर्थ शेष		
हस्तगत रोकड़ा	10,125.00	
अग्रदाय	1,000.00	
बैंक में रोकड़	7,957,431.40	7,968,556.00
भारत सरकार से प्राप्त सहायता		
योजनेत्तर	9,300,000.00	
योजना	7,300,000.00	16,600,000.00
कार्यालय प्राप्तियां		
लाइसेंस शुल्क	89,763.00	
पानी तथा बिजली बिल	6,892.00	
इ.डी.पी.आर. प्राप्तियां	15,366.00	
फोटोकापी प्राप्तियां	1,19,531.00	
अनुपयोगी वस्तुओं की बिक्री	1,564.00	
अन्य विविध प्राप्तियां	104,919.00	
प्रकाशन रायलटी	10,483.00	
अवकाश वेतन तथा पेंशन	30,527.00	
स्टाफ कार इस्तेमाल करने का शुल्क	1,800.00	

और प्रशासन संस्थान
1992-93
प्राप्तियां और भुगतान लेखा

भुगतान		
संस्थागत व्यय		
वेतन : (योजनेत्तर)		
संकाय	3,674,655.00	
कार्यक्रम निष्पादन सहायता	904,680.00	
सामान्य प्रशासन	1,994,084.00	
वित्त तथा लेखा	371,700.00	
पेंशन और उपदान	665,278.00	
जी.पी.एफ/सी.पी.एफ में		
नियोक्ता के अंशदान पर ब्याज	602,713.00	
यात्रा व्यय	15,024.00	8,228,134.00
स्टाफ प्रशिक्षण		17,000.00
वेतन : (योजना)		
संकाय	441,234.00	
कार्यक्रम निष्पादन सहायता	102,424.00	
सामान्य प्रशासन	73,804.00	
वित्त तथा लेखा	45,618.00	663,080.00
कार्यालय व्यय		
योजनेत्तर	1,667,545.50	
योजना	1,030,726.00	2,698,271.50

प्राप्तियां		
पेंशन कर्त्ता का पूंजीगत मूल्य	270,778.00	
कार्यक्रम प्राप्तियां	105,655.00	757,278.00
छात्रावास किराया		370,013.00
उपहार तथा चंदे के रूप में प्राप्ति (पुस्तकालय के लिए पुस्तकें)		4,285.00
ब्याज		
ब्याज वाली पेशगियों पर ब्याज	99,549.00	
अल्पकालिक जमा राशि पर ब्याज	492,485.00	
जी.पी.एफ/सी.पी.एफ निवेश	157,829.00	
बचत बैंक लेखा पर ब्याज	6,782.40	756,645.40
प्रतिभूति जमा		10,000.00
प्रायोजित कार्यक्रम और अध्ययन		
कार्यक्रम और अध्ययन प्राप्तियां		2,359,220.00

1992–93

भुगतान		
छात्रावास		
आवर्ती व्यय (योजनेतर)	210,146.00	
आवर्ती व्यय (योजना)	125,064.00	
गैर आवर्ती व्यय (योजना)	17,905.00	353,115.00
अकादमिक गतिविधियां (योजनेतर)		
कार्यक्रम व्यय	1,060,304.00	
माइक्रोपोसेसर प्रभार	147,057.00	
फोटोकापी प्रभार	323,497.00	1,530,858.00
अकादमिक गतिविधियां (योजना)		
अनुसंधान अध्ययन		
आवर्ती व्यय	721,452.00	
गैर आवर्ती व्यय	23,400.00	744,852.00
सहायता योजना	31,150.00	
प्रकाशन	176,324.00	
पुस्तकालयपुस्तकें/प्रलेखन	390,995.00	598,469.00
अकादमिक सहायता		
विज्ञापन प्रभार	75,604.00	
लेखन सामग्री प्रभार	304,438.00	
ट्रंक-काल प्रभार	293,341.00	
कार्यक्रम	13,656.00	687,039.00
उपहार तथा दान (पुस्तकें)		4,285.00
फर्नीचर व साज-सामान	342,810.00	
अन्य कार्यालय उपकरण	896,419.00	
टाइपराइटर	11,790.00	
स्टाफ कार	27,416.00	1,278,435.00

प्राप्तियां		
वसूली योग्य पेशगियां		
साइकिल पेशगी	4,470.00	
स्कूटर पेशगी	48,560.00	
त्यौहार पेशगी	37,420.00	
भवन निर्माण पेशगी	144,989.00	
मोटरकार पेशगी	94,458.00	
पंखा पेशगी	800.00	
संगणक पेशगी	51,540.00	382,237.00
एल.आइ.सी.प्राप्तियां		182.00
योग		29,208,416.80

ह.

(ओ.पी. शर्मा)

वित्त अधिकारी

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान

नई दिल्ली

1992–93

भुगतान		
जमा (योजना)		
के,लो.नि.वि.के पास		
जमा (योजना)		646,435.00
यू.डी.राशि का भुगतान		10,125.00
प्रायोजित कार्यक्रम और अध्ययन		
आवर्ती वयय	3,387,140.00	
गैर आवर्ती व्यय	253,564.00	3,640,704.00
वसूली योग्य पेशगियां		
पंखा पेशगी	1,200.00	
मोटर कार पेशगी	65,200.00	
साइकिल पेशगी	4,800.00	
स्कूटर पेशगी	50,560.00	
त्यौहार पेशगी	48,600.00	
भवन निर्माण पेशगी	224,200.00	394,560.00
विविध पेशगी		24,262.00
रोकड़ बाकी		
हस्तगत रोकड़	3,950,000.00	
अग्रदाय	1,000.00	
बैंक में रोकड़	3,737,792.30	7,688,792.30
योग		29,208,416.80

ह.
(बलदेव महाजन)
संयुक्त निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान : नई दिल्ली
रोकड़ बाकी का विवरण (31 मार्च 1993)

शीर्ष	रोकड़ जमा	अनुदान
योजनेतर	849,894.23	9,300,000.00
योजना	1,649,561.53	7,300,000.00
प्रायोजित कार्यक्रम/अनुसंधान अध्ययन	5,458,975.64	2,359,220.00
यू.डी. राशि	10,125.00	0.00
ब्याना	0.00	0.00
राशि वसूली (एस.एल.आई.स्कीम)	0.00	0.00
योग	7,968,556.40	18,959,220.00

ह.
(ओ.पी.शर्मा)
वित्त अधिकारी
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

1992–93

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान : नई दिल्ली
रोकड़ बाकी का विवरण (31 मार्च 1993)

अन्य प्राप्तियां	योग	भुगतान	शेष
2,270,458.40	12,420,352.63	12,072,505.50	347,847.13
0.00	8,949,561.53	5,796,290.00	3,153,271.53
0.00	7,818,195.64	3,640,704.00	4,177,491.64
0.00	10,125.00	10,125.00	0.00
10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
182.00	182.00	0.00	182.00
2,280,640.40	29,208,416.80	21,519,624.50	7,688,792.30

ह.
(बलदेव महाजन)
संयुक्त निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
वर्ष 1992-93 का आय और व्यय लेखा

व्यय	
स्थापना व्यय	8,891,214.00
कार्यालय व्यय	2,698,271.50
स्टाफ प्रशिक्षण	17,000.00
छात्रावास व्यय	335,210.00
अकादमिक गतिविधियां	3,146,823.00
व्यय से अधिक आय	1,683,083.50
योग	16,771,602.00

ह.
(ओ.पी.शर्मा)
वित्त अधिकारी
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

1992–93

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
वर्ष 1992-93 का आय और व्यय लेखा

आय			
सहायता अनुदान	16,600000.00		
सहायता अनुदान को छोड़कर			
कार्यालय वस्तुएं	1,319,740.00		
पुस्तकालयों की पुस्तकें	390,995.00	1,710,735.00	14,889,265.00
कार्यालय प्राप्तियां			757,278.00
छात्रावास किराया	370,013.00		
पिछले साल का घटाकर	920.00	369,093.00	
वर्ष के दौरान उपचय		3,970.00	373,063.00
ब्याज	756,645.40		
पिछले साल का घटाकर	4,649.40		751,996.00
योग			16,771,602.00

ह.
(बलदेव महाजन)
संयुक्त निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान : नई दिल्ली
तुलन पत्र (31 मार्च, 1993)

देयताएं		
पूंजीकृत अनुदान		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष राशि	28,130,857.82	
वर्ष के दौरान बढ़ाई गई राशि	1,710,735.00	
परिवर्धन (समायोजन द्वारा)	3,445,792.77	
पूंजीनिवेश–बट्टेखाते को घटाकर	335,333.00	32,952,052.59
प्रायोजित कार्यक्रम की प्राप्तियां		
पूंजीकृत प्राप्तियां	720,693.00	720,693.00
कोप/एम.आई.एस परियोजना		
के गत वर्ष की शेष राशि	694,455.00	
वर्ष के दौरान बढ़ाई गई राशि	75,417.00	769,872.00
प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनिकरणः		
संचारेक्षण प्रणाली के गत वर्ष की शेष राशि	24,359.00	
वर्ष के दौरान बढ़ाई गई राशि	144,288.00	168,647.00
विश्व बैंक (इटावा परियोजना)		23,400.00
महाविद्यालयों का विकास		
(वि.अ.आयोग द्वारा प्रायोजित)		2,775.00

1992–93

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान : नई दिल्ली
तुलन पत्र (31 मार्च, 1993)

परिसंपत्तियां		
भूमि तथा भवन		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष राशि	17,373,369.78	
परिवर्धन समायोजन द्वारा	3,445,792.77	
वर्ष के दौरान अन्य कारणों से बढ़ी राशि	0.00	20,819,162.55
फर्नीचर तथा अन्य खर्चे, स्टाफ कार, टाइपराइटर तथा कम्पयूटर आदि के खर्चों को शामिल करके		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष राशि	9,581,805.42	
वर्ष के दौरान बढ़ी राशि	1,565,620.00	
वर्ष के दौरान डिस्पोसल को घटाने पर	329,957.00	10,817,468.42
पुस्तकालय की पुस्तकें		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष राशि	2,700,366.93	
वर्ष के दौरान बढ़ी राशि	390,995.00	
उपहार और दान के द्वारा बढ़ोत्तरी	4,285.00	
बट्टे खाते को घटाकर	5,376.00	3,090,270.93
भविष्य निधि निवेश		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष राशि	4,080,000.00	
वर्ष के दौरान बढ़ी राशि	1,120,000.00	
घटाए वर्ष के दौरान निकाली गई राशि	200,000.00	5,000,000.00

देयताएं

व्यय से अधिक आय

पिछले तुलन पत्र के मुताबिक शेष राशि	12,123,007.93	
वर्ष के दौरान बड़ी राशि	1,683,083.50	
परिवर्धन (समायोजन द्वारा)	60,952.00	
वर्ष के दौरान व्यय को घटाकर	3,445,792.77	10,421,250.66

निर्धारित कार्यक्रम तथा अध्ययन

पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष राशि	5,479,662.04	
वर्ष के दौरान बढ़ी राशि	2,359,220.00	
वर्ष के दौरान व्यय को घटाकर	3,640,704.00	4,198,178.04

भविष्य निधि

पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष राशि	4,555,118.00	
वर्ष के दौरान बढ़ी राशि	2,854,414.00	
घटाए वर्ष के दौरान निकाली गई राशि	1,613,048.00	5,796,484.00

उपहार तथा दान

गत वर्ष की शेष राशि	85,177.31	
वर्ष के दौरान बढ़ाई गई राशि	4,285.00	89,462.31

परिसंपत्तियां

जमा		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष राशि	55,990.00	
वर्ष के दौरान बड़ी राशि	0.00	55,990.00
के.लो.नि.वि. के पास जमा		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष राशि	8,495,212.77	
वर्ष के दौरान बड़ी राशि	646,435.00	
वापसी घटाकर	0.00	
समायोजन घटाकर	3,445,792.77	
समायोजन द्वारा अतिरिक्त भुगतान	•60,952.00	5,756,807.00
वसूली योग्य पेशगियां		
मोटर कार पेशगी	334,184.00	
गृह निर्माण पेशगी	445,850.00	
त्यौहार पेशगी	32,640.00	
साइकिल पेशगी	3,590.00	
स्कूटर पेशगी	92,470.00	
कम्पयूटर पेशगी	140,805.00	
पंखा पेशगी	400.00	1,049,939.00
विविध पेशगियां (नीपा)		45,012.00
स्थानांतरण यात्रा व्यय पेशगी		7,000.00
विविध पेशगियां (एन.सी.टी.II)		20,686.40
प्रेषित धन		
जी.एस.एल.आई योजना		
गतवर्ष की शेष राशि	4,914.00	
वर्ष के दौरान बढ़ी राशि	0.00	
वर्ष के दौरान प्राप्ति को घटाकर	182.00	4,732.00

देयताएं

पेशगी		
वर्ष के दौरान प्राप्त राशि		10,000.00
जमा		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष राशि	3,500.00	
वर्ष के दौरान बढ़ी राशि	0.00	
वर्ष के दौरान समाशोधन	0.00	3,500.00
यू.डी.राशि		
वर्ष के दौरान शेष राशि	10,125.00	
वर्ष के दौरान बढ़ी राशि	0.00	
वर्ष के दौरान समाशोधन	10,125.00	0.00
योग		55,156,314.60

ह.
(ओ.पी.शर्मा)
वित्त अधिकारी
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

परिसंपत्तियां		
छात्रावास से प्राप्त आय		
गतवर्ष की शेष राशि	920.00	
वर्ष के दौरान की वसूली	920.00	
वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	3,970.00	3,970.00
भविष्य निधि के स्टेट बैंक		
लेखा से प्राप्त ब्याज		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष राशि	4,649.40	
वर्ष के दौरान बढ़ी राशि	0.00	
वर्ष के दौरान वसूली की घटाकर	4,649.40	0.00
शेष रोकड़		
हस्तगत राशि (चैक)	3,950,000.00	
अग्रदाय	1,000.00	
चालू खाता (सी-4)	3,737,792.30	
पी.एफ.एस.बी खाता (टी-2)	796,484.00	8,485,276.30
जमा		55,156,314.60

ह.
(बलदेव महाजन)
संयुक्त निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थानः नई दिल्ली
31 मार्च 1993 तक के निर्धारित कार्यक्रम/अध्ययन का लेखा प्रपत्र

क्रं. सं.	कार्यक्रम/अध्ययन का नाम	अर्थ शेष (1.4.92 को)	प्राप्तियां	योग	व्यय	शेष
1	2	3	4	5	6	7
1.	राष्ट्रीय शिक्षक आयोग-II I केंद्रीय तकनीकी एकक II आयोग के दौरे का आयोजन	98,832.05	0.00	98,832.05	0.00	98,832.05
2.	अनौपचारिक शिक्षा की प्रयोगात्मक परियोजना मूल्यांकन अध्ययन (शिक्षा मंत्रालय)	24,923.36	0.00	24,923.36	0.00	24,923.36
3.	अनौपचारिक शिक्षा समेत प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा का प्रारंभिक तथा नवाचारी कार्यक्रम (कोप) तथा जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए एम.आई.एस (मा.सं.वि. मंत्रालय)	921,038.30	0.00	921,038.30	483,810.00	437,228.30
4.	शिक्षा तथा रोजगार के बीच लाभकारी संबंधों का अध्ययन (योजना आयोग)	13,372.90	0.00	13,372.90	0.00	13,372.90
5.	मौजूदा सुविधाओं का अधिकाधिक प्रभावी प्रयोग (योजना आयोग)	18,037.00	0.00	18,037.00	0.00	18,037.00

1	2	3	4	5	6	7
6.	शैक्षिक योजना और प्रशासन में अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा	937,397.14	249,087.00	1,186,484.14	308,495.00	877,989.14
7.	उच्च शिक्षा में क्षमता, गुणवत्ता और लागत का अध्ययन (वि.वि.अनुदान आयोग द्वारा प्रायोजित)	20,954.13	0.00	20,954.13	0.00	20,954.13
8.	उच्च शिक्षा में संसाधन आवंटन की प्रविधि पर परियोजना (वि.वि. अनुदान आयोग द्वारा (प्रायोजित)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
9.	कम्पयूटर किराए पर लेकर उसके प्रभावी प्रयोग का अध्ययन (वि.वि. अनुदान आयोग द्वारा प्रायोजित)	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00
10.	विकेंद्रीकरण के उपाय के रूप में व्यष्टि स्तरीय शैक्षिक योजना और प्रबंध	8,944.61	0.00	8,944.61	0.00	8,944.61
11.	पर्यावरण शिक्षा में अंतक्षेत्रीय पाठ्यक्रम (यूनेस्को)	45,360.15	0.00	45,360.15	18,111.00	27,249.15
12.	पर्यावरण शिक्षा पर एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम (यूनेस्को)	153,109.40	0.00	153,109.40	0.00	153,109.40

1	2	3	4	5	6	7
13.	दक्षिण एशियाई देशों के लिए पर्यावरण शिक्षा	(-) 4,423.00	4,423.00	0.00	0.00	0.00
14.	लेखकीय सेविदा : पर्यावरण शिक्षा निर्देशिका (यूनेस्को)	52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
15.	जिला शिक्षा अधिकारियों (प्रौढ़ शिक्षा) का छह सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम	116,419.00	0.00	116,419.00	116,419.00	0.00
16.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पुनरीक्षण समिति	136,203.00	0.00	136,203.00	136,203.00	0.00
17.	शिक्षा में प्रतिदर्श सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग	48,323.00	284,000.00	332,323.00	123,611.00	208,712.00
18.	प्रारंभिक शिक्षा की संचारेक्षण प्रणाली	2,046,614.00	0.00	2,046,614.00	569,724.00	1,476,890.00
19.	उत्तर प्रदेश में सबके लिए शिक्षा (विश्व बैंक योजना) पूर्व परियोजना गतिविधियां (इटावा)	(-) 95,541.00	0.00	(-) 95,541.00	246,430.00	(-) 341,971.00
20.	शैक्षिक प्रौद्योगिकी योजना का मूल्यांकन अध्ययन	634,122.00	0.00	634,122.00	373,337.00	260,785.00

1	2	3	4	5	6	7
21.	प्रतिभाशाली छात्रों के लिए (देहात के) माध्यमिक स्तर पर छात्रवृत्तियों का मूल्यांकन अध्ययन (मा.सं.वि. मंत्रालय)	78,885.00	0.00	78,885.00	18,524.00	60,361.00
22.	विकलांग बच्चों के लिए योजना सुविधाओं संबंधी विषय पर जिला स्तर के शिक्षा अधिकारियों का अभिविन्यास कार्यक्रम (18-20, जून 91)	63,147.00	0.00	63,147.00	63,147.00	0.00
23.	डी.आई.ई.टी. कार्यक्रम	88,470.00	0.00	88,470.00	3,562.00	84,908.00
24.	डाइट का कार्यक्रम (रामस्वरूप शर्मा)	16,082.00	193,000.00	209,082.00	195,787.00	13,295.00
25.	पुस्तकालयाध्यक्षों का डाइट का प्रशिक्षण कार्यक्रम	42,485.00	50,000.00	92,485.00	51,859.00	40,626.00
26.	स्कैप कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में विदेशों से नामित प्रशिक्षार्थियों का कार्यक्रम	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
27.	लोक जुंबिश परियोजना	53,145.00	0.00	53,145.00	1,861.00	51,284.00
28.	सार्क विशेषज्ञों की बैठक	(-) 71,988.00	0.00	(-) 71,988.00	6,828.00	(-) 78,816.00

1	2	3	4	5	6	7
29.	भारत में विश्वविद्यालयों के विकास की प्रवृत्ति (वि.वि. अनुदान आयोग द्वारा प्रायोजित)	0.00	300,000.00	300,000.00	258,870.00	41,130.00
30.	आधारभूत स्तर पर महिलाओं का कल्याण (मा.सं.वि. मंत्रालय)	0.00	162,100.00	162,100.00	16,125.00	145,975.00
31.	शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों में महाविद्यालयों का विकास (वि.वि. अनुदान आयोग द्वारा प्रायोजित)	0.00	200,000.00	200,000.00	118,961.00	81,039.00
32.	क्षेत्रीय कार्यशाला साक्षरता तथा सतत शिक्षा की योजना और प्रबंध (3 अगस्त से 14 अगस्त, 1992)	0.00	140,350.00	140,350.00	140,350.00	0.00
33.	प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा के लिए प्रलेखन ग्रंथ की तैयारी	0.00	113,400.00	113,400.00	113,400.00	0.00
34.	भारत में शिक्षा का विकास	0.00	0.00	0.00	7,262.00	(-) 7,262.00
35.	नीपा में शैक्षिक योजना और प्रबंध पर प्रशिक्षण कार्यक्रम-चीन के वैज्ञानिक तकनीकी संघ के छह सदस्य	0.00	294,000.00	294,000.00	146,070.00	147,930.00

1	2	3	4	5	6	7
36.	उत्तर प्रदेश में शैक्षिक अनुसंधान तथा मूल्यांकन सामर्थ्य का निर्धारण (विश्व बैंक परियोजना-II चरण)	0.00	368,860.00	368,860.00	56,152.00	312,708.00
37.	कार्य योजना के लिए पश्चिम क्षेत्र की बैठक तथा कार्यशाला (20.1.93 से 21.1.93)	0.00	0.00	0.00	13,806.00	(-) 13,806.00
	योग	5,479,662.04	2,359,220.00	7,838,882.04	3,640,704.00	4,198,178.04

ह.
(ओ.पी. शर्मा)
वित्त अधिकारी
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

ह.
(बलदेव महाजन)
संयुक्त निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली
वर्ष 1992-93 के लिए सी.पी.एफ/जी.पी.एफ की प्राप्ति तथा भुगतान लेखा

प्राप्ति		भुगतान		
अर्थ शेष	475,118.00	पेशगियों और निकासी	1,613,048.00	1,613,048.00
अंशदायी तथा पेशगियों		आवर्ती जमा निवेश	1,120,000.00	
की वापसी	2,251,701.00	निकासी को छोड़कर	200,000.00	920,000.00
जी.पी.एफ. पर ब्याज/नियोक्ताओं	602,713.00	अंत शेष		796,484.00
का अंशदान				
योग	3,329,532.00			3,329,532.00

ह.
(ओ.पी.शर्मा)
वित्त अधिकारी)
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

ह.
(बलदेव महाजन)
संयुक्त निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान
नई दिल्ली

लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र

मैंने राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के 31 मार्च 1993 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के आगत और भुगतान लेखा/आय और व्यय लेखा तथा 31 मार्च, 1993 के तुलन पत्र की जांच कर ली है। मैंने सभी अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं तथा संलग्न लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में दी गई अभियुक्तियों के आधार पर अपनी लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरी राय में तथा मेरी जानकारी और मुझे दिए गए स्पष्टीकरण एवं संस्थान की बहियों में दर्शाए गए विवरणों के अनुसार ये लेखे और तुलनपत्र उपयुक्त रूप से तैयार किए गए हैं तथा संस्थान के कार्यकलापों का सही और उचित रूप प्रस्तुत करते हैं।

ह.

महानिदेशक, लेखा परीक्षा

केंद्रीय राजस्व

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक :

लेखा परीक्षा रिपोर्ट
(वर्ष 1992-93 के लिए)

1. **प्रस्तावना**

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (नीपा) पहले शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों के राष्ट्रीय स्टाफ़ कालेज के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना एक स्वायत्त संस्था के रूप में हुई थी और सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत इसे पंजीकृत किया गया था। संस्थान का मुख्य उद्देश्य शैक्षिक योजना और प्रशासन के विविध क्षेत्रों में प्रशिक्षण और अनुसंधान के कार्यों का मार्गदर्शन करना तथा अनुदान तथा सह-अनुसंधान के माध्यम से इन क्षेत्रों के कार्यों में पर्याप्त रूप से विकास करना है।

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 की धारा 20 (1) (कार्य, शक्ति और सेवा शर्तें) के तहत पांच वर्षों (1991-92 से 1995-96) के लिए संस्थान की लेखा परीक्षा सुपुर्द की गई है।

2. संस्थान की वित्तीय व्यवस्था केंद्रीय सरकार व अन्य संस्थानों द्वारा दिए गए अनुदान पर आधारित है। वर्ष 1991-92 और 1992-93 की प्राप्तियां व भुगतान का विश्लेषण नीचे दिया गया है।

प्राप्तियां
(लाख रुपए में)

	विवरण	1991-92	1992-93
1.	रोकड़ा/बैंक का अर्थ शेष	44.69	79.69
2.	सरकार द्वारा अनुदान		
	(अ) योजना	89.97	73.00
	(ब) योजनेत्तर	95.28	93.00
3.	प्रायोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत प्राप्तियां	51.36	23.59
4.	अन्य प्राप्तियां	24.25	22.80
	योग	305.55	292.08

भुगतान
(लाख रुपए में)

	विवरण	1991-92	1992-93
1.	संस्थागत/कार्यालय व्यय	70.32	102.48
2.	अकादमिक कार्यक्रम	35.66	29.63
3.	पूंजीगत व्यय	8.01	17.11
4.	प्रायोजित कार्यक्रम	32.17	36.41
5.	अन्य	79.70	29.56
6.	अंत शेष	79.69	76.89
	योग	305.55	292.08

3. लेखा टिप्पणी

भवन निर्माण पेशगी

भवन निर्माण पेशगी (रु. 4,45,850/-) में 40,400 की वह राशि भी शामिल है जो संस्थान के अधिकारी की दी गई थी। यह अधिकारी दिसंबर 1989 से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है। रकम की वसूली के प्रति आशंका को देखते हुए वसूली की प्रक्रिया को गुप्त रखा गया है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक :

ह/-
महालेखा परीक्षक
केंद्रीय राजस्व

वर्ष 1992-93 की अंकेक्षण रिपोर्ट पर अनुच्छेदवार टिप्पणियां

लेखापरीक्षा	उत्तर
1. प्रस्तावना राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (नीपा) पहले शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों के राष्ट्रीय स्टाफ कालेज के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना एक स्वायत्त संस्था के रूप में हुई थी और सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत इसे पंजीकृत किया गया था। संस्थान का मुख्य उद्देश्य शैक्षिक योजना और प्रशासन के विविध क्षेत्रों में प्रशिक्षण और अनुसंधान के कार्यों का मार्गदर्शन करना तथा अनुदान तथा सह-अनुसंधान के माध्यम से इन क्षेत्रों के कार्यों में पर्याप्त रूप से विकास करना है।	कोई टिप्पणी नहीं
2. लेखा परीक्षा की आवश्यकता वर्ष 1991-92 से 1995-96 के दौरान पांच वर्ष के लिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971 की धारा 20 (1) (कार्य, शक्ति और सेवाशर्तें) के तहत इस संस्थान की लेखा का अंकेक्षण किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं

संस्थान की वित्तीय व्यवस्था मुख्य रूप से केंद्रीय सरकार व अन्य संस्थानों द्वारा दिए गए अनुदान पर आधारित है। वर्ष 1991-92 और 1992-93 की प्राप्तियां व भुगतान का विश्लेषण नीचे दिया गया है:

प्राप्तियां
(लाख रुपए में)

	विवरण	1991-92	1992-93	उत्तर
1.	रोकड़ा/बैंक का अर्थ शेष	44.69	79.69	प्राप्तियों के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं
2.	सरकार द्वारा अनुदान			
	अ. योजना	89.97	73.00	
	ब. योजनेत्तर	95.28	93.00	
3.	प्रायोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत प्राप्तियां	51.36	23.59	
4.	अन्य प्राप्तियां	24.25	22.80	
	योग	305.55	292.08	

भुगतान
(लाख रुपए में)

	विवरण		1991-92	1992-93
1.	संस्थागत/कार्यालय व्यय		70.32	102.48
2.	अकादमिक कार्यक्रम		35.66	29.63
3.	पूंजीकृत व्यय		8.01	17.11
4.	प्रायोजित कार्यक्रम		32.17	36.41
5.	अन्य		79.70	29.56
6.	अंत शेष		79.69	76.89
	योग	272.39	305.55	292.08

4. लेखा टिप्पणी

भवन निर्माण पेशगी

भवन निर्माण पेशगी (रु. 4,45, 850/-) में 40,400 की वह राशि भी शामिल है जो संस्थान के अधिकारी को दी गई थी। यह अधिकारी दिसंबर 1989 से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है। रकम की वसूली के प्रति आशंका व्यक्त नहीं की गई है।

यह अधिकारी दिनांक 1.4.87 से 31.12.89 तक अध्ययन अवकाश पर था। इस अधिकारी ने अभी तक नीपा में कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। यह मसला संस्थान की कार्यकारी और वित्त समिति के सम्मुख रख दी गई है। रकम की वसूली के लिए कानूनी कार्यवाही करने का निर्णय लिया जा चुका है। इस अधिकारी की तब तक पेंशन लाभ नहीं मिलेगा जब तक रकम की वसूली न हो जाए।

LIBRARY & DOCUMENTATION
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-9373
Date.... 5-72.96

नीपा पुस्तकालय का एक दृश्य

संस्थान में डैस्क टाप प्रकाशन का एक दृश्य

सुश्री शैलजा, उपमंत्री, नीपा परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए आती हुईं

कालेज प्राचार्यों के कार्यक्रमों का उद्‌घाटन सत्र